सुविचार
अनुभव पाने के लिए महंगी कीमत चुकानी होती है, लेकिन अनुभव से आप ज्ञान की बातों को सीख सकते हैं।

Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi

Ranchi • Friday, 21 June 2024 • Year : 02 • Issue : 153 • Ranchi Edition • Page : 12 • Price : ₹3 • www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

Shama Sikander
Set The Internet... 12

SHARE

सेंसेक्स	:	77,478.93
निफ्टी	:	23,567.00

SARAFA

सोना	:	6,775
चांदी	:	97.01

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

प्रभावित रहीं जेएपी-आईटी की सेवाएं

RANCHI : झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (जेएपी-आईटी) की सेवाएं गुरुवार को प्रभावित रहीं। इस कारण राज्य के निबंधन कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहा। जेएपी आईटी की ओर से जारी किए गए संदेश में कहा गया कि डाटा सेंटर में कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण सेवाएं प्रभावित हैं। संभव है कि सर्वर के संचालन में आ रही दिक्कतों के कारण ई-केवाईसी का सर्वर भी प्रभावित रहे। तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए जेएपी आईटी की ओर से काम किया जा रहा है। सर्वर के शुरू होने के साथ ही इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा।

6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों की चेक होंगी ईवीएम

NEW DELHI : चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की जांच के आदेश दिए हैं। इनमें हरियाणा- तमिलनाडु की दो-दो सीटें शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक-एक सीटें हैं। 8 सीटों में से भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 सीटों में जीती मिली थी। वहीं, 3 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में गईं। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के 8 आवेदन आए थे। इनमें ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की गई थी। आयोग अब इन 8 सीटों की 92 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम की जांच करेगा। इसके अलावा आयोग ने आंध्रप्रदेश और ओडिशा की 3 विधानसभा सीटों के ईवीएम के जांच के आदेश दिए हैं। आयोग यहां के 26 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम में गड़बड़ी की जांच करेगा।

तमिलनाडु में जहरीली शराब से अब तक 35 की मौत

KALLAKURICHI : तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें पांच महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल 15 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जहरीली शराब त्रासदी की गाज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पर गिरी है। तमिलनाडु सरकार ने जिलाधिकारी श्रवण कुमार जातावथ का तबादला और पुलिस अधीक्षक समय सिंह मीणा को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट जारी कर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है, कल्लाकुरिची में मिलावटी शराब पीने से लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी हूं। सीबी-सीआईडी जांच: मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस घटना की सीबी-सीआईडी जांच का आदेश दिया है।

योग दिवस आज, श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी

AGENCY SRINAGAR : 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। इसके एक दिन पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे। शुक्रवार को वह योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर के पहले दौरे पर यहां पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है क्योंकि सबको बांटने वाली अनुच्छेद 370 की दीवार अब गिर चुकी है। यहां शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने यह बात कही। मोदी ने कहा, "जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और यह सबकुछ हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली अनुच्छेद 370 की दीवार अब गिर चुकी है।" कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 1,500 करोड़ रुपये की 84 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया।

बोले- जम्मू-कश्मीर में अब गिर चुकी है अनुच्छेद 370 की दीवार

2000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र

प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए 2000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मोदी ने लोकसभा चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश में रिकॉर्ड मतदान का उल्लेख करते हुए कहा, जम्मू-कश्मीर के युवाओं ने इस लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित की है।

योगाभ्यास करते छात्र व छात्राएं।

स्थिर सरकार के नए दौर में भारत

मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भारत अब स्थिर सरकार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है और इस लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर की आवाम की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने इस चुनाव में जम्हूरियत को जिताया है आपने पिछले 35-40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है।

रांची में अंतराष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व सैकड़ों बच्चों ने किया योगाभ्यास

RANCHI : भाजयुमो कला और खेल प्रकोष्ठ रांची महानगर एवं रिलेशंस की ओर से गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व संध्या पर बरियातू रोड स्थित डांस वांस में सैंकड़ो बच्चों ने एक साथ योगाभ्यास किया।मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डांस वांस नृत्य संस्थान के निदेशक शिवम् मनोहरण और भाजयुमो कला और खेल प्रकोष्ठ रांची महानगर के संयोजक आशुतोष द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।योग प्रशिक्षक सन्नी और प्राची ने सभी बच्चों को योग सिखाया। इस दौरान बच्चों को प्राणायाम, आसन एवं सूर्य नमस्कार का योगाभ्यास कराया। मुख्य अतिथि शिवम् मनोहरण और आशुतोष द्विवेदी ने संयुक्त रूप से कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल से 21 जून को अंतराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।

आधे घंटे की झमाझम बारिश से राजधानी रांची में हुआ जल-जमाव।

आईएमडी ने दी चेतावनी और शाम होते ही शुरू हो गई झमाझम बारिश

PHOTON NEWS RANCHI : गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची के लिए मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। शाम लगभग 6:00 बजे के आसपास अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और झमाझम बारिश शुरू हो गई। लगभग आधे घंटे तक जमकर बारिश हुई। दोपहर के बाद बोकारो, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची, सिमडेगा और पलामू में जमकर बारिश हुई। रांची में हिनू सबसे ज्यादा गर्म जगह रहा, जबकि बारिश भी यहीं सबसे ज्यादा हुई। रांची के हिनू में 39.4 मिलीमीटर वर्षा पिछले दिन रिकॉर्ड की गई। टाटीसिल्वे में 12 मिलीमीटर वर्षा हुई जबकि नामकुम में 28 मिलीमीटर वर्षापात हुआ। मौसम केंद्र के मुताबिक, हिनू का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री रहा, जबकि टाटीसिल्वे का 37.4 डिग्री और नामकुम का 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के रांची स्थित मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी किया था। इसमें कहा गया है कि अगले 2 से 3 घंटे में गरज के साथ वज्रपात एवं वर्षा होने की प्रबल संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 4.1 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। एक दिन में अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड की मामूली वृद्धि हुई थी। रांची के न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट आई है। 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड गिरने के बाद राजधानी का न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है।

- रांची, बोकारो, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, सिमडेगा और पलामू में हुई जमकर बरसा पानी
- वर्षा के बाद सुहाना हो गया झारखंड में मौसम
- हीट वेव से राहत, सभी जिलों का पारा 40 डिग्री से रहा नीचे
- न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री तक दर्ज की गई गिरावट

शहरों का तापमान

शहर	उच्चतम	न्यूनतम
रांची	33.4	21.6
जमशेदपुर	35.7	27.7
डालटनगंज	37.8	25.5
बोकारो	36.1	26.6
चाईबासा	38	23.6
देवघर	35.3	26.1
गढ़वा	37.7	26.1
सरायकेला	37.2	26.7
गोड्डा	38.7	28.0

पीएम मोदी पर कसा तंज, नीट यूजी परीक्षा पर कब करेंगे चर्चा

नेट एग्जाम कैंसिल, खड़गे ने पूछा- कब रद्द होगी नीट परीक्षा

AGENCY NEW DELHI : 18 जून को पूरे देश में यूजीसी-नेट परीक्षा हुई थी और 19 जून को ही इसे रद्द कर दिया गया। मामले को लेकर शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि प्रथम दृष्टया में जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार, यूजीसी-नेट में गड़बड़ी की गई है। परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूजीसी-नेट के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली थी। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे रद्द करने का फैसला लिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अपने एक्स हैंडल पर आगे लिखा, यूजीसी परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्र-छात्राओं के जज्बे की जीत है। ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का कुत्सित प्रयास किया।

केंद्र व एनटीए को 'सुप्रीम' नोटिस

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए), केंद्र और अन्य से जवाब मांगा। वैसे छात्र जो मेघालय केंद्र में नीट-यूजी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे और कथित तौर पर उनको 45 मिनट कम मिले थे, उन्होंने प्रार्थना की थी कि उन्हें उन 1563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और जिन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को तय की है। उधर, एनएसयूआई (भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन) ने नीट और यूजीसी-नेट के मुद्दे पर दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

मनोवैज्ञानिक रूप से टूट चुके हैं प्रधानमंत्री : राहुल गांधी

नीट यूजी परीक्षा और यूजीसी नेट परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर कांग्रेस नरेंद्र मोदी नीत एनडीए सरकार पर लगातार हमले कर रही है। इस बीच पार्टी सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी को घेरा और कहा- प्रधानमंत्री पेपर लीक को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि नीट पेपर और यूजीसी-नीट के पेपर लीक हुए। हर परीक्षा में धांधली हो रही है। पेपर लीक मुद्दे को इंडिया गठबंधन संसद में उठेगा। मनोवैज्ञानिक रूप से प्रधानमंत्री टूट चुके हैं। सरकार चलाने के लिए संघर्ष करेंगे। पेपर लीक होने का नुकसान लाखों छात्रों को उठाना पड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि पेपर लीक मामले में जो भी शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

बिहार के उपमुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव को लपेटा

गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नीट पेपर विवाद में बड़ा खुलासा आते हुए पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को भी लपेटा है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में बिहार में उभर कर आए मामले साफ बता रहे हैं कि इसमें तेजस्वी यादव के नजदीकी लोगों का हाथ हैं। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने डॉक्यूमेंट भी दिखाया। उन्होंने एक पन्ने को दिखाया और कहा कि ये कॉल डिटेल है। दोनों दिन का कॉल डिटेल इसमें है। अब देखना है कि मामले को लेकर सत्ता पक्ष के द्वारा उठाए गए सवाल का विपक्ष क्या जवाब देता है।

हाईकोर्ट में याचिका खारिज, कल से एग्जाम

झारखंड में जेपीएससी परीक्षा का रास्ता साफ

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को 11वीं जेपीएससी परीक्षा पीटी के मॉडल आंसर को चुनौती देने वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद जेपीएससी की दलील को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी। 22 जून से 11वीं जेपीएससी की परीक्षा शुरू हो रही है। ऐसे में अब इस परीक्षा का रास्ता साफ हो गया। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ एस एन पाठक की कोर्ट में हुई। इस मामले में प्रियंका

अनुज, जया कुमारी, सिद्धार्थ सौरभ सहित पांच छात्रों ने याचिका दाखिल की थी। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने कोर्ट को बताया कि पीटी परीक्षा के बाद जेपीएससी ने 11वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का मॉडल आंसर प्रकाशित किया था।

पूर्व तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन की बालकनी से गिरने के कारण मौत

BENGALURU : : शुक्रवार को पूर्व तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन की अपने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल की बालकनी से गिरने के कारण मौत हो गई और यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या यह आत्महत्या का मामला है। पुलिस ने यह जानकारी दी। कर्नाटक पुलिस ने बयान में कहा,ह्यह्यलगता है कि 52 वर्षीय डेविड जूड जॉनसन कोथनूर के कनक श्री लेआउट में अपने अपार्टमेंट से गिर गए। कोथनूर पुलिस स्टेशन में यूडीआर दर्ज की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। जॉनसन को पिछले सप्ताह पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद सेंट फिलोमेना अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से झटका, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

बिहार में आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला रद्द

AGENCY PATNA : गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले को रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी , ओबीसी और ईबीसी को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की बेंच ने गौरव कुमार और अन्य की याचिकाओं पर 11 मार्च को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इधर, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि रिजर्वेशन इन कैटेगरी की आबादी की बजाय इनके सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए।

75 फीसद हुआ था आरक्षण का दायरा

जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण 65 फीसदी कर दिया था। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को बिहार में सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर कोटा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक कर दिया गया था। बिहार सरकार ने जातीय गणना की रिपोर्ट 2 अक्टूबर को जारी की थी। इसके मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 27.12 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग और 36 प्रतिशत आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। दोनों को जोड़ दें तो इनकी संख्या 63 प्रतिशत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी कि सरकार बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी। 50 फीसदी से इसे 65 या उसके ऊपर ले जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक

किसानों की कर्जमाफी के लिए बैंकों से करेंगे बात : सीएम

PHOTON NEWS RANCHI : मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं हैं। इन योजनाओं का लाभ अन्नदाताओं को मिले, इसे निश्चित तौर पर सुनिश्चित करें, क्योंकि किसानों की समृद्धि से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रगति से जुड़ी जानकारी से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत दो लाख रुपये तक का ऋण माफ करने की योजना है। इससे पहले किसानों के 50 हजार रुपये तक का लोन माफ किया गया था। ऐसे में जिन किसानों का कृषि ऋण बकाया है, उनके एनपीए माफी के लिए बैंकों से बातचीत करें, ताकि सरकार की इस योजना का ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिल सके। इसके साथ मृतक लाभुकों का सही तरीके से सत्यापन करने के बाद ऋण माफी की राशि का भुगतान किया जाए।

- किसानों की समृद्धि से राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
- राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जलस्तर का आकलन के बाद करें बोरिंग

योजनाओं के क्रियान्वयन में टाइम लाइन का रखें ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कार्यों में टाइम फैक्टर काफी मायने रखता है। ऐसे में किसानों के बीच समय पर खाद - बीज का वितरण करने के साथ अन्य कृषि से जुड़ी सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे इसका पूरा सदुपयोग कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अलग-अलग क्षेत्र में जल स्तर में काफी भिन्नताएं हैं। किसी इलाके में ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे है तो कहीं यह थोड़ा ऊपर है। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में बोरिंग वहां के भूमिगत जल स्तर को देखते हुए किया जाना चाहिए , ताकि यह असफल साबित नहीं हो। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश कृषि समृद्धि योजना की समीक्षा के क्रम में अधिकारियों को दिया। इस योजना के तहत किसानों के बीच पंप सेट वितरित किया जाना है।

किसानों और कृषक संगठन और समूह से करें संवाद

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाएं तभी सफल होंगी, जब किसानों को उसका पूरा लाभ मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे योजनाओं को लेकर किसानों, कृषक समूहों और कृषक संगठनों से संवाद करें। उनसे उनकी समस्याओं की जानकारी लें। अगर सरकार की किसी योजना में कोई त्रुटि है तो उसे जानने का प्रयास करें, ताकि समय पर उन त्रुटियों को दूर कर किसानों तक उसका लाभ पहुंचाया जा सके।

नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर

RANCHI : घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को तेजी रही। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 141 अंक चढ़कर नए शिखर पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार बढ़त में रहा। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स में लगातार छठे कारोबारी सत्र में तेजी रही और यह 141.34 अंक यानी 0.18 फीसदी की बढ़त के साथ नई ऊंचाई 77,478.93 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 305.5 अंक चढ़कर 77,643.09 अंक तक चला गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 51 अंक यानी 0.22 फीसदी की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 23,567 अंक पर बंद हुआ।

बेल पर अपील के लिए ईडी ने मांगा समय

सीएम केजरीवाल को शराब नीति केस में मिली जमानत

AGENCY NEW DELHI : गुरुवार रात 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। वे शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं। उधर, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने जमानत के खिलाफ अपील के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। कोर्ट ने कहा कि ये दलीलें ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं। इससे पहले ईडी ने कोर्ट में कहा था कि जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाया जाए, लेकिन वेकेशन बेंच ने इससे इनकार कर दिया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, 'सत्यमेव जयते।'

कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 1 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरने को कहा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया था। जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुबह सुनवाई हुई।

BRIEF NEWS

दो वाहनों से 75 गेलन स्प्रीट जब्त, दो गिरफ्तार

GIRIDIH : अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार की कार्रवाई करते हुए स्प्रिट लोडेड दो वाहन को जब्त किया है । इस बाब उत्पाद अवर निरीक्षक कुमार महेंद्र देवगम ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक के निदेर्शानुसार यह कार्रवाई की गयी है । उन्होंने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि हजारीबाग जिले के बरही से कच्चा स्प्रिट लाकर गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले में सप्लाई किया जा रहा है ।सूचना पर जीटी रोड में टीम ने दो संदिग्ध वाहनों को रोक कर तलाशी लिया गया तो 40 लीटर का 75 गेलन स्प्रिट दोनों वाहनों से जब्त किया गया । इस दौरान चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है । इस धंधे में संलिप्त लोगों के बारे में छानबीन की जा रही है।

हजारीबाग पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष

HAZARIBAGH : विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो झामुमो के मीडिया सेल सदस्य एवं नगर संयोजक मंडली सदस्य सरफराज अहमद के घर गुरुवार को अपने हजारीबाग प्रवास के दौरान पहुंचे। उनके स्वागत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई कार्यकर्ता और उनके परिवार के लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को बुके देकर स्वागत किया। वहीं मीडिया से रूबरू हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री महतो ने बेबाकी से उनके कई सवालों का उत्तर दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया की सूचना पर ही अधिकारियों को फोन कर तुरंत कार्रवाई का निर्देश भी दिया।

मुख्यमंत्री से मिले विधायक प्रदीप यादव

RANCHI : मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन से गुरुवार झारखंड मंत्रालय में राज्य के दर्जा प्राप्त मंत्री-सह-राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद महतो एवं विधायक प्रदीप यादव ने मुलाकात की। इस अवसर पर संयुक्त रूप से इन्होंने झारखंड सरकार द्वारा 19 जून 2024 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के भीतर जाति आधारित जनगणना कराए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दिए जाने के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री को बधाई दी तथा उनके प्रति आभार व्यक्त किया

गुजरात की महिला ने पंडरा में की आत्महत्या

RANCHI : राजधानी रांची के पंडरा इलाके में गुजरात की एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। बताया जाता है कि गुजरात की महिला शादी कर देवी मंडप रोड में रह रही थी। मृतका पिछले साल दिसंबर माह में शादी की थी, उसका नाम पूजा है। इस मामले की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है। जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन रांची पहुंच रहे हैं।

नए आपराधिक कानून पर मास्टर ट्रेनर को मिला प्रशिक्षण

RANCHI : नए आपराधिक कानून को लेकर 163 मास्टर ट्रेनर को ई-एसएकेएचवाईए एप का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण गुरूवार को अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय होटवार में दिया गया। इसमें झारखंड पुलिस की पूर्व से चयनित 163 मास्टर ट्रेनरों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का संचालन राज्य सूचना विभाग पदाधिकारी एनआईसी झारखंड की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में एडीजी आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण सुमन गुप्ता सहित गृह विभागकी ओर से गठित कमेटी के सभी सदस्य शामिल थे।

एक घर की आलमारी से 80 गोलियां बरामद

DHANBAD : धनबाद के सरायढ़ेला थाना पुलिस ने एक घर से 80 गोली बरामद किया है। अनन्या अपार्टमेंट में एक महिला के साथ पति द्वारा मारपीट की सूचना पर पहुंची थी। इसी क्रम में आलमारी में एक बैग से गोली बरामद किया। पुलिस मौके पर ही आरोपी राहुल कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मूलरुप से बिहार के पटना जिले के शालिमपुर थाना क्षेत्र स्थित रुपस मरवाही के रहने वाले आरोपी राहुल कुमार सिंह वर्तमान में धनबाद जिले के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित अनन्या अपार्टमेंट फ्लैट नं-402 में रहता है।

एक योजना संबंधी भुगतान के बदले मांगी गई थी रिश्वत

एसीबी ने 5 हजार रुपये घूस लेते पंचायत सेवक को किया अरेस्ट

PHOTON NEWS LATEHAR : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की पलामू प्रमंडलीय टीम ने लातेहार जिले के बालुमाथ प्रखंड के एक पंचायत सेवक को 5 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। उसका नाम अर्जुन राम है। एसीबी की टीम ने अर्जुन राम को भुगतान कराने के एवज में 5 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी की पलामू टीम ने यह जानकारी दी है। टीम की ओर से बताया गया है कि आवेदक ने पंचायत सेवक अर्जुन राम पर एक योजना के भुगतान के बदले में रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया। योजना के लाभुक ने कहा सेरेगढ़ा पंचायत की योजना संख्या 57975265 के भुगतान के एवज में 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। आवेदक को इस योजना संख्या के तहत ईंट सोंलिंग का कार्य आवंटित किया गया था। कार्य पूर्ण होने के बाद उसने पंचायत सेवक को भुगतान कराने के लिए कहा था। इसके एवज में पंचायत सेवक ने घूस की मांग की थी। इस संबंध में एसीबी के पलामू थाना में कांड संख्या 05/2024 भादवि की धारा 7(ए) पीसी (अमेंडमेंट) एक्ट 2018 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। उसे गिरफ्तार कर पलामू लाया गया है। उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

पुलिस गिरफ्त में पंचायत सेवक अर्जुन राम। ● फोटोन न्यूज

अर्जुन राम को पकड़ने के लिए बिछाया ट्रैप

पंचायत सचिव ने बिना रिश्वत जब भुगतान की व्यवस्था नहीं की, तो लाभुक ने इसकी शिकायत एसीबी की पलामू टीम से की। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने शिकायत की जांच की। जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद एसीबी ने एक ट्रैप बिछाया और पंचायत सेवक अर्जुन राम को 5 हजार रुपये के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

'आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मैं प्रयासरत रहूंगी'

कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी को गुलदस्ता देकर स्वागत करते लोग।

PHOTON NEWS HAZARIBAGH : कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली दफा गुरुवार को रांची से कोडरमा लौटने के क्रम में, केंद्रीय महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भाजपाइयों ने बाजे-गाजे के साथ स्वागत किया। इसी कड़ी में हजारीबाग पहुंचने पर पुराना बस स्टैंड के पास हजारीबाग जिला के पार्टी कार्यकताओं ने फूल-माल व बुके देकर स्वागत किया । केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पुराना बस स्टैंड के समीप बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इन्होंने कहा कि जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मैं लगातार प्रयासरत रहूंगी। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के मंत्री होने से निश्चित रूप से हजारीबाग-रामगढ़ जिले का विकास होगा । पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने कहा की कोडरमा और बरही विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल सटा हुआ है।

बरहरवा में 9 साल की बच्ची की हत्या परिजनों ने जताई दुष्कर्म की आशंका

PHOTON NEWS SAHIBGANJ : साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना क्षेत्र के ग्रामसीर में 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची की हत्या कर शव को एक निमाणार्धीन भवन में फेंके जाने का मामला प्रकाश में आया है। नाबालिग के परिजनों ने दुष्कर्म की भी आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार, नाबालिग की मां बाजार करने के लिए बुधवार की शाम करीब 4 बजे घर से निकली थी। बजार से लौटने के बाद देखा कि उनकी 9 साल की बच्ची घर में नहीं है। आसपास में काफी खोजीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। उसके माता-पिता और परिजन रात भर परेशान रहे। गुरुवार को सुबह होते ही घर से कुछ दूरी पर एक निमाणार्धीन मकान के कमरे में बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली। बच्ची की मां एवं अन्य लोग वहां पहुंचे, तो देखा कि उनकी बच्ची के शरीर पर कई जगह नाखून के निशान हैं। बच्ची के मुंह में तंबाकू डाल दिया गया है। कमर से नीचे कई जगह खून के निशान हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी बरहरवा थाना पुलिस को दी। बरहरवा थाना के इंस्पेक्टर सुधीर कुमार पोद्दार, रांगा थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह, बरहरवा थाना के एसआई अमित कच्छप, आरपी यादव, कबिन्द्र मिश्रा सहित अन्य घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। इधर, पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए साहिबगंज एसपी कुमार गौरव ने जांच के लिए राजमहल के एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी को भेजा। एसडीपीओ भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। नाबालिग की मां ने आशंका जतायई है कि दुष्कर्म के बाद उनकी बेटी की हत्या की गई है। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। इस सनसनीखेज मामले की पुलिस ने गंभीरता से छानबीन शुरू कर दी है। हर बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। इंस्पेक्टर सुधीर कुमार पोद्दार ने कहा कि पुलिस जल्दी ही मामले का उद्भेदन करेगी। नबालिग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्ची की मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा।

घटनास्थल पर जांच करती पुलिस। ● फोटोन न्यूज

कोर्ट परिसर में बाइक चोरी करते युवक धराया

DUMKA : जिले में वाहन चोरी का सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों ने अब सबसे सुरक्षित जगह माने जाने वाले कोर्ट परिसर को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को कोर्ट परिसर से रामगढ़ के एक व्यक्ति की बाइक चोरी कर भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ लिया। जमकर पिटाई करने के बाद उसे नगर थाना के सुपुर्द कर दिया। अब पुलिस उससे चोरी हुई अन्य बाइक के बारे में जानने का प्रयास कर रही है। रामगढ़ प्रखंड के सिमरा गांव का संतोष मंडल कोर्ट के काम से व्यवहार न्यायालय आया था। उसने अपनी बाइक पुराने एसी कार्यालय के सामने खड़ी की। वहां पर पहले से करीब दो दर्जन बाइक लगी हुई थी। करीब 12 बजे एक युवक संतोष की बाइक लेकर चला। इसी बीच संतोष भी काम समाप्त कर बाइक की ओर जाने लगा तो देखा कि एक युवक उसकी बाइक को ढकेलकर ले जा रहा है। उसने शोर मचाया तो युवक बाइक छोड़कर भागने लगा। परिसर में मौजूद लोगों ने अधिवक्ताओं की मदद से उसे धर दबोचा।

ग्रामीण डॉक्टर के बेटे के अपहरण मामले में छह अपराधी गिरफ्तार

PHOTON NEWS GIRIDIH : जिले के देवरी थाना क्षेत्र के चतरो गांव निवासी ग्रामीण चिकित्सक डॉ लक्ष्मण दास के पुत्र पवन दास के अपहरणकांड में शामिल छह अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया है, उनमें इस गिरोह का सरगना देवरी थाना क्षेत्र के कोसोंगोदोदिघी गांव निवासी संजय पासवान भी शामिल है। अन्य पांचों में संजय राम, महेश कुमार वर्मा, सद्दाम अंसारी, राजकुमार वर्मा और मो मुजफ्फर शामिलहैं। इन सभी आरोपितों के पास से पुलिस ने एक लोडेड देसी पिस्टल के साथ तीन कारतूस, अपहरण में इस्तेमाल की गई कार, अपहृत युवक पवन कुमार दास की बाइक के साथ कुल चार बाइक, छह मोबाइल फोन सेट बरामद किए हैं। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने गुरुवार पत्रकारों को जानकारी दी। एसपी ने बताया कि 13 जून 2024 को देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चतरो निवासी डॉ लक्ष्मण दास के पुत्र पवन दास का अपहरण कर लिया गया था। वह उस वक्त अपनी दुकान से घर लौट रहे थे। डॉ लक्ष्मण दास की लिखित शिकायत पर देवरी थाना में 13 जून 2024 को कांड सं-40/24 दर्ज किया गया। इसके बाद एसडीपीओ खोरीमहुआ नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गुप्त सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस टीम ने तेजी से काम करते हुए 12 घंटे के भीतर अपहृत पवन कुमार दास को मोटरसाईकिल सहित बिरनी के पेशम जंगल से सकुशल बरामद कर लिया। अपहरण में इस्तेमाल की गई कार भी पुलिस ने बरामद कर ली। इसके बाद अनुसंधान के क्रम में लगातार छापेमारी कर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से घटना में लिप्त सभी अपराधकर्मियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार सभी आरोपितों ने अपहरण में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। अभियुक्तों के निशानदेही पर ही घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किए गए। रेकी के लिए इस्तेमाल की गई तीन बाइक भी बरामद किए गए।

गिरफ्तार अपराधियों के बारे में जानकारी देती पुलिस। ● फोटोन न्यूज

मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव पर छात्रों ने लिखे निबंध

PHOTON NEWS LATEHAR : मादक पदार्थों के दुरुपयोग को समाप्त करने तथा इसके विरूद्ध जागरूकता के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 19 जून से लेकर 26 जून तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला खेल कार्यालय की ओर से गुरुवार को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में निबंध लेखन प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें छात्र-छात्राओं ने मादक पदार्थों का सेवन करने वालों लोगों के अंदर कुप्रभाव, कैंसर जैसे रोग इत्यादि पर निबंध लिखा। कार्यक्रम में निगा कुमारी, गरिमा रॉय, कल्पना कुमारी, राम स्वरूप सिंह, प्रिंस गुप्ता, पंकज सिंह, मिक्कू कुमार, संगम उरांव, मोहित कुमार, चांदनी कुमारी समेत अन्य का निबंध लेखन सराहनीय रहा। वहीं, विधालय की प्रधानाध्यापिका तृप्ति भारती, शिक्षक संतोष पासवान, समीर टोप्पो, उदय कुमार का सहयोग सराहनीय रहा। इस दौरान खेल विभाग के प्रशिक्षक योगेश यादव, प्रवीण मिश्रा, खेल समन्वयक लखेश्वर मंडल आदि सक्रिय रहे।

अबुआ आवास योजना के पहले चरण की राशि अविलंब करें जारी : डीसी

PHOTON NEWS HAZARIBAGH : ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक गुरुवार को समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त नैंसी सहाय की अध्यक्षता में की गई। समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रेरणा दीक्षित मौजूद रहीं। बैठक की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारीयों को कहा कि अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत किए गए आवास निर्माण को पहली किस्त की राशि अविलंब जारी करें। उन्होंने आवास निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लाभुकों की चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाये। जिन्हें अबुआ आवास आवंटित हो चुका है और उनके पहला चरण का कार्य संतोषजनक है,तो उन्हें दूसरी किस्त की राशि जारी करें। सरकार की प्राथमिकता वाले योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोर कसर न रखें। योग्य लाभुकों को अबुआ आवास योजना का लाभ मिले यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कम प्रगति वाले प्रखंडों से जवाब तलब कर जल्द से जल्द प्रथम व द्वितीय किश्त की राशि हस्तानांतरित करने का निर्देश दिया। अबूआ आवास में ग्रामीणों द्वारा पीलिंथ तक के कार्यों की जीओ टैग फोटोग्राफ व डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया।

समीक्षा बैठक में दिशा-निर्देश देतीं उपायुक्त नैंसी सहाय व अन्य। ● फोटोन न्यूज

सांसद ने समस्याओं के समाधान का दिया निर्देश

PHOTON NEWS HAZARIBAGH : सांसद मनीष जायसवाल जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक्टिव और एक्शन मोड में नजर आये। गुरुवार को सांसद मनीष जायसवाल ने बरही के पूर्व विधायक मनोज यादव संग जिले के बरही अनुमंडल के जल समस्या तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के चौडीकरण से उत्पन्न समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों के आलाधिकारियों से सर्किट हाउस में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान भीषण गर्मी में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र विशेषकर बरही और चौपारण में जल्द से जल्द जलापूर्ति की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही। विभिन्न पंचायतों में संचालित जल नल योजना की त्रुटियों को जल्द दूर करके पानी की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी करने की बात कही। राज्य सरकार द्वारा प्रति पंचायत में निर्धारित पांच चापाकलों के निर्धारित स्थलों पर नियमानुसार लगाने की बात कही। बरही अनुमंडल क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निजात के लिए खराब जलमीनार की तत्काल मरम्मती, खराब चापानल की मरम्मती, बंद पड़े जलापूर्ति योजना को चालू करने तथा गांवों में एसएलडब्लूएल के अंतर्गत बनाए गए सोख्ता, गड्ढा, नाडेप का शीघ्र भुगतान करने को निर्देशित किया गया ।

झुमरीतिलैया में पानी और सफाई की समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन

बिजली की कटौती से बढ़ी परेशानी

PHOTON NEWS KODERMA : जिले के झुमरीतिलैया शहर में पानी, बिजली और सफाई की समस्याओं को लेकर जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने समर्थको के साथ गुरुवार को विद्युत कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया।

धरने के दौरान शालिनी गुप्ता ने कहा कि झुमरीतिलैया में पानी, बिजली और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी है। उन्होंने बताया कि शहर के विभिन्न हिस्सों में बिजली की 23 घंटे की निर्बाध आपूर्ति नहीं हो रही है और 1 घंटे का मेंटेनेंस कार्य भी समय पर नहीं किया जा रहा है। बिजली की कटौती से न केवल जनजीवन प्रभावित हो रहा है, बल्कि पेयजल की आपूर्ति भी बाधित हो रही है। शालिनी गुप्ता ने बताया कि 2014-15 में 60-70 लाख रुपये का टैक्स वसूला जाता था, जो अब बढ़कर 6-7 करोड़ रुपये हो गया है। इसके बावजूद सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन गंभीर समस्याओं का समाधान नहीं करता है, तो जनता टैक्स देने की व्यवस्था पर पुनर्विचार करेगी। कई वार्डों में पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है। कहीं पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है और जहां बिछाई गई है, वहां पानी नहीं पहुंच रहा है। सप्लाई पानी का कनेक्शन शुल्क भी बढ़ा दिया गया है, जिससे जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। धरना स्थल पर बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता सुधांशु ने ज्ञापन पर विभागीय कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, उन्होंने कहा की शहर में 23 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध होगी और मेंटेनेंस केवल एक घंटे में पूरा किया जाएगा।

बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपती शालिनी गुप्ता। ● फोटोन न्यूज

'सभी के सहयोग से करें नशामुक्त राष्ट्र का निर्माण'

LOHARDAGA : मादक पदार्थों पर रोक के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को नगर भवन में किया गया। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि आज समाज में प्रत्येक वर्ग के बच्चे नशा से ग्रसित हैं। समाज कल्याण कार्यालय द्वारा यह कार्यशाला रखी गई है जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र की कर्मीगण भी हैं जिनकी पहुंच के प्रत्येक वर्ग तक है। अक्सर पंचायत व प्रखण्ड स्तर में नशा के विरूद्ध अभियान चलाये जाने की बात होती है। इसमें आंगनवाड़ी सेविकाओं की भूमिका बढ़ जाती है। आप अपने-अपने आंगनवाड़ी क्षेत्र में जाएं और नशा से ग्रसित किशोरों व युवाओं को जागरूक करें और नशा छुड़वाएं। जरूरत पड़े तो जनप्रतिनिधियों को भी साथ लें। उन्हें पढ़ने-लिखने व खेलकूद में रूचि लेने के लिए प्रेरित करें। आपके सहयोग से गांव नशा मुक्त बनेगा। साथ ही जिला के साथ-साथ राज्य और पूरा राष्ट्र नशामुक्त बनेगा।

जांच के बाद ही निर्माण एजेंसी को करें भुगतान

PHOTON NEWS LATEHAR : उपायुक्त गरिमा सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को डीएमएफटी फंड से जिले में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इसमें उपायुक्त ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर सभी संचालित योजनाओं को तय समयवधि के अंदर पूर्ण करें। इसके साथ ही, वैसी योजनाएं, जो पूर्ण कर ली गई हैं, उन्हें जांचोपरांत ही एजेंसी को भुगतान किया जाए। इससे पूर्व उपायुक्त ने डीएमएफटी से हो रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी ली एवं अविलंब कार्यकारी एजेंसी को लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रभारी पदाधिकारी, डीएमएफटी संतोष भगत ने उपायुक्त को डीएमएफटी के माध्यम से संचालित विकास योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति की जानकारी दी। समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने कार्य की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तायुक्त कार्य कराना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने डीएमएफटी की राशि से किए जा रहे पीसीसी पथ निर्माण, पुल-पुलिया निर्माण, स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण, तालाब एवं जलाशय जीर्णोद्धार इत्यादि कार्य की समीक्षा कर निर्माण कार्य को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त सुरजीत कुमार सिंह, सिविल सर्जन डॉ. अवधेश सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत राजीव रंजन व जिला कृषि पदाधिकारी अमृतेश सिंह भी उपस्थित थे।

BRIEF NEWS

राज्य सरकार ने चार डीएसपी का किया तबादला

RANCHI : राज्य सरकार ने चार डीएसपी का तबादला किया है। रांची में विशेष शाखा में पदस्थापित डीएसपी समीर कुमार सवैया को लोहरदगा जिले के किस्को का डीएसपी बनाया गया है। इसीप्रकार सीटीसी मुसाबनी में पदस्थापित डीएसपी अनिमेष गुप्ता को बोकारो का डीएसपी मुख्यालय, पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत मुजीबुर रहमान को विशेष शाखा रांची का डीएसपी और पलामू आईआरबी-10 में पदस्थापित डीएसपी बेनेडिक्ट मरांडी को गिरिडीह आईआरबी- 9 का डीएसपी बनाया गया है। इस संबंध में बुधवार देर रात गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

कांग्रेस की चुनाव परिणाम समीक्षा बैठक स्थगित

RANCHI : कांग्रेस की 21,23 और 24 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव परिणाम समीक्षा समिति की बैठक स्थगित कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने गुरुवार को बताया कि देश में हुए नीट पेपर लीक के मामले में राज्यव्यापी प्रदर्शन का आयोजन 21 जून को किया गया है उसे देखते हुए समीक्षा बैठक स्थगित की गई है। शांति ने बताया कि समिति अब 29 जून को रांची लोकसभा, 30 जून को चतरा एवं लातेहार में, एक जुलाई को लोहरदगा, 2 जुलाई को खूंटी और तीन जुलाई को धनबाद लोकसभा में समीक्षा बैठक करेगी।

उपायुक्त ने नौ सीओ से मांगा स्पष्टीकरण

RANCHI : रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गुरुवार को नौ अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा गया कि नामांतरण वादों में आपत्तिरहित 30 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या एवं आपत्तिसहित 90 दिनों से अधिक लंबित मामलों की संख्या बहुत ही अधिक है तथा सीमांकन वादों में स्वीकृत मामलों की कुल संख्या से अस्वीकृत मामलों की संख्या अधिक है। इस संदर्भ में उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने राजस्व संबंधी मामलों दाखिल-खारिज, उत्तराधिकारी दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन- विभिन्न प्रमाण पत्र, अधिग्रहीत भूमि का दाखिल-खारिज, परिशोधन पोर्टल एवं सीपी ग्राम, पीजी पोर्टल की समीक्षा के क्रम में वादों के लंबित मामले अत्यधिक होने के कारण खेद प्रकट किया है। नामांतरण एवं सीमांकन से सम्बंधित मामलों की समीक्षा में निम्न अंचल में लंबित वादों की संख्या अधिक पाए गए तथा लंबित मामलों की समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण की मांग की गई।

झारखंड विधानसभा में नियुक्ति मामले में हुई गड़बड़ी पर फाइनल सुनवाई

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला रख लिया सुरक्षित

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड विधानसभा नियुक्ति गड़बड़ी मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को शनिवार तक लिखित बहस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन में कोर्ट को बताया कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट कानूनी रूप से रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। रिपोर्ट को सरकार के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था लेकिन इसे सीधे राज्यपाल को दे दिया गया। राज्यपाल ने जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट सरकार को नहीं दी, जिससे विधानसभा के सदन के पटल पर एक्शन रिपोर्ट के बाद छह माह के भीतर इसे नहीं रखा जा सका। जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट में कई त्रुटियां भी थी एवं उस कमीशन की कई अनुशंसा भी अस्पष्ट थी।इन त्रुटियों को देखने के लिए जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की एक कमीशन बनानी पड़ी। जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की रिपोर्ट को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उसे विधानसभा के सदन पटल पर रखा जा चुका है। जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर विधानसभा कमेटी के सदस्य थे, इस कमेटी ने विधानसभा नियुक्ति गड़बड़ी मामले की जांच का रिपोर्ट दिया था की कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें केवल जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट ही दी गई थी, रिपोर्ट के साथ कोई दस्तावेज (एनेक्सचर) नहीं दी गई थी। पूर्व में ही सरकार की ओर से एसजे मुखोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत की जा चुकी थी। झारखंड विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी मामले में शिव शंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड विधानसभा से पूछा था कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट में क्या त्रुटियां थी जिसके कारण दूसरी आयोग बनानी पड़ी थी।

शेषनाथ सिंह खरवार की जमानत मंजूर

झारखंड हाई कोर्ट ने तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में मुख्य साजिशकर्ता गोपाल कृष्ण पातर उर्फ.राजा पीटर के अंगरक्षक शेषनाथ सिंह खरवार को जमानत दे दी है। कोर्ट ने शेषनाथ सिंह खरवार को राहत देते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी। शेषनाथ सिंह खरवार को सात अक्टूबर, 2017 को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। नौ जुलाई, 2008 को बुंडू के एसएस हाई स्कूल में एक समारोह के दौरान रमेश सिंह मुंडा सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पेयजल सचिव व नगर आयुक्त को लगी फटकार

रांची के जलश्रोतों के संरक्षण और रांची के तीन डैमों की साफ-सफाई और अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई।पेयजल विभाग के सचिव और रांची नगर निगम के नगर आयुक्त कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। इस संबंध में झारखंड सिविल सोसाइटी की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। अदालत ने पेश अधिकारियों से पूछा कि शहर में पीने के पानी में गंदगी पर हाई कोर्ट से पहले विभाग का ध्यान क्यों नहीं जाता? कोर्ट के संज्ञान के बाद ही विभाग क्यों जागा ? इसके साथ ही अदालत ने दोनों अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई के दौरान दोबारा कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने नगर विकास विभाग के सचिव को भी ने अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने गुरुवार को नगर आयुक्त और पेयजल विभाग के सचिव से पूछा कि बड़ा तालाब और डैमों की सफाई के लिए लॉन्ग टर्म प्लान क्या है तो दोनों अधिकारियों ने अदालत को बताया कि इसके लिए कई एजेंसियों से विचार विमर्श किया जा रहा है और इसमें नगर विकास विभाग की भी भूमिका है। नगर विकास विभाग जब तक सीवरेज का काम पूरा नहीं करेगा, तब तक जलाशयों को स्वच्छ रखने में दिक्कत होगी। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई में नगर विकास विभाग के सचिव को भी हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।

लंबित मामलों को जल्द करें निष्पादित, डीसी ने दिए निर्देश

समाहरणालय सभाकक्ष में समीक्षा बैठक करते डीसी राहुल कुमार सिन्हा व अन्य।

PHOTON NEWS RANCHI : रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरूवार को समाहरणालय में भू राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में भूमि सीमांकन, लंबित दाखिल खारिज, लंबित प्रमाण पत्र के मामले, भारत सरकार एवं झारखंड सरकार के विभिन्न एजेंसियों को भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। डीसी ने सभी अंचल अधिकारियों से विशेष रूप से कहा कि भूमि का सीमांकन, दाखिल खारिज, रैयती जमीन पर लगान लगा कर सरकारी खजाने में लगान जमा कराएं। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न हो इसके लिए इसे सहेज कर रखना है, जितना भी भू-हस्तान्तरण भारत सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं में करना है, उसका भू-हस्तान्तरण कराएं। डीसी ने लंबित दाखिल-खारिज (लंबित 30 दिन बिना आपत्ति एवं लंबित 90 दिन आपत्ति) एवं भूमि सीमांकन के मामलों की सघन समीक्षा की। उन्होंने कार्य निष्पादन पर असंतोष व्यक्त करते हुए सम्बंधित अंचल अधिकारियों को जल्द से जल्द लंबित दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन के मामले का निष्पादन ससमय करने का निर्देश दिया।

किन मामलों में क्या निर्देश

अंचलों में चल रही महत्वपूर्ण योजना-सरकारी जमीन का अधिग्रहण एवं स्थानांतरण राज्य सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए अंचलों में जो महत्वपूर्ण योजनाएं बड़े पैमाने में चल रही हैं , उसे पूरा कराएं। लंबित प्रमाण पत्र अंचल में लंबित (जाति/आय/आवसीय) को ससमय बना कर देने का निर्देश। म्यूटेशन से संबंधित मामले झ लैंड डिमार्केशन, सक्सेशन पार्टिशन/म्यूटेशन के लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने को कहा गया। राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों की समीक्षा झ विभिन्न स्तर के राजस्व रांपदाधिकारियों के न्यायालयों की समीक्षा, ई कोर्ट के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति की समीक्षा में नियमित रूप से अपने कोर्ट की कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री के निर्देश का दिखा असर अधिकारियों ने मंदिर का किया सर्वे

PHOTON NEWS RANCHI : गुरूवार को पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने रांची के पहाड़ी मंदिर का निरिक्षण किया। झाखंड सरकार ने राज्य के आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों में विशेष ध्यान देने और पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। इसी क्रम में सीएम चंपाई सोरेन ने पर्यटन विभाग को पर्यटन स्थलों को विकसित करने का आदेश दिया था। अब उनका ये प्लान जमीन पर उतरता दिख रहा है। पर्यटन विभाग की टीम ने पहाड़ी मंदिर का सौंदर्यीकरण, विवाह मंडप, दर्शनार्थियों के लिए आरामशाला, पहाड़ी कॉरिडोर, ध्यान केंद्र और सेल्फी प्वाइंट बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को राज्य के धार्मिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का आदेश दिया था। उन्होंने रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका के मंदिर को भी वर्ल्ड क्लास टूरिज्म साइट बनाने का निर्देश दिया था। वहीं पहाड़ी मंदिर में रोपवे बनाने की भी बात कही थी। अधिकारियों ने पहांड़ी मंदिर विकास समिति के सचिव राकेश सिन्हा, राजेश साहू, बादल सिंह के साथ समिति के सदस्यों के साथ बैठक की।

पहाड़ी मंदिर का निरीक्षण करते पर्यटन विभाग के अधिकारी। • फोटोन न्यूज

इंडियन आर्मी की कैंटीन की तर्ज पर पुलिस जवानों के भी बनेंगे स्मार्टकार्ड

RANCHI : झारखंड पुलिस के जवानों के लिए खुशखबरी है। झारखंड पुलिस भी अपने जवानों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने जा रही है। भारतीय सेना की कैंटीन की तरह झारखंड पुलिस के जवानों को भी कैंटीन में कम दामों पर सामान मिलेंगे। राज्य के 40 हजार पुलिसकर्मियों को स्मार्ट कार्ड से फायदा होगा। अब झारखंड पुलिस के जवान पुलिस कैंटीन में स्मार्ट कार्ड के जरिये भी खरीददारी कर पायेंगे। स्मार्ट कार्ड पर खरीदारी सिर्फ पुलिस वाला और फिर उसका परिवारिक सदस्य ही कर सकता है। नई स्कीम के तहत कार्ड जारी होने के बाद जीएसटी में 50 प्रतिशत तक की भी छूट मिलेगी।

मानसून के मद्देनजर नाले-नालियों की सफाई कराना पहली प्राथमिकता

PHOTON NEWS RANCHI : नगर विकास सचिव अरवा राजकमल ने कहा कि राज्य के सभी शहरी निकायों में मानसून के मद्देनजर नाले नालियों की सफाई कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना प्राथमिकता होगी। गुरुवार को नगर विकास सचिव अरवा राजकमल ने चंद्रशेखर से प्रभार ग्रहण करने के बाद ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि साथ ही सभी निकायों में जलजमाव की समस्या के रोकथाम के उपाय किये जायेंगे। इसके लिए निकायों के अधिकारियों को प्रभार ग्रहण करने के साथ ही निर्देश भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पेयजलापूर्ति एवं सीवरेज संबंधी चालू योजनाओं को गति प्रदान कर उसका लाभ आम जनता को दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। इसकी जल्द ही समीक्षा की जायेगी। राजकमल ने कहा कि नगर विकास से संबंधित दीर्घावधि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सुधारात्मक निर्णय लेकर सकारात्मक पहल की जायेगी। सचिव ने कहा कि विभाग को नये कनीय अभियंताओं के पदास्थापन से विकास कार्यों के लिए बल मिला है। उन्हें प्रशिक्षित कर नगर स्तर पर होने वाले कार्यों की जवाबदेही सौंपी जायेगी। इससे स्थानीय स्तर के कामों में तेजी आयेगी। नगर विकास विभाग के कार्यों में अन्य विभागों के साथ संबंध रहता है। इसके लिए दूसरे विभागों के साथ समन्वय बना कर योजनाओं में तेजी लायी जायेगी।

नगर विकास सचिव अरवा राजकमल।

हॉकी इंडिया सब-जूनियर चैंपियनशिप का हुआ ट्रायल

PHOTON NEWS RANCHI : असम के गुवाहाटी में 24 जुलाई से 31 जुलाई तक हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जॉन महिला और पुरुष हॉकी चैंपियनशिप आयोजित किया गया है। इसके लिए हॉकी झारखंड टीम गठन के लिए गुरुवार को पुरुष खिलाड़ियों का चयन ट्रायल किया गया। ट्रायल का आयोजन मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित हुई । पुरुष वर्ग का चयन ट्रायल में सिमडेगा, खूंटी, गुमला, लातेहार ,रांची , हजारीबाग सहित झारखंड के अन्य जिला से कुल 135 हॉकी खिलाड़ी ट्रायल में शामिल हुए। इन खिलाड़ियों में से 25 खिलाड़ी को चयन किया गया है ,जिनका विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर उनमें से बेहतर 18 खिलाड़ियों को चयनित कर उक्त प्रतियोगिता में भेजा जायेगा।

हर वर्ग के विकास के लिए दरवाजे खोलेगी जाति जनगणना : प्रदीप

PHOTON NEWS RANCHI : कांग्रेस विधायक दल के उप नेता प्रदीप यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना हर वर्ग के विकास के लिए दरवाजे खोलेगा।उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन सरकार के जरिये कैबिनेट की ओर से जातिगत जनगणना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिलना। सूबे के उन सभी वर्गों के विकास के लिए दरवाजे खोलेगा। जिन्हें अबतक उनके भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली है। यादव गुरुवार को कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने प्रस्ताव पारित होने पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कैबिनेट के सदस्यों सहित कांग्रेस एवं गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी धन्यवाद दिया कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर लगातार इसे लेकर सरकार से बात कर रहे थे। यादव ने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि यह निर्णय राज्य के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों ,वंचितों, अल्पसंख्यक और मूलवासियों को राज्य के विकास में भागीदार बनाएगा। कांग्रेस और राहुल गांधी चाहते थे कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो इसके लिए लंबा संघर्ष आज भी किया जा रहा है, झारखंड सरकार का यह निर्णय इस संघर्ष को भी प्रभावित करेगा और देश में संदेश देगा कि कांग्रेस की सरकार और गठबंधन की सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह गंभीर है।

सीएम, मंत्रियों-विधायकों का वेतन बढ़ाना शर्म का विषय

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव झारखंड छत्तीसगढ़ प्रभारी विजय शंकर नायक ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों एवं विधायकों के वेतन में 20 हजार रुपये की वृद्धि करने पर नाराजगी जाहिर की है। कहा कि जिस राज्य में कुपोषण से 69 प्रतिशत बच्चे और 65 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी जैसे रोग से प्रभावित हों, पलायन, बेरोजगारी,भुखमरी चरम पर हो, उस राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों का वेतन बढ़ाना शर्म का विषय है। झारखंड राज्य गठन के 24 वर्ष बाद भी राज्य कुपोषण की बड़ी आपदा से घिरा हुआ है। हाल में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार, झारखंड के अधिकतर बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। यह राज्य के माननीय एवं नौकरशाहों के लिए शर्म का विषय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा संगठन ने भी यह स्वीकारा की झारखंड में सबसे बड़ी मूल समस्या कुपोषण है। राज्य में कुपोषण की समस्या सबसे ज्यादा है। अन्य राज्यों की अपेक्षा इसमें झारखंड सबसे आगे है।

विजय शंकर नायक। • फोटोन न्यूज

नौ दिनों तक गुलजार रहेगा मेला, श्रृंगार-पूजन कर 108 दीपों से उतारी जाएगी आरती

भगवान जगन्नाथ कल करेंगे स्नान

PHOTON NEWS RANCHI : भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा संग महास्नान और श्रृंगार कर 15 दिनों के लिए एकांतवास में जायेंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून को प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मंदिर में नेम-निष्ठा से स्नान यात्रा अनुष्ठान कराया जायेगा। मंदिर के पुजारी कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि दिन के डेढ़ बजे से अनुष्ठान शुरू होगा। मंदिर के पुरोहित वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान को 108 कलश में रखे वनौषधि और सुगंधित जल से स्नान करायेंगे। श्रृंगार-पूजन कर 108 दीपों से आरती उतारी जायेगी। ढाई बजे परंपरानुसार आदिवासी पाहन और श्रद्धालु भी दूध, जल और सुगंधित द्रव्य आदि से प्रभु को स्नान करायेंगे। इसके बाद विग्रहों का स्पर्श दर्शन कर मंगल कामनाएं की जायेगी। फिर विग्रहों को पुजारी गर्भ गृह में ले जायेंगे। उन्होंने बताया कि प्रभु गर्भगृह में छह जुलाई तक रहेंगे। दर्शन सुलभ नहीं होगा। दर्शनार्थी श्रीगणेश, श्रीकृष्ण रूप का दर्शन और पूजन कर सकेंगे। प्रभु की सांकेतिक पूजा होगी। गर्भगृह में विग्रहों का रंग-रोगण किया जायेगा।

छह को नेत्रदान, रथ यात्रा सात जुलाई को : आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा छह जुलाई को जगन्नाथ स्वामी का एकांतवास समाप्त होगा। मंदिर के गर्भगृह से बाहर आने के बाद भगवान का नेत्रदान किया जायेगा। साथ ही भगवान सर्वदर्शन शुलभ हो जायेंगे। कौस्तुभ ने बताया कि नेत्रदान अनुष्ठान शाम साढ़े चार बजे से शुरू होगा। सात जुलाई को रथ यात्रा निकाली जायेगी।

बीमार होंगे भगवान, चलेगा उपचार : मान्यतानुसार भगवान स्नान करने से बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में उनका उपचार किया जाता है। पुजारी के द्वारा खास काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है। इसमें सोठ, पिंपली, दाल चीनी, गुल मिर्च से बनाया हुआ काढ़ा भगवान श्री जगन्नाथ को पिलाया जाता है। रथ यात्रा मेला नौ दिनों तक गुलजार रहेगा. भक्त भक्ति आनंद के साथ मेले का भी लुफ्त उठायेंगे। तरह-तरह के झूले, नाटक-नवटंकी वालों के साथ खाने-पीने का स्टॉल सब को लुभायेगा। पारंपरिक साजो समानों की जमकर बिक्री होगी। पशु-पक्षी और ढोल-नगाड़ा से लेकर खेती-गृहस्थी तक का साजो-सामान भी मिलेगा। इस तरह का बाजार सिर्फ रथ यात्रा मेले के दौरान ही लगाया जाता है। यही कारण है कि नौ दिनों तक मेला में भारी भीड़ रहती है।

नशा मुक्ति को लेकर कार्यशाला आयोजित, हेल्पलाइन नंबर जारी

PHOTON NEWS RANCHI : मादक पदार्थों पर रोक को लेकर गुरुवार को मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में जिलास्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान एसपी एनसीबी सारिक उमर की ओर से विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों और उनके प्रभाव के बारे में पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी गयी। उपस्थित लोगों विशेषकर छात्रों को मादक पदार्थों की पहचान, सेवन से होने वाले प्रभाव और बचाव के बारे में विस्तार से बताया गया। नशे के सेवन से किस तरह युवा पीढ़ी और समाज प्रभावित हो रहे हैं इससे संबंधित एनसीबी का वीडियो भी सभी को दिखाया गया।कार्यशाला में संबोधित करते हुए एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि नशा के खिलाफ जनजागरण की आवश्यकता है। माता-पिता सहित अन्य अभिभावक बच्चों के क्रियाकलापों पर नजर रखें, उनसे बातचीत करें, साथ में लंच या डिनर करें। बच्चों की आंखों, चलने और बोलने के तरीके से पहचानें, कहीं वो नशा तो नहीं कर रहा। उन्होंने बताया कि इसके लिए रांची पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जिस पर व्हाट्सऐप के माध्यम से रांची में चल रहे नशे के कारोबार, मादक पदार्थों की बिक्री एवं इसमें संलिप्त व्यक्ति की जानकारी दी जा सकती है। कार्यशाला के दौरान सभी को ये वीडियो दिखाया गया। कार्यशाला के दौरान उपस्थित लोगों को हेल्पलाइन नंबर 9153886238 नोट कराया गया एवं सभी से दूसरे लोगों से साझा करने की अपील की गयी।

कार्यशाला में शामिल अधिकारी व अन्य। • फोटोन न्यूज

समाचार सार

आयकर विभाग ने छात्र-छात्राओं को दिए जूते-मोजे

JAMSHEDPUR : आयकर विभाग, जमशेदपुर के प्रधान आयकर आयुक्त शिशिर धमीजा के निर्देश पर बाराद्वारी स्थित पीपुल्स अकादमी के करीब 50 छात्र-छात्राओं को जूते-मोजे दिए गए। इस मौके पर आयकर विभाग से विजय कुमार (आईटीओ, हेड क्वार्टर), प्रीतम सिंह (एओ), सुजीत कुमार (एमटीएस), समाजसेवी पूरबी घोष और विद्यालय के प्रिंसिपल चंद्रदीप पांडेय उपस्थित थे।

स्टे लगी जमीन पर पार्क बनाने की कोशिश

JAMSHEDPUR : एग्रिको कंपनी की दीवार से सटे श्रीश्री सार्वजनिक शिव मंदिर के समीप निजी जमीन पर हाई कोर्ट द्वारा स्टे लगे होने के बावजूद पार्क बनाने का मामला प्रकाश में आया है। जमीन मालिक की ओर से अधिवक्ता एसएस तिवारी ने बताया कि यह भूखंड ए. संजीबी के नाम से है और बिहार सरकार ने उक्त भूखंड को टाटा लीज से बाहर कर दिया है। इसके लिए टाटा स्टील ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने 28 मार्च 2012 को खारिज कर दिया था। इसके बाद टाटा स्टील ने हाई कोर्ट में दूसरी अपील दाखिल की, लेकिन वह अभी सुनवाई के लिए लंबित है। यदि जबरन पार्क बनाया जाता है तो यह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला होगा।

आजसू पार्टी का स्थापना दिवस कल, तैयारी पूरी

JAMSHEDPUR : आजसू पार्टी का स्थापना दिवस 22 जून को विभिन्न स्थानों पर मनाया जाएगा। इसे लेकर गुरुवार को तमाम स्थानों पर बैठक हुई, जिसमें पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने बोड़ाम, पटमदा, घोड़ाबांधा, एनएच-33, जुगसलाई व परसुडीह, जिलाध्यक्ष कन्हैया सिँह ने बागबेडा व सुंदरनगर और चंदगुप्त सिंह ने पूर्वी विधानसभा की कमान संभाली है। ज्ञात हो कि पार्टी का स्थापना दिवस बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बैठक मे सहिस ने बताया कि पार्टी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी की सहभागिता आवश्यक है।

रंगकर्मियों ने बरेली में किया 'कसक' का मंचन

JAMSHEDPUR : शहर के युवा रंगकर्मियों ने गुरुवार को बरेली में 'कसक' नाटक का मंचन किया। गीता थिएटर के कलाकारों ने थिएटर अड्डा में रंगालय एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर सोसायटी बरेली द्वारा आयोजित 15 दिवसीय नाट्य समारोह के 3वें दिन लोक खुशहाली चेरिटेबल ट्रस्ट सभागार में इस नाटक का मंचन किया। इसकी कहानी मजबूरी एवं गरीबी के भव-सागर मे फंसे अति-निम्न मध्यमवर्गीय परिवार में रहने वाले कर्ज.में डूबे बुधवा, सुगनी (पत्नी) एवं उसके दो बच्चों (फुलवा एवं सोहन) की व्यथा-कथा है। नाटक में दिखाया गया है कि परिवार की खुशी के लिए सुगनी पहले अपनी इज्जत का सौदा करती है, तो अंत में आत्महत्या कर लेती है। नाटक में सुगानी का किरदार गीता कुमारी, बुधवा का पात्र सोनारी निवासी सूरज धीवर, बेटी फुलवा का पात्र नवनीत कौर और बेटा सोहन का अनंत सरदार, नाटक के खलनायक बड़े ठाकुर की भूमिका प्रेम दीक्षित तथा नौकर का पात्र अभिरंजन कुमार ने निभाया। मंचन सज्जा में हरजीत कौर, प्रकाश में आलोक और ध्वनि में भूमि सिंह ने सहयोग किया।

कदमा में सजी शास्त्रीय संगीत संध्या

JAMSHEDPUR : शास्त्रीय संगीत के प्रति समर्पित संस्था बंशी बोस म्यूजिक फाउंडेशन और कला उद्यान, जमशेदपुर की संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को संध्या 6.30 बजे से कला उद्यान, उलियान, कदमा के प्रेक्षागृह में शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इसमें देश के प्रख्यात सितार वादक पंडित देवजीत चक्रबर्ती ने सितार पर राग मियां मल्हार में आलाप, जोड़, झाला बजाकर राग कलाश्री में विलंबित और द्रुत तीनताल में बंदिश पेश की। तबले में शहर के तबला वादक अमिताभ सेन ने बखूबी संगत किया। कार्यक्रम का उद्घाटन जेएमसी के अध्यक्ष अनिरुद्ध सेन, समाजसेवी पूरबी घोष, लेखिका विभा मिश्रा, बंगाल क्लब के सचिव सौम्य सेन व बीबी चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया।

अर्पण का रक्तदान शिविर 23 को

JAMSHEDPUR : शहर की संस्था अर्पण द्वारा 23 जून को महारक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की शहादत को समर्पित यह शिविर साकची स्थित रेडक्रॉस भवन में सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चलेगा।

पूर्वी सिंहभूम में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के 105 शिक्षकों की होगी नियुक्ति

सबसे अधिक बांग्ला के 81 शिक्षक होंगे नियुक्त, प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजा गया

PHOTON NEWS JSR: झारखंड के सरकारी स्कूलों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य के सभी जिलों में भाषावार पद सृजन की प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में सिंहभूम जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने छात्र संख्या के अनुसार पद सृजन की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

इसके तहत जिले के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा के नामांकित विद्यार्थियों के आधार पर कुल 105 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसका प्रस्ताव जिला शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेज दिया गया है। ऐसे में अब इतने पदों पर ही शिक्षकों की नियुक्ति इस जिले में होगी। अगर भाषावार पद की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में बोली जाने वाली तीन जनजातीय भाषा (संताली, मुंडारी व भूमिज) के लिए 18 और क्षेत्रीय भाषा बांग्ला व उडिया के लिए 87 शिक्षकों के पद सृजन का प्रस्ताव भेजा गया है। यह प्रस्ताव विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के बच्चों के सर्वेक्षण के बाद तैयार किया गया। इसके तहत जिले के सभी 1500 सरकारी स्कूलों से डाटा संग्रह किया गया।

प्रशिक्षित शिक्षकों को अधिकतम 600 तो अप्रशिक्षित को 360 रुपए हर दिन मिलेगा मानदेय: जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के लिए घंटी आधारित शिक्षकों के रूप में नियुक्ति होगी। चयन मेरिट के आधार पर होगी। इसमें प्रशिक्षित (प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण बीएड) को प्रत्येक घंटी के लिए 200 रुपए की दर से एक दिन में अधिकतम 600 रुपए देय होगा। अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रत्येक घंटी के लिए 120 रुपए की दर से एक दिन में अधिकतम 360 रुपए देय होगा। संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा इस संबंध में प्राप्त निधि से वास्तविक उपस्थिति एवं लिए गए क्लास के आधार पर मानदेय भुगतान किया जाएगा। एक महीने में अधिकतम 25 कार्य दिवस की गणना की जाएगी।

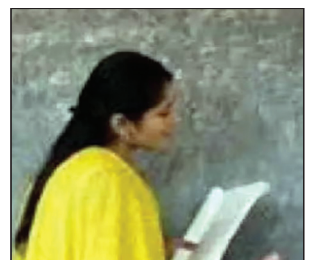

जिले में किस भाषा में कितने शिक्षकों के लिए भेजा गया प्रस्ताव

भाषा	:	कुल पद
संथाली	:	11
मुंडारी	:	01
भूमिज	:	06
बांग्ला	:	81
उडिया	:	06

इस आधार पर तैयार होगी मेधासूची: शिक्षकों का चयन मेधा सूची के आधार पर होगा। इसके 100 अंकों पर मेरिट बनेगी। इसमें मैट्रिक के लिए 20, इंटर के लिए 30, जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के लिए 10, स्नातक के लिए 20, स्नातकोत्तर के लिए 10 व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण/बीएड के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके आधार पर अधिकतम प्राप्तांक वाले वेदकों का चयन किया जाएगा। चयनित शिक्षकों की संपुष्टि पहले प्रखंड स्तरीय चयन समिति पूर्ण प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। इसके बाद उपायुक्त की अध्यक्षता वाली चयन समिति सूची को संपुष्ट करेगी।

इसलिए की जा रही नियुक्ति: सरकार का कहना है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन-अध्यापन का कार्य किया जाता है तो इसका सीधा असर उनकी उपस्थिति में पड़ता है। मातृभाषा को विद्यालयों में व्यवहार में लाया जाए तो बच्चे सहजता से विद्यालयी परिवेश से जुड़ेंगे तथा उनका ठहराव विद्यालयों में लंबी अवधि के लिए होगा। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया का असर विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा पर भी होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने का निर्देश है।

स्नातक नामांकन के लिए 23 हजार अभ्यर्थियों ने भरा आवेदन

JAMSHEDPUR : कोल्हान विश्वविद्यालय के चार वर्षीय स्नातक (सत्र 2024-28) कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गयी है। मिली जानकारी के अनुसार इस बार 23 हजार विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। यह पिछले तीन सालों में सबसे कम है। एडमिशन के लिए मेधा सूची 24 जून को जारी होगी। विश्वविद्यालय की ओर से सभी कॉलेजों के प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी कर नामांकन के लिए तैयार रहने को कहा है। मेधा सूची कॉलेजवार जारी होगी जिसके आधार पर दाखिला लिया जाएगा। कोल्हान विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों को निर्देश जारी कर अपने यहां अनिवार्य रूप से हेल्प डेस्क बनाने को कहा है। ताकि किसी स्टूडेंट को एडमिशन से संबंधित समस्या हो तो वह हेल्प डेस्क से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके।

इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर तैयार होगी मेधा सूची: स्नातक में नामांकन के लिए मेधा सूची इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार होगी। इससे सभी कॉलेज अपने स्तर से जारी करेंगे।

एनएमएल के 'बिहाइंड द टीचर्स डेस्क' में प्रस्तुत किए गए 57 तकनीकी पत्र

PHOTON NEWS JSR: बर्मामाइंस स्थित सीएसआईआर-एनएमएल में आयोजित दो दिवसीय 'बिहाइंड द टीचर्स डेस्क' सेमिनार का गुरुवार को समापन हो गया। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों/ संस्थानों के 100 से अधिक छात्रों और वक्ताओं ने भाग लिया। धातुकर्म और सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में तीन समानांतर सत्रों में लगभग 57 तकनीकी पत्र प्रस्तुत किए गए। 'बिहाइंड द टीचर्स डेस्क' के 14वें संस्करण का आयोजन सीएसआईआर-नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी के सहयोग से भारतीय धातु संस्थान (आईआईएम) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसमें टाटा स्टील लिमिटेड, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जमशेदपुर और एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च (एसीएसआईआर) ने भी सहयोग किया। सीएसआईआर-एनएमएल सभागार में हुए समापन समारोह में आईआईएम जमशेदपुर के सचिव डॉ. गोपी किशोर मंडल ने फीडबैक सत्र का संचालन किया और प्रतिभागियों से कुछ सुझाव प्राप्त किए। सीएसआईआर-एनएमएल के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधरी और आईआईएम जमशेदपुर चैप्टर के अध्यक्ष प्रो. अशोक कुमार ने सभी प्रतिभागियों-विजेताओं को बधाई दी। धन्यवाद ज्ञापन बीटीटीडी-2024 के सह-संयोजक डॉ. प्रेम कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि प्रतिभागी 21 जून को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट का औद्योगिक दौरा करेंगे।

एनएमएल के समापन समारोह में सम्मानित प्रतिभागी • फोटोन न्यूज

टेल्को ग्राउंड में जेएन टाटा ट्रॉफी क्रिकेट शुरू

JAMSHEDPUR : टाटा मोटर्स क्रिकेट कोचिंग सेंटर एवं झारखंड यूथ क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को जेएन टाटा ट्रॉफी का तीसरा क्रिकेट टूनार्मेंट टेल्को ग्राउंड में शुरू हुआ। इस टूनार्मेंट में कुल 18 टीम भाग ले रही है, जिसमें जमशेदपुर से 12 और रांची, चक्रधरपुर रेल मंडल, घाटशिला, खड़गपुर आदि की टीमें हैं। आयोजन में उपेंद्र सिंह, महेंद्र यादव, बाबला, सोनू सिंह, पंकज, रवि शर्मा आदि सक्रिय हैं। इस टूनार्मेंट का फाइनल 30 जून को खेल जायगा। पहले दिन मुख्य अतिथि टाटा मोटर्स के एचआर हेड मोहन गंटा व टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।

बुरुडीह डैम के सुंदरीकरण को 23 को भूमिपूजन करेंगे सीएम

- वन विभाग डैम के पास बना रहा गेस्ट हाउस, पार्क भी बनेगा

PHOTON NEWS GHATSHILA: पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल अंतर्गत बुरुडीह डैम का सुंदरीकरण होना है। इसके लिए मुख्यमंत्री 23 जून को वन विभाग द्वारा बनाए जाने वाले गेस्ट हाउस का भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डीडीसी मनीष कुमार, एसएसपी किशोर कौशल समेत कई विभागीय पदाधिकारी ने गुरुवार को बुरुडीह डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान डैम के नीचे वाले मैदान की साफ-सफाई का निर्देश दिया। वन विभाग के पदाधिकारियों से मैदान के किनारे-किनारे ट्रेंच खोदने को कहा, ताकि कार्यक्रम के दौरान यदि बारिश हो जाए, तो मैदान में जलजमान नहीं हो सके। इस दौरान सीएम के चॉपर उतरने के स्थान को लेकर बुडुडीह डैम के किनारे बने फुटबॉल मैदान का भी अधिकारियों ने जायजा लिया। इस दौरान एसडीओ सच्चिदानंद महतो, बीडीओ युनिका शर्मा व सीओ निशात अंबर भी मौजूद थे।

पहले फेज में 35 करोड़ होंगे खर्च

बताया जाता है कि पहले चरण में बुरुडीह डैम के सुंदरीकरण पर लगभग 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें डैम के नीचे गेस्ट हाउस, बेहतर खेल का मैदान, पार्क आदि का निर्माण किया जाएगा। इससे लोगों में यह उम्मीद जगने लगी है कि अब घाटशिला के प्रमुख पर्यटन स्थल के दिन बहुरेंगे।

टाटा स्टील के पक्ष में हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

- टाटा स्टील व पुंज एंड संस प्रा. लि. के बीच 1996 से चल रहा था विवाद

PHOTON NEWS JSR : झारखंड हाई कोर्ट ने लगभग 28 वर्ष पुराने मामले में टाटा स्टील के पक्ष में फैसला सुनाया है।

टाटा स्टील ने पुंज एंड संस प्रा. लि. को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए मासिक किरायेदारी नियमों और शर्तों पर बमार्माइंस क्षेत्र में 3.544 एकड़ भूखंड आवंटित किया था। उक्त आवंटन पूरी तरह से अस्थायी आधार पर इस समझ के साथ किया गया था कि वे आदित्यपुर क्षेत्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण (एआईडीए) की योजना पूरी होने पर अपने कारखाने को आदित्यपुर में स्थानांतरित कर देंगे। चूंकि एआईडीए यानी आयडा की योजना पूरी होने और कंपनी द्वारा उन्हें दिए गए समय के विस्तार के बाद भी पुंज एंड संस ने परिसर खाली नहीं किया, इसलिए टाटा कंपनी द्वारा इसे खाली कराने के लिए पुंज एंड संस के खिलाफ टाइटल सूट दायर किया गया था। इसमें 1996 में अपील का फैसला पुंज एंड संस के पक्ष में हुआ। टाटा कंपनी ने टाइटल अपील में पारित फैसले को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। इस बीच, पुंज एंड संस ने कंपनी बेच दी। तब वाणी इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड पक्षकार बना। अंततः न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की पीठ के समक्ष दूसरी अपील पर सुनवाई हुई और टाटा कंपनी द्वारा प्रस्तुत दूसरी अपील को अनुमति देते हुए 13.06.2024 को फैसला सुनाया गया।

मोंटी अग्रवाल के समर्थन में उतरा अग्रवाल समाज

JAMSHEDPUR : भाजपा के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने 18 जून को भाजयुमो, जमशेदपुर महानगर के मीडिया प्रभारी मोंटी अग्रवाल एवं भाजयुमो जमशेदपुर महानगर के आईटी सेल प्रभारी आशीष कुमार साहू को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया था। इस पर मोंटी अग्रवाल के समर्थन में अग्रवाल समाज उतर गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन के जिलाध्यक्ष संदीप मुरारका ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर मोंटी अग्रवाल का निलंबन वापस कराने की मांग की है। लंबे-चौड़े पत्र में बाबूलाल को अग्रवाल समाज के महत्व से भी अवगत कराया गया है।

पत्र की प्रतिलिपि भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह को भी प्रेषित करने का उल्लेख किया गया है।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन सर्वोत्तम तरीका : डीडीसी

PHOTON NEWS JSR: समाहरणालय सभागार में गुरुवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को जिला में सुचारू रूप से संचालित करने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में शामिल मुख्य अतिथि उपविकास आयुक्त मनीष कुमार ने बढ़ती जनसंख्या पर प्रभावी कार्ययोजना के रूप में परिवार नियोजन को महत्वपूर्ण बताया। उपविकास आयुक्त ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन सर्वोत्तम तरीका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ह्यछोटा परिवार सुखी परिवारह्ण के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम वर्षों से चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से शिविर लगाकर बंध्याकरण एवं नसबंदी कर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने को कहा। उन्होंने विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। जून-जुलाई में परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रम जिला में चलाए जाएंगे। ऐसे में परिवार नियोजन के उपायों को अपना कर जनसंख्या संतुलन को बनाए रखा जा सकता है तथा ह्यस्वस्थ झारखंड सुखी झारखंडह्ण की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है।

जनसंख्या नियंत्रण पर बैठक करते डीडीसी मनीष कुमार

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज | **सुबह से शाम तक विभिन्न संस्थाओं द्वारा मनाया जाएगा योग दिवस**

योग के रंग में डूबेगी लौहनगरी, सीखेंगे निरोग रहने के गुर

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : अंतरराष्ट्रीय योग दिवस देश-विदेश के साथ लौहनगरी में भी शुक्रवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसे लेकर शहर की राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं की ओर से भव्य तैयारी की गई है। भाजपा, जमशेदपुर महानगर की ओर से सभी 28 मंडलों में सामूहिक रूप से योग दिवस मनाया जाएगा, तो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अलावा शिक्षण संस्थानों ने भी व्यापक तैयारी की है। अधिकांश आयोजन सुबह में किए जाएंगे, जबकि कुछ संस्थाओं की ओर से शाम को योग दिवस पर आयोजन किए जाएंगे। शहर की सोसाइटी-कॉलोनी में भी सुबह से योग दिवस की धूम रहेगी। इस दौरान शहर के महिला-पुरुष योग शिक्षक आसन-प्राणायाम का अभ्यास तो कराएंगे ही, स्वस्थ जीवनशैली के गुर भी बताएंगे। इस दौरान सबसे ज्यादा चहल-पहल जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, जुबिली पार्क, गांधी घाट, एग्रिको ट्रांसपोर्ट मैदान, सिदगोड़ा सूर्य मंदिर सहित शहर के विभिन्न पार्कों-मैदानों में रहेगी, जहां शहरवासी नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं।

योगाभ्यास करतीं महिलाएं • फोटोन न्यूज

घोड़ाबांधा में सुबह 5.30 बजे से होगा योग

टेल्को स्थित साईनाथ देवस्थानम, घोड़ाबांधा में शुक्रवार को सुबह 5.30 से 6.30 बजे तक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसी कड़ी में सुबह 9.30 से 10.30 बजे तक ज्येष्ठ पूर्णिमा का पूजन होगा।

बोधि मंदिर में शाम 4 बजे से होगा योग दिवस

साकची स्थित बोधि मंदिर में शुक्रवार शाम 4 बजे से योग दिवस मनाया जाएगा। यहां जमशेदपुर वीमेंस क्लब ईशा फाउंडेशन के साथ कार्यक्रम होगा।

आसनों का अभ्यास व फायदे

अनुलोम-विलोम: क्रोध, विस्मृति, बेचैनी,नकारात्मकता और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस बीमारी दूर होती है
सूर्य नमस्कार: शरीर, मन और आत्मा सबल होते हैं।
भुजंगासन: पाचन, लिवर और किडनी और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है।
गोमुख आसन: मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को दूर करने
सूखासन: मन को शांत ,चिंता और तनाव को दूर करती है।
वज्रासन: गैस-कब्ज-एसिडिटी दूर करता है।
वृक्षासन: पैरों, टखनों, पिंडलियों, घुटनों और जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करता है।
कपालभाति: इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है।
चक्रासन: सिरदर्द, नेत्र विकारों, सर्वाइकल व स्पोंडोलाईटिस कंट्रोल रहता है।
ताड़ासन: शरीर के पोस्चर में सुधार होता है।
पर्वतासन: मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है।

मानगो गांधी घाट में चल रहा 100 घण्टे का योग अभ्यास

पतंजलि योग सेवा समिति जमशेदपुर शाखा की ओर से मैंगो गांधी घाट में 2 जून से सामूहिक योग अभ्यास चल रहा है जिसमें 60 अभ्यर्थी अभ्यास कर रहे हैं सुबह 5:00 बजे से 8:00 तक ऑफलाइन और शाम को 5:00 बजे से 7:00 तक ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है।

पुलिस लाइन में चल रहा अभ्यास

पुलिस लाइन में 21 जून के लिए तैयारी चल रही है यहां महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों को योग सिखाया जा रहा है योग आचार्य कृतिका कुमारी ने बताया कि 45 मिनट अभ्यास रोजाना कराया जा रहा है। यहाँ सुबह 5:30 बजे से अभ्यास कराया जाता है

बारीडीह बस्ती में पिछले एक महीने से सिखाया जा रहा

योगाचार्य मगनलाल शर्मा बारीडीह में लोगों को योग सीख रहे हैं मगनलाल शर्मा शहर से लेकर झारखंड बिहार के अन्य स्थान पर ऑफलाइन और ऑनलाइन योग की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि लोग योग के प्रति सजक बने और बीमारियों से दूर रहे।

घर पर प्रैक्टिस

योगाचार्य मगनलाल शर्मा ने बताया कि योग दिवस के लिए लोग घर बैठकर की योगाभ्यास की शुरूआत कर सकते हैं ताकि शहर में होने वाले मुख्य आयोजन का हिस्सा बन सकें। इसके चलते सूर्यनमस्कार, अनुलोम-विलोम, गोमुख आसन और अन्य आसनों को दोहराकर प्रैक्टिस की जा रही है।

दपू रेलवे में लोको पायलट के 1308 पद वर्षों से रिक्त

जोन में सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसी की वर्तमान स्थिति

सर्किल	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
दक्षिण पूर्व रेलवे जोन	10,623	9,315	1308
चक्रधरपुर डिवीजन	5,147	4,530	533
आद्रा डिवीजन	1790	1399	387
रांची डिवीजन	894	791	94
खड़गपुर डिवीजन	2763	2572	173

JAMSHEDPUR : दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में सेफ्टी कैटेगरी के तहत लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के 1308 पद वर्षों से रिक्त है। रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं हो रही है, वहीं पैसेंजर ट्रेन की संख्या और मालगाड़ियों से ढुलाई लगातार बढ़ रही है। इस कारण लोको पायलट और सहायक लोको पायलट 8 घंटे के बजाए 10 से 12 घंटे तक लगातार काम कर रहे हैं। नींद पूरा नहीं होने और मानसिक दबाव के कारण सिग्नल ओवर शूटिंग, ओवर स्पीडिंग समेत कई गलतियां लोको पायलटों से हो रही है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ स्टाफ एसोसिएशन के नेता तापस चट्टोराज का कहना है कि सेफ्टी कैटेगरी के बेहद जरूरी पदों पर नियुक्ति होने से लोको पायलट और सहायक लोको पायलटों की संख्या बढ़ेगी। उन्हें पर्याप्त आरामि मलने से लोको पायलट पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे।

BRIEF NEWS

विधानमंडल का मानसून सत्र 22 से 26 जुलाई तक

PATNA : बिहार विधानमंडल का सत्र आगामी 22 से 26 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी।बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के लिए सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद अब विधानसभा सचिवालय जल्द ही पूरा शेड्यूल जारी करेगा।पांच दिनों तक चलने वाले सत्र के दौरान सरकार कई अहम विधेयकों को सदन के पटल पर रखेगी और दोनों सदनों से उन्हें पारित कराने की कोशिश करेगी। 22 जुलाई को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही मानसून सत्र की शुरूआज होगी। सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।

23 साल पुराने केस में साधु यादव को सजा

PATNA : आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के साले साधु यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज जेल भेज दिया है। जिस मामले में साधु यादव को बेऊर जेल भेजा गाय है। वो मामला 23 साल पुराना है। जब साल 2001 में साधु पर परिवहन आयुक्त को धमकाने और कार्यालय में हंगामा करने का मामला दर्ज हुआ था। साल 2022 में एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में साधु को 3 साल की सजा सुनाई थी। वहीं पटना हाईकोर्ट ने सजा के खिलाफ दायर अपील पर सरेंडर के बाद सुनवाई की बात कही थी।

बिजली की चपेट में आकर युवक की मौत

CHAMPARAN : जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के सरेया कचहरी टोला गाँव में एक युवक की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गयी । मौत के बाद परिजन में चीख पुकार मच गयी है। मृतक नागेंद्र साह के 31 वर्षीय पुत्र रविकांत कुमार है। बताया गया कि रविकांत अपने ही घर में बिजली वायर का काम कर रहा था, जिससे करंट की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजन ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण रविकांत कुमार घर मे पंखा लगाने को लेकर तार सेट कर रहा था। पंखे का तार निकालने के क्रम में वह करंट की चपेट में आकर तार पर हीं गिर गया। आनन फानन में ग्रामीण पहाड़पुर स्थित एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अपराध की योजना बनाते अवैध हथियार के साथ धराया

BHAGALPUR : सिटी एसपी राज ने गुरुवार को बताया कि बीते 19 जून को रात्रि में जगदीशपुर थाना की पुलिस को सूचना मिली की मुस्तफापुर लोहा पुल के पास कुछ लोग मिलकर किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष जगदीशपुर अपने दल-बल के साथ सूचना स्थल पर पहुंचे। पुलिस को आते देख तीनों व्यक्ति भागने लगे जिन्हें पकड़कर तलाशी ली गई। उक्त तीनों व्यक्तियों की तलाशी लेने पर 01 देशी कट्टा एवं 03 कारतूस बरामद किया गया तथा उक्त तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

बिहार में नीतीश कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों पर लगाई मुहर

मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया व भागलपुर में चलेगी मेट्रो

- खेल विभाग में 98 समेत विभिन्न विभागों में 545 नए पदों के सृजन की स्वीकृति
- नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में खेल क्लब का किया जाएगा गठन

AGENCY PATNA : बिहार में नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान कुल 22 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है। इसमें फैसला लिया गया कि मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल चलेगी। राज्य कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने खेल विभाग में 98 समेत विभिन्न विभागों में 545 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही राज्य के सभी नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में खेल क्लब का गठन किया जाएगा। पटना में बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर लोक निजी भागीदारी के द्वारा बहुमंजिली इमारतें बनेंगी। 2024-25 में फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को डीजल अनुदान देने के लिए 150 करोड़ स्वीकृत किया गया। कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र को लेकर सहमति बन गई है। इस बार बिहार विधानमंडल का सत्र 22 से 26 जुलाई तक चलने की बात कही गई है। इस बार के मॉनसून सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी। वहीं कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में खेल क्लब के गठन को मंजूरी मिल गई है।

जमीन विवाद में पुत्र ने की पिता की हत्या

E. CHAMPARAN : जिले में आपसी विवाद में एक पुत्र पक अपने पिता की पीट-पीट कर हत्या कर दी। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शंभू चक पंचायत के वार्ड नंबर 10 राई टोला की है। बताया जा रहा है कि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शम्भूचक पंचायत के वार्ड नंबर-10 राइटोला गांव निवासी अरुण सिंह और उसके छोटे भाई रत्नेश सिंह के बीच घरारी के जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था, जिसको लेकर फिर से दोनो के बीच विवाद शुरू हुआ तो पिता वशिष्ठ सिंह (70 साल) बीच में आ गए।फिर दोनों के बीच पहले गाली- गलौज फिर मारपीट शुरू हो गया। इसी दौरान अरुण सिंह ने अपने बेटे विवेक कुमार, पत्नी अर्चना देवी और एक पट्टीदार संजय सिंह के साथ मिल कर अपने वृद्ध पिता वशिष्ठ सिंह की पिटाई शुरू कर दी,जिससे वशिष्ठ सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद अरुण सिंह अपनी पत्नी और बेटा के साथ फरार है।

नवादा में एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मिलीं लाशें

घटनास्थल पर जुटी ग्रामीणों की भीड़।

- रुपया के लिए हत्या का लगाया जा रहा कयास
- कुछ दिन पहले बेची थी 15 लाख की कीमती जमीन

AGENCY NAWADA : बिहार के नवादा से सनसनीखेज खबर सामने आई है। एक ही परिवार की तीन महिलाओं की संदेहास्पद मौत हो गई है। तीनों के शव घर के अंदर बंद पाए गए। तीनों की मौत कई दिनों पहले हो चुकी थी। इस वजह से लाश खराब हो चुकी हैं। घटना की जानकारी तब मिली जब घर से दुर्गंध निकलने लगा। ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़ा तो सभी अवाक रह गए। घर के अंदर के तीन अलग अलग कमरों में तीनों महिलाओं के शव पड़े थे। घटना जिले के कौआकोल थाना क्षेत्र के भलुआही गांव की है। जानकारी मिलते ही कई गांवों के लोग घटना स्थल पर जुट गए। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक घर में तीन महिलाएं ही रहती थीं। कोई पुरुष सदस्य नहीं है। इधर ग्रामीणों के बीच यह चर्चा के सप्ताह भर पहले घर की महिलाओं ने जमीन बेची थी। बताया जा रहा है कि जमीन बेचने पर उन्हें 15 लाख रुपए दिए गए थे। रुपए के लिए हत्या का लगाया जा रहा कयास लगाए जा रहे हैं।

महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि कई हिस्सों में घुसा बाढ़ का पानी

AGENCY KISHANGUNJ : जिले में बीते तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश से महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। साथ ही डोंक नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसको लेकर सीओ मोहित राज ने भी नदियों का जायजा लिया है। पोठिया प्रखंड क्षेत्र होकर बहने वाली महानंदा व डोंक नदी का जलस्तर पिछले तीन दिनों से बढ़ रहा है। लगातार वर्षा होने के कारण दोनों नदी उफान पर है। महानंदा नदी का जलस्तर बढ़कर 4 सेंटीमीटर हो गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से गोरिहाट, डाक बंगला, कलियागंज आदि स्थानों पर नदी किनारे बसने वाले गिल्हाबाड़ी, बारापोखर, आदिवासी टोला मुस्लिम टोला, बारापोखर प्राथमिक विद्यालय, तैयबपुर, कलियागंज, गोरिहाट, इंदरपुर सहित दर्जनों गांवों में नदी का पानी प्रवेश कर जाता है। फिलहाल, बहादुरगंज के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। नदी की उफान को लेकर लोग इस आशंका को लेकर परेशान हैं, कि यदि रात तक पानी की बढ़ती रफ्तार नहीं रुका तो मुश्किलें बढ़ जायेगी। इसी प्रकार डोंक नदी का भी जल स्तर बढ़ने से लोग बाढ़ की आशंका को लेकर चिंतित हैं। पोठिया के मो. आदिल, बिरजू सहित कई स्थानीय लोगो ने बताया कि गांव में अब तक पानी प्रवेश नहीं किया है। लेकिन, माल मवेशियों को दिक्कत जरूर है। नदियों के उफान से कई मुख्य सड़कों से संपर्क टूटने के कगार पर है। कई डायवर्जन भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे लोगों को काफी परेशानी होगी। मामले पर अंचल अधिकारी मोहित राज ने बताया कि उनके द्वारा विभिन्न बढ़े हुए नदियों का निरीक्षण किया जा रहा है, साथ ही टूटे हुए डायवर्जन वाले जगहों को चिह्नित कर तत्काल प्रभाव से उसे ठीक किया जा रहा है और चलने लायक बनाया जा रहा है।

अमृत भारत ट्रेन की चपेट में आकर बच्चे की मौत

W. CHAMPARAN : रक्सौल-सीतामढ़ी रेलखंड के जयमूर्तिनगर हॉल्ट स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक मासूम की मौत हो गयी। मृतक बनकटवा के अनिल ठाकुर का पुत्र 3 वर्षीय कल्लू कुमार बताया गया है। वहीं उसकी दो बहनें खुशी कुमारी (5) व रुचि कुमारी (4) ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बचीं। तीनों सगे भाई बहन प्लेटफार्म के उत्तरी भाग में मौजूद अपने पिता की दुकान से लौट रहे थे। लौटने के क्रम में दो बहनें ट्रैक पार कर गयी, जबकि छोटा भाई ट्रैक पार कर ही आ रहा थी कि रक्सौल की ओर से आर रही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया,जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी। उल्लेखनीय है कि मृतक अपने माता पिता का एकलौता पुत्र था। उसकी मां गूंगी है वही उसके पिता भी दिव्यांग हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख पुकार मची है, परिजनो का रो रोकर बुरा हाल बना हुआ है।

कटिहार में मशरूम के छाते से जीविका दीदी को मिल रही है आर्थिक सुरक्षा

AGENCY KATIHAR : एडी खुशबू, कोढ़ा. बदलाव के दौर में महिलाएं स्वावलंबी व आत्मनिर्भर होते हुए जिंदगी के हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी के झंडा लहरा रही हैं। खेती के क्षेत्र में भी महिलाएं परिश्रम कर बेहतर पैदावार ले रही हैं। कृषि कार्य में भी अपना लोहा मनवा रही हैं। इसी कड़ी में कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र की बिशनपुर पंचायत के बिशनपुर ग्राम की जीविका दीदी राजकुमारी देवी मशरूम की खेती कर मिसाल कायम कर रही हैं। पिछले दो वर्ष से मशरूम की बेहतर खेती कर घर की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान कर रही हैं। अपने परिवार के जीवन में खुशियों के रंग भर रही हैं। जीविका राजकुमारी देवी मशरूम की खेती कर प्रत्येक वर्ष लाखों रुपये कमा रही हैं। प्रखंड क्षेत्र की विशनपुर पंचायत निवासी जीविका दीदी ने सुखद भविष्य की आस में मशरूम की खेती शुरू की। अब लाभ भी ले रही हैं। केला की खेती के लिए प्रसिद्ध कोढ़ा प्रखंड में महज 10 वर्ष पूर्व पनामा विल्ट नामक रोग लगने के कारण प्रखंड क्षेत्र में केला खेती का रकबा घट गया। इसके बाद लोग मक्का खेती के तरफ मुड़े। अब बिशनपुर की जीविका दीदी ने मशरूम की खेती की शुरूआत की है। उन्हें लगा कि मशरूम की खेती कर अच्छे मुनाफे के साथ आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ा जा सकता है। राजकुमारी देवी ने बताया कि प्रथम वर्ष जब करीब तीन चार कट्ठे जमीन में मशरूम की खेती शुरू की तो लगभग 40 हजार रुपये खर्च आया। एक वर्ष में करीब दो लाख 50 हजार रुपये की मशरूम का बिक्री हुई। मशरूम में 20 से 25 दिन में फसल निकलनी शुरू हो जाती है। हालांकि मशरूम की खेती में मौसम का भी प्रतिकूल असर पड़ताहै। ठंड के मौसम में फसल बेहतर परिणाम देता है। जबकि गर्मी में उपज में कमी आ जाती है। राजकुमारी देवी ने आगे बताया कि सर्वप्रथम जीविका समूह से मैं जुड़ी। जुड़ने के बाद जीविका द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर मशरूम की खेती की शुरूआत की। मशरूम की खेती करने के दौरान कुछ समझ में नहीं आ रहा था।

अंगिका को आठवीं सूची में शामिल करने को ले प्रदर्शन

AGENCY BHAGALPUR : अंगजनपद की लोक भाषा अंगिका अपने परिचय का मोहताज होते दिख रही है। अंगिका भाषा सदैव उपेक्षा का शिकार रही, जिस तरह मैथिली, बांग्ला, भोजपुरी भाषा के अलावा कई भाषा पर सरकार का विशेष ध्यान है। उसके हिसाब से अंगिका भाषा पर इतना विचार नहीं किया जा रहा। जिसके चलते अंगिका भाषा अपेक्षित होती चली जा रही है। अंगिका भाषा की संवैधानिक मान्यता को लेकर गुरुवार को अंग क्षेत्र के लोगों ने एक विशाल धरना का आयोजन किया। साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार के समक्ष कई मांगों को भी रखा, जिसमें अंगिका भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल करने, भागलपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में उद्घोषणा अंगिका में भी की जाए, अंगिका भाषा से नौकरी दी जाए, विश्वविद्यालय में अंगिका पर विशेष कार्य हो, अंगिका भाषा पर सिनेमा टीवी सीरियल वेब सीरीज बनाई जाए आदि शामिल हैं। लोगों ने भागवत झा आजाद अंगिका केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की भी बात कही। साथ ही साथ अंगिका को जल्द से जल्द दूसरी राजभाषा घोषित करने की भी मांग सरकार के समक्ष रखी।

यादव, मुसलमान और कुशवाहा का..., बोल कर बुरे फंसे सांसद देवेश चंद्र ठाकुर

AGENCY MUZAFFARPUR : सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद अपने उस बयान को लेकर कानूनी पचड़े में घिर गए हैं जिसमें उन्होंने यादव, मुस्लमान और कुशवाहा का काम नहीं करने की बात कही थी। उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में नालिसी दायर की गई है। अहियापुर के दिलीप कुमार कुशवाहा ने कोर्ट में परिवाद दायर कर इसे समाज में अस्थिरता फैलाने वाला वक्तव्य बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि इस बयान से लाखों लोगो को मानसिक आघात लगा है। कोर्ट ने परिवाद को ग्रहण करने के बिंदु पर सुनवाई के लिए रखा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर सोशल मीडिया भी जोरदार

सीतामढ़ी एमपी के विरुद्ध मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद

बहस छिड़ी है। दाखिल परिवाद में बताया है कि सांसद निर्वाचित होने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी के परिहार और डुमरा में खुले मंच से अपना वक्तव्य दिया है। इसमें कहा कि सांसद चुनने के बाद जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के साथ पुरे देश का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन उन्होंने कहा कि जिन यादव, मुसलमान और कुशवाहा को काम पड़ेगा वह लालू यादव के पास जायेंगे। उनके इस वक्तव को सुनने के बाद परिवादी, गवाह और लाखों लोग आहत हुए है। धारा आपीसी की धारा 501 और 505 के तहत परिवाद दाखिल की गई है। यह मामला देवेश चंद्र ठाकुर के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने मुसलमान, यादव और कुशवाहा समाज पर उन्हें वोट नहीं देने का आरोप लगाया था। सीतामढ़ी लोकसभा सीट से देवेश चंद्र ठाकुर ने 2024 के चुनाव में 50 हजार से ज्यादा वोटों से राजद के उम्मीदवार अर्जुन राय परास्त किया। 2019 में इसी सीट पर जदयू के सुनील कुमार पिंटू 2 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे।

सीतामढ़ी में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या

- घटना महिंदवारा थाना के मौना गांव की, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस

AGENCY SITAMARHI : सीतामढ़ी जिले के महिंद्रावारा में एक भाजपा नेता की बीती रात जमीनी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। घटना जिले के महिंदवारा थाना क्षेत्र के मौना गांव की है। जहां बुधवार की रात अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मौना गांव निवासी भरत साह के करीब 35 वर्षीय पुत्र राजेश कुमार साह के रूप में की गयी है। बताया जाता है कि राजेश भाजपा युवा मोर्चा के कोआही मंडल का पूर्व में अध्यक्ष रह चुका है। फिलहाल वह अपने दरवाजे पर ही सीएसपी व कैफे का संचालन करता था। बुधवार की रात वह अपने दरवाजे पर ही कैफे में बैठा हुआ था, इसी बीच बाइक सवार तीन सशस्त्र अज्ञात अपराधकर्मी वहां पहुंचे तथा राजेश के उपर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग दौर पड़े। लोगों को आते देख अपराधकर्मी बाइक पर सवार हो फरार हो गये। जख्मी राजेश को परिजनों ने आनन फानन में एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया, जहां इलाज के क्रम उसने दम तोड़ दिया।

गर्मी से मिली निजात, कैमूर छोड़ पूरे बिहार में हुई बारिश, पूर्णिया में झमाझम बरसे बादल

किशनगंज के रास्ते मानसून की हुई एंट्री

AGENCY PATNA : आखिरकार बिहारवासियों को भीषण गर्मी से निजात मिल गई। गुरूवार तड़के कैमूर को छोड़कर पूरे बिहार में बारिश हुई। जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश पूर्णिया में 126 मिमी, सुपौल में 94 मिमी, किशनगंज 82.4, पूर्वी चंपारण 74, अररिया, 72, सीवान, 66.2, जुमई 60, गोपालगंज 57, कटिहार 56, मिमी बारिश इन जिलों के अलग-अलग हिस्सों में हुई। वहीं अगर बात तापमान की करें तो आज सबसे ज्यादा पारा 42.8 डिग्री औरंगाबाद का रहा, वहीं सबसे कम तापमान 21 डिग्री मोतिहारी का रहा। पूरे प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी हुई है। बिहार में मानसून किशनगंज, पूर्णिया के रास्ते प्रवेश कर गया है। मौसम विभाग के निदेशक सुनील नारायण थुल ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार के लगभग 10 जिलों में मानसून प्रवेश कर गया है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। आपको बता दें इससे पहले मौसम विभाग ने अररिया, किशनगंज, सुपौल, कटिहार और पूर्णिया में 20 और 21 जून को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। जबकि 22 जून को इन जिलों के अलावा सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में एक दो स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। राज्य के अन्य जिलों में विशेषकर उत्तर बिहार में 21 जून से 23 जून के बीच गरज तड़क के साथ बारिश के आसार हैं। पिछले 18 दिनों से पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर इस्लामपुर में अटके मानसून करंट के प्रसार की परिस्थितियां अब तेजी से तैयार होने लगी हैं। इसके मुताबिक 21 से 22 जून तक बिहार में किशनगंज-पूर्णिया के रास्ते मानसून की दस्तक हो सकती है। मानसून के आगमन के साथ ही तापमान में चार डिग्री कमी आ सकती है। इधर मानसून के आगमन की देरी से बिहार में 70 प्रतिशत तक बारिश की कमी हो गई है।

पुलिस हाजत में युवक की मौत पर बवाल, ग्रामीणों का थाना पर हंगामा

मौत की खबर के बाद थाना परिसर में जुटी ग्रामीणों की भीड़ ।

AGENCY MOTIHARI : बिहार में एक बार फिर पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर बवाल का मामला सामने आया है। घटना पूर्व चंपारण के झड़ोखर थाने की है। युवक बाइक की चोरी के आरोप में में झरोखर थाने के हाजत में बंद था। उसकी पहचान 30 वर्षीय नन्हक राय के रूप में की गई है। संदेहास्पद स्थिति में गुरुवार की सुबह हाजत में उसकी मौत हो गयी। पुलिस मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है जबकि परिजनों का कहना है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। पुलिस पर आरोप लगा कर परिजनों ने थाने पर और अस्पताल में बवाल किया। इस मामले मे सिकरहना डीएसपी अशोक कुमार ने नन्हक राय को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। उसने हाजत में गले में फंदा डाल आत्महत्या का प्रयास किया था। पुलिस के द्वारा आनन फानन में उसे घोड़ासहन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन मृतक के परिजनों ने इस बात से साफ साफ इनकार किया है। उन लोगों ने ने पीट पीट कर मार डालने का आरोप थानाध्यक्ष पर लगाते हुए झरोखर थाने पर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने का विरोध करते हुए घोड़ासहन के अस्पताल में भी हंगामा किया। मौके पर मौजूद डीएसपी अशोक कुमार तथा छौड़ा दानों पुलिस निरीक्षक धनंजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल के द्वारा सख्ती बरतते हुए सब को शांत करवा दिया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा झरोखर थाने का अब भी घेराव किया जा रहा है। डीएसपी के नेतृत्व में आसपास के सभी थानों के पुलिस अधिकारी और सशस्त्र बल फिलहाल झरोखर में कैंप कर रहे हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में जुटे हैं।

पं. माधवराव सप्रेः हिंदी के विस्मृत महानायक

पंडित माधवराव सप्रे, हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य में लगभग भुला दिए गए महानायक हैं। भारतबोध और भारतीयता के सबसे प्रखर प्रवक्ता स्प्रे हमारे स्व को जगाने वाले लेखक हैं। हिन्दी नवजागरण के अग्रदूत माधवराव सप्रे को याद करना उस परंपरा को याद करना है, जिसने देश में न सिर्फ भारतीयता की अलख जगाई वरन हिन्दी समाज को आंदोलित भी किया। उनके हिस्से इस बात का यश है कि उन्होंने मराठीभाषी होते हुए भी हिन्दी की निंरतर सेवा की। अपने लेखन, अनुवाद, संपादन और सामाजिक सक्रियता से समाज का प्रबोधन किया। 19 जून,1871 को मध्य प्रदेश के एक जिले दमोह के पथरिया में जन्मे सप्रे जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। आज के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तीन राज्य उनकी पत्रकारीय और साहित्यिक यात्रा के केंद्र रहे। छत्तीसगढ़ मित्र, हिन्दी केसरी के माध्यम से पत्रकारिता में किया गया उनका कार्य अविस्मरणीय है। उनकी देशज चेतना, भारत प्रेम, जनता के दर्द की गहरी समझ उन्हें बड़ा बनाती है। राष्ट्रोत्थान के लिए तिलक जी के द्वारा चलाए जा रहे अभियान का लोकव्यापीकरण करते हुए वे एक ऐसे संचारक रूप में आते हैं, जिसने अपनी जिंदगी राष्ट्र को समर्पित कर दी। सप्रे जी की बहुमुखी प्रतिभा के बहुत सारे आयाम और भूमिकाएं थीं। वे हर भूमिका में पूर्ण थे। कहीं कोई अधूरापन नहीं, कच्चापन नहीं। सप्रे जी को लंबी आयु नहीं मिली। सिर्फ 54 साल जिए, किंतु जिस तरह उन्होंने अनेक सामाजिक संस्थाओं की स्थापना की, पत्र-पत्रिकाएं संपादित कीं, अनुवाद किया, अनेक नवयुवकों को प्रेरित कर देश के विविध क्षेत्रों में सक्रिय किया वह विलक्षण है। 26 वर्षों की उनकी पत्रकारिता और साहित्य सेवा ने मानक रचे। पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंददास, गांधीवादी चिंतक सुंदरलाल शर्मा, द्वारिका प्रसाद मिश्र, लक्ष्मीधर वाजपेयी,माखनलाल चतुर्वेदी, लल्ली प्रसाद पाण्डेय,मावली प्रसाद श्रीवास्तव सहित अनेक हिन्दी सेवियों को उन्होंने प्रेरित और प्रोत्साहित किया। जबलपुर की फिजाओं में आज भी यह बात गूंजती है कि इस शहर को संस्कारधानी बनाने में सप्रे जी ने एक अनुकूल वातावरण बनाया। जिसके चलते जबलपुर साहित्य, पत्रकारिता और संस्कृति का केंद्र बन सका। 1920 में उन्होंने जबलपुर में हिन्दी मंदिर की स्थापना की, जिसका इस क्षेत्र में सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ाने में अनूठा योगदान है। हिन्दी पत्रकारिता में उनका गौरवपूर्ण स्थान है। सन् 1900 के जनवरी महीने में उन्होंने छ्त्तीसगढ़ के छोटे से कस्बे पेंड्रा से 'छत्तीसढ़ मित्र' का प्रकाशन प्रारंभ किया। दिसंबर,1902 तक इसका प्रकाशन मासिक के रुप में होता रहा। इसे प्रारंभ करते हुए उसके पहले अंक में उन्होंने लिखा-''संप्रति छत्तीसगढ़ विभाग को छोड़ एक भी प्रांत ऐसा नहीं है, जहां दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक पत्र प्रकाशित न होता हो। आजकल भाषा में बहुत सा कूड़ा-करकट जमा हो रहा है वह न होने पावे इसलिए प्रकाशित ग्रंथों पर प्रसिध्द मार्मिक विद्वानों के द्वारा समालोचना भी करे।'' यह बात बताती है कि भाषा के स्वरूप और विकास को लेकर वे कितने चिंतित थे। साथ ही हिन्दी भाषा को वे एक समर्थ भाषा के रुप में विकसित करना चाहते थे, ताकि वह समाज जीवन के सभी अनुशासनों पर सार्थक अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो सके। कुछ पत्र लंबे समय तक चलते हैं पर पहचान नहीं बना पाते । 'छत्तीसगढ़ मित्र' की प्रकाशन अवधि हालांकि बहुत कम है ,किंतु इस समय में भी उसने गुणवत्तापूर्ण, विविधतापूर्ण सामग्री को प्रकाशित कर आदर्श संपादकीय,लेखकीय परंपरा को निर्मित करने में मदद की, वह भी एक ऐसे इलाके से जहां इसकी कोई पूर्व परंपरा नहीं थी। बत्तीस पेज की यह पत्रिका समग्रता के साथ आती है, जिसमें कथा, कहानी, समाचार, प्रार्थना, पत्र, नीति विषयक बातें, उपदेशपरक और व्यंग्य परक लेख, समीक्षाएं प्रकाशित होती थीं। सप्रे ने जी ने संपादकीय तो नहीं लिखे किंतु समाचारों के अंत में सुझाव के रुप में एक वाक्य जाता था। एक साल के बाद इसका स्वरूप पूरी तरह साहित्यिक हो गया और समाचारों प्रकाशन इसमें बंद हो गया। इस मासिक पत्र के प्रकाशक अधिवक्ता वामनराव लाखे थे और सप्रे जी के साथ संपादक के रूप में रामराव चिंचोलकर का नाम भी जाता था। इस पत्र की गुणवत्ता और सामग्री को बहुत सराहना मिली। उस समय के प्रमुख अखबार भारत मित्र(कोलकाता) ने लिखा कि झ''इस पत्र के संपादक एक महाराष्ट्रीयन हैं तथापि हिन्दी बहुत शुद्ध लिखते हैं। लेख भी बहुत अच्छे होते हैं। हम आशा करते हैं कि मध्य प्रदेश वासी इस पत्र को बनाए रखने की चेष्ठा करेंगें।'' अभावों के चलते यह यात्रा बंद हो गयी और सप्रे जी नागपुर के देशसेवक प्रेस में काम करने लगे। वहीं पर सप्रे जी ने जीवन के कठिन संघर्षों के बीच 1905 में हिन्दी ग्रंथ प्रकाशन-मंडली की स्थापना की। इसके माध्यम से हिन्दी भाषा के विकास और उत्थान तथा अच्छे प्रकाशनों का लक्ष्य था। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के कार्यों से प्रभावित सप्रे जी ने 13 अप्रैल,1907 से 'हिन्दी केसरी' का प्रकाशन आरंभ किया। भारतबोध की भावना भरने, लोकमान्य तिलक के आदर्शों पर चलते हुए इस पत्र ने समाज जीवन में बहुत खास जगह बना ली। राष्ट्रीय जागरण की भावना से ओतप्रोत इस पत्र में देश के जाने-माने पत्रकारों का सहयोग रहा। बताते हैं कि मुंबई के प्रख्यात पत्रकार जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, सप्रे जी के आग्रह पर उस समय के प्रमुख अखबार 'श्रीवेंकेटेश्वर समाचार' के संपादक की नियमित नौकरी छोड़कर नागपुर चले आए और 'हिन्दी केसरी' से जुडे।

भीषण गर्मी में मजदूरों की फिक्र भी जरूरी

ANALYSIS

प्रियंका सौरभ

साफ पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं से वंचित झुग्गियों के घर टिन या तारपोलिन की छतों के नीचे तपती गर्मी झेलते हैं। चूंकि ये काम ज्यादातर खुले वातावरण में ही करने पड़ते हैं, तो भीषण गर्मी में इन लोगों के बीमार पड़ने का खतरा भी ज्यादा रहता है। इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए चल रहे प्रयासों और नई पहलों को विकसित किया जाना चाहिए, जिससे उनकी भलाई और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भारत में हाल ही में कई क्षेत्रों में तापमान को 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच दआ, जिससे डेली वर्कर्स, खासकर डिलीवरी कर्मियों और दिहाड़ीदार मजदूरों के सामने आने वाली चुनौतियों में इजाफा हुआ है। इस प्रकार के खुला काम करने वाले इस दौरान श्रमिक पर्याप्त स्वास्थ्य-सुरक्षा उपायों और न्यूनतम ब्रेक के बिना चरम मौसम की स्थिति के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण गर्मी से थकावट और निर्जलीकरण से पीड़ित हुए हैं, जिससे पता नहीं कितनों की जान असमय गई है। दिहाड़ीदार मजदूर स्थायी नौकरियों के बजाय अल्पकालिक अनुबंध या फ्रीलांस काम करते है। इस में उबर, स्विगी और जोमैटो जैसे डिजिटल प्लेटफार्म के जरिए अस्थायी, लचीले और प्रोजेक्ट-आधारित काम करने वाले भी शामिल हैं ।

देश में पड़ रही भीषण गर्मी से डेली वर्कर्स, विशेषकर डिलीवरी कर्मियों, ईंट-भट्ठों पर काम करने वालों और दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए कामकाजी परिस्थितियां गंभीर हो गई हैं। भीषण गर्मी ने खुला काम करने वाले वर्कर्स के लिए कठोर कार्य स्थितियों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया है। इस भीषण गर्मी में कई लोग खुले वातावरण और गर्म मौसम में काम करने के लिए मजबूर हैं। अगर वे काम नहीं करेंगे, तो उनके घर खाना नहीं पकेगा। यह उनके जीवन-यापन का एकमात्र साधन है। ऐसे लोग अकसर काफी गरीबी में जीने के लिए विवश होते हैं। साफ पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं से वंचित झुग्गियों के घर टिन या तारपोलिन की छतों के नीचे तपती गर्मी झेलते हैं। चूंकि ये काम ज्यादातर खुले वातावरण में ही करने पड़ते हैं, तो भीषण गर्मी में इन लोगों के बीमार पड़ने का खतरा भी ज्यादा रहता है। इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए चल रहे प्रयासों और नई पहलों को विकसित किया जाना चाहिए, जिससे उनकी भलाई और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भारत में हाल ही में कई क्षेत्रों में तापमान को 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच दआ, जिससे डेली वर्कर्स, खासकर डिलीवरी कर्मियों और दिहाड़ीदार मजदूरों के सामने आने वाली चुनौतियों में इजाफा हुआ है। इस प्रकार के खुला काम करने वाले इस दौरान श्रमिक पर्याप्त स्वास्थ्य-सुरक्षा उपायों और न्यूनतम ब्रेक के बिना चरम मौसम की स्थिति के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण गर्मी से थकावट और निर्जलीकरण से पीड़ित हुए हैं, जिससे पता नहीं कितनों की जान असमय गई है। दिहाड़ीदार मजदूर स्थायी नौकरियों

के बजाय अल्पकालिक अनुबंध या फ्रीलांस काम करते है। इस में उबर, स्विगी और जोमैटो जैसे डिजिटल प्लेटफार्म के जरिए अस्थायी, लचीले और प्रोजेक्ट-आधारित काम करने वाले भी शामिल हैं । ये नौकरियां लचीलापन प्रदान करती हैं , लेकिन इन लोगों को पारंपरिक रोजगार से जुड़े लाभों और सुरक्षाओं का अभाव होता है। अगर वे काम नहीं करेंगे, तो उनके घर खाना नहीं पकेगा। यह उनके जीवन-यापन का एकमात्र साधन है। ऐसे लोग अकसर काफी गरीबी में जीने के लिए विवश होते हैं। साफ पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं से वंचित झुग्गियों के घर टिन या तारपोलिन की छतों के नीचे तपती गर्मी झेलते हैं। चूंकि ये काम ज्यादातर खुले वातावरण में ही करने पड़ते हैं, तो भीषण गर्मी में इन लोगों के बीमार पड़ने का खतरा भी ज्यादा रहता है। ऐसे श्रमिकों को अक्सर स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति लाभ या सवेतन अवकाश की सुविधा नहीं मिलती, जिससे बीमारी या चोट के समय वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। श्रमिकों की आय अत्यधिक परिवर्तनशील और अप्रत्याशित होती है, जिससे वित्तीय योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। श्रमिकों को कठोर कार्य स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें चरम मौसम का सामना करना भी शामिल हैइनको आमतौर पर स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में वगीर्कृत किया जाता है, जिससे उन्हें कई श्रम सुरक्षा से वंचित रखा जाता है जो औपचारिक कर्मचारियों को प्राप्त होती हैं। ऐसे विपरीतस मय में श्रमिकों को संरक्षण और निष्पक्ष व्यवहार के लिए आवश्यक प्रबंध करने की जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ के लिए वर्कर्स को स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करनाबहुत जरूरी है। उदाहरण के लिएः राजस्थान प्लेटफार्म आधारित वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 का उद्देश्य वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जो अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मिसाल कायम करेगा। वर्कर्स के लिए एक न्यूनतम वेतन नीति स्थापित करना ताकि एक स्थिर आय और न्यूनतम भुगतान किए गए घंटे या कमाई सुनिश्चित हो सके। जैसे सिंगापुर के प्रस्तावित विधायी परिवर्तनों में श्रमिकों के लिए कार्य-चोट बीमा और पेंशन कवरेज का विस्तार करना शामिल है, जिसका भारत भी अनुकरण कर सकता है। वर्कर्स को कर्मचारी के रूप में मान्यता देना या उन्हें समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना समय की मांग है। इसमें संगठित होने और यूनियन बनाने का अधिकार शामिल है। उदाहरण के लिएः यूके और कैलिफोर्निया में कानूनी लड़ाइयों के कारण वर्कर्स को कर्मचारी के रूप में मान्यता मिली है, जो न्यूनतम वेतन और अन्य लाभों के हकदार हैं । सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए जिसमें सुरक्षात्मक गियर, नियमित ब्रेक और चरम मौसम से श्रमिकों की सुरक्षा के उपाय शामिल हैं। उदाहरण के लिएः निष्पक्ष व्यवहार और शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं , लेकिन इनको मजबूत करने की आवश्यकता है। स्वतंत्र श्रम न्यायालयों की स्थापना करना और यह सुनिश्चित करना कि उनमें मामलों को तुरंत और निष्पक्ष रूप से निपटाने की क्षमता हो। उदाहरण के लिएः कतर की श्रम विवाद समितियों ने न्याय तक पहुंच में सुधार किया है , लेकिन देरी और प्रवर्तन संबंधी मुद्दे बने हुए हैं, जिसके लिए और सुधार की आवश्यकता है। वर्कर्स की रोजगार क्षमता और आय क्षमता को बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना भी आवश्यक है। इसमें वित्तीय साक्षरता और डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण शामिल हो। उदाहरण के लिए स्किल इंडिया जैसी सरकारी पहलों का विस्तार करके वर्कर्स को विशेष रूप से लक्षित किया जा सकता है , ताकि उन्हें प्रासंगिक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। कल्याणकारी योजनाओं के पंजीकरण और पहुंच को सरल बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग कर सेवा वितरण में सुधार के लिए वर्कर डेटा को राष्ट्रीय श्रम डेटाबेस में एकीकृत करना श्रमिकों के लिए फायदेमंद स्कीम बनाने में सहायक होगा। उदाहरण के लिएः भारत का ई-श्रम पोर्टल, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है, वर्कर्स को शामिल करने के लिए इसका लाभ उठाया जा सकता है , ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें समय पर लाभ मिले। भारत में वर्कर्स के अधिकारों की रक्षा और उनके साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और अच्छी तरह से लागू किए गए उपायों की आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा, कानूनी मान्यता, बेहतर कार्य परिस्थितियां, न्याय तक पहुंच, प्रशिक्षण और बेहतर डिजिटल बुनियादी ढांचा एक निष्पक्ष श्रमिक अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। कार्यबल के इस बढ़ते हुए हिस्से की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों और नई पहलों को विकसित करना जारी रखना चाहिए, ताकि उनकी भलाई और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार शक के घेरे में!

कुछ दिन पहले केंद्रीय साहित्य अकादमी (अकादेमी) द्वारा 2024 के युवा व बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की सोशल मीडिया पर खबर के बाद बधाइयों के साथ- साथ, जैसे अकादमी पुरस्कारों को लेकर हर साल होता रहा है, कोई न कोई सवाल, विवाद तो उठता ही उठता है, इस बार भी कुमार सुशांत ने प्रविष्टि की अंतिम तिथि, और उसके बाद छपी पुस्तकों पर सवाल उठाते हुए पोस्ट लिखी तो जाहिर है मामला तूल पकड़ना ही था, कई प्रतिक्रियाएं, सवालों के रूप में सामने आ रही हैं। अकादमी के किसी भी नियम में अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किताबों पर विचार के लिए कहीं कोई विशेषाधिकार का जिक्र या प्रावधान नहीं है। नियम -3 के बिन्दु (6) में स्पष्ट लिखा है कि 24 भारतीय भाषाओं में प्राप्त सुयोग्य पुस्तकों की सूची संबद्ध भाषा परामर्श मण्डल के (संयोजक सहित) सभी सदस्यों को इस अनुरोध के साथ भेजी जाएगी कि वे अकादमी द्वारा निर्धारित तिथि तक दो पुस्तकों का अनुमोदित करें। नियम 7 - विविध के पहले पैराग्राफ में यह जरूर लिखा है कि यदि भाषा परामर्श मण्डल के किसी सदस्य या निर्णायक के द्वारा संस्तुति भेजने की समय सीमा की अनदेखी की जाती है तो अकादमी यह मानकर चलेगी कि उसकी कोई संस्तुति नहीं है और तदनुसार अपनी पुरस्कार प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी सिवाय उस विशेष परिस्थिति के जिसमें अकादमी समय- सीमा को बढ़ा पाने की स्थिति में हो तथा वास्तव में उसे बढ़ाती हो। आश्चर्य की बात जिन तीन लोगों के बारे में सवालिया निशान हैं वे तीनों ज्यूरी द्वारा रेकॉमेंडेड हैं यानी तीनों पुस्तकों की पैरवी की गई है। तीन पैरवी वाले लोगों में एक को पुरस्कार दिया गया है। अब ज्यूरी कितनी ईमानदार है यह सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लिस्ट में जितने नाम आए हैं वे सभी ज्यूरी द्वारा रेकॉमेंडेड ही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं रेकॉमेंडेड नाम पर ही केवल विचार हुआ और जो लेखक निर्धारित समय के भीतर अपनी पुस्तक जमा किए उनकी पुस्तक पर (रिकमेंड न होने के कारण) विचार ही नहीं किया गया। लिस्ट में शामिल किस किताब को किस ज्यूरी मेंबर ने रेकॉमेंड किया क्या साहित्य अकादमी यह बतलायेगी ? प्रसिद्ध आलोचक,कवि, लेखक नवनीत पांडेय के अनुसार सवाल यह है कि अगर अकादमी अपनी विज्ञप्ति में घोषित अंतिम तिथि में परिवर्तन नहीं करती है या बिना पब्लिक सूचना तिथि केवल निर्णायक पैनल को ही व्यक्तिशः सूचित कर तिथि बढ़ा देती है तो बात अलग है, बावजूद इसके किसी नियम में यह कहीं लिखा है कि निर्णायक मण्डल या पैनल को अंतिम तिथि के बाद प्राप्त या किसी व्यक्तिगत जानकारी,सोर्स से प्रकाशित किताब को सूची में शामिल कर, करा सकता है। यदि इन नियमों में कोई संशोधन नहीं हुआ है, यही हैं तो इनके प्रावधानों की जानकारी के बावजूद अगर निर्णायक मण्डल, पैनल तिथि के बाद प्राप्त, प्रकाशित किताबों पर विचार कर उसे अंतिम सूची में शामिल कर उन्हें पुरस्कार योग्य पाती है, पुरस्कार घोषित करती है तो अवश्य ही ये प्रतिभाएं अप्रतिम और विलक्षण हैं, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। याद दिला दूं कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार-2024 हेतु आवेदन और प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 थी। साहित्य अकादमी ने पुरस्कार की घोषणा के साथ जिन 12 लेखकों का नाम प्रकाशित किया है उनमें दो लेखकों की पुस्तक आवेदन की तिथि के बाद आई है। पहले लेखक हैं शहादत और दूसरे विहाग वैभव। शहादत की पुस्तक 'कर्फ़्यू की रात' लोकभारती प्रकाशन से 2024 में पब्लिश हुई यानी आवेदन की अंतिम तिथि के 5 महीने बाद और विहाग वैभव की पुस्तक राजकमल प्रकाशन से सितम्बर 2023 में प्रकाशित हुई यानी आवेदन की अंतिम तिथि के एक महीने बाद। पाठक दोनों पुस्तक के प्रकाशन का प्रमाण गूगल में देखें। ऐसी स्थिति में साहित्य अकादमी ने इन दोनों लेखकों की पुस्तकों पर विचार कैसे किया? इन दोनों पुस्तकों का नाम अंतिम सूची में कैसे है? नियमतः तो यह अमान्य और अनैतिक है। इस विषय पर शोध करने के दौरान पाया कि पुरस्कृत लेखक की पुस्तक 30 अगस्त 2023 को प्रकाशित हुई और 31 अगस्त 2023 आवेदन की अंतिम तिथि थी। एक दिन में स्वयं लेखक महोदय पुस्तक प्रकाशक से लेकर साहित्य अकादमी के कार्यालय कैसे पहुंचा दिए? क्योंकि साहित्य अकादमी की प्रेस विज्ञप्ति में साफ-साफ लिखा है कि आवेदक को पुस्तक की दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित जन्म प्रमाण पत्र के साथ जमा करानी होगी। साहित्य अकादमी से अनुरोध है कि इसपर गौर फरमाया जाए और तुरन्त कार्रवाई करते हुए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 की घोषणा वापस ली जाए। नए सिरे से पुरस्कृत युवा की नई घोषणा की जाए। यह अन्य समर्थ युवा लेखकों के साथ ज्यादती है। यह तो बहुत गंभीर मामला है, पारदर्शिता का दावा करने वाली अकादमी के लिए बहुत ही अपमानजनक भी, लेखकों को संज्ञान लेना चाहिए, अकादमी सचिव, अध्यक्ष से जवाब तलब करना चाहिए। सुशांत जी, आपने प्रमाण सहित जो साहित्य अकादमी की पोल खोली है उस पर सभी साहित्यकारों की दृष्टि जानी चाहिए। अब इन पुरस्कारों का कोई मूल्य नहीं रह गया। क्या इनके सदस्य भी प्रायोजित होते हैं और निर्णायक भी। कम से कम साहित्यिक पुरस्कारों को पारदर्शिता अवश्य रखनी चाहिए। उचित लेखन का मूल्यांकन कर-के ही पुरस्कार घोषित होने चाहिए।

Social Media Corner

सच के हक में...

हमारी सरकार देशभर में कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में हमने वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है। इससे यहां के लोगों का जीवन आसान होगा, साथ ही काशी आने वाले तीर्थयात्रियों को भी बहुत सुविधा होगी।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

किसानों के हित और समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार कटिबद्ध रही है। आज केन्द्रीय कैबिनेट ने खरीफ सीजन के 14 मौसमी फसलों पर टरढ बढ़ाने का निर्णय लिया। धान, कपास, मिलेट्स, ऑयल सीड्स और दलहन की फसलों के नए एमएसपी, इन फसलों पर लागत शुल्क से कम से कम डेढ़ गुने अधिक हैं। देश के किसानों के आने वाले कल की अनवरत चिंता करने के लिए मोदी जी का आभार।

(गृह मंत्री अमित शाह का 'एक्स' पर पोस्ट)

धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मानवीय संवेदनाएं दम तोड़ रहीं हैं। मरीज नग्न अवस्था में फर्श पर ईलाज कराने को मजबूर हैं। ना तो शरीर पर कपड़े हैं, ना सोने के लिए कोई बेड... अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य मंत्री बदहाली की जिम्मेवारी लेने की बजाय पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डीसी धनबाद संदर्भ में संज्ञान लेकर कारवाई करते हुए मरीजों को समुचित ईलाज मुहैया कराने की व्यवस्था करें।

(पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

मनोरंजन का बाजार, संस्कृति पर प्रहार

आजकल देश में मनोरंजन का बाजार भारतीय संस्कृति पर तगड़ा प्रहार कर रहा है। धारावाहिकों और मनोरंजन शोज में द्विअर्थी-भद्दे संवाद और दृश्य खुल्लम-खुल्ला सुनाए और दिखाए जा रहे हैं। सिनेमा के परदे पर शीला-मुन्नी जैसे गानों की भरमार है। युवा रास्ते में आती-जाती लड़कियों पर इन गानों के माध्यम से फब्तियां कसते हैं। फिल्म और टेलीविजन ऐसी चीजों की जानकारी देने लगते हैं जिन्हें बच्चे सही अर्थों में जानने के बजाय गलत तरीके से अपनाने लगते हैं। इसी का परिणाम जघन्य यौन अपराध के रूप में बार-बार प्रकट हो रहा है। अश्लीलता परोसे जाने की इस प्रवृत्ति के साथ फूहड़ विज्ञापनों की भरमार ने सुसभ्य समाज की चिंता बढ़ा दी है। इनमें सामान्यतः नारी की फूहड़ छवि प्रस्तुत की जा रही है। इसका विरोध हमेशा शून्य रहा है। तभी तो यह सब धड़ल्ले से चल रहा है। यदि समय रहते इन अश्लील विज्ञापनों, पोस्टरों, पत्रिकाओं व फिल्मी दृश्यों पर लगाम कसने के प्रयास की किसी ने पहल नहीं की तो आने वाले कुछ वर्षों में यह स्थिति और भी असहज हो जाएगी। वासना के विस्फोट की यह चिंगारी भारतीय संस्कृति को तार-तार कर देगी। मनोरंजन के नाम पर फिल्मों में परोसी जा रही अश्लीलता समाज को कहां ले जाएगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। दिल्ली में कुछ समय पहले एक छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की घटना इसकी सबसे भयंकर परिणति कही जा सकती है। इस घटना पर समाजशास्त्री डॉ. विज्ञा तिवारी का कहना है कि आजकल फिल्मों और टेलीविजन का किशोरों और युवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जहां पहले फिल्में सामाजिक और नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाती थीं, आज वह अश्लीलता परोस रही हैं। अफसोस तो इस बात का है कि यह सब कुछ हर किसी के जेहन में भी है मगर इसके विरोध में अपनी आवाज मुखर करने वाला कोई नहीं है। हर कोई जानता है कि ऐसे दृश्यों और संवादों से बच्चों, युवाओं व बुजुर्गों के मन-मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़ता है। हालात इतने विस्फोटक हैं कि किशोरवय की दहलीज पर पांव रखते ही लड़कियां बहक जाती हैं। फूहड़ मेकअप, बदन दिखाऊ पोशाक, लड़कों से दोस्ती इनकी पहचान बन जाती है। सड़कों, स्कूलों और दीगर स्थानों से शुरू यह दोस्ती बेडरूम में जाकर खत्म होती है। स्थिति विस्फोटक होने पर हाथ मलने के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता। हद तो यह है कि ऐसे बच्चों के माता-पिता को कोई आपत्ति नहीं होती। ऐसी सोच रखने वाली नई पीढ़ी व उनके बदलते अभिभावक मॉर्डर्न जमाने की बात कहकर घटिया संस्कृति के अंधेरे में लुप्त होते जा रहे हैं। इसी मनोवृत्ति का ही नतीजा है कि आज देश में चारों तरफ यौन अपराध बढ़ रहे हैं। हद तो यह है कि खूनी रिश्तों की आंखों में भी वहशत समाने लगी है। अब तो लोग परिचित परिवारों की लड़कियों तक को हवस की नजरों से देखने लगे हैं। पिछले दिनों आफताब नामक युवक ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की हत्या कर उसके 35 टुकड़े कर दिए। खुलासा होने पर खूब हंगामा बरपा। समाज के पहरेदारों ने शुचिता की दुहाई दी। नेताओं ने कठोर कानून बनाने के वादे किए। गुजरते दिनों के साथ सब लोग घटना को भूल गए। भारत में सिनेमा को एक समय आदर्श संस्कारों एवं प्रेरणा का मुख्य स्रोत माना जाता था। रामायण, महाभारत जैसे धारावाहिक व राजा हरिश्चंद्र, संतोषी माता जैसी फिल्में देखने के लिए लोग बेताब रहते थे। रामायण और महाभारत के प्रसारण समय पर तो सड़कों पर कर्फ्यू जैसा नजारा होता था। अब तो सिनेमा सारी हदें पार कर चुका है। फिल्मों के नाम और शहर के चौराहों पर लगे पोस्टर अश्लीलता की सीमाएं पार कर रहे हैं । फिल्में दर्शकों को अपनी आदर्शवादिता की बजाए बेशर्मी से आकर्षित कर रही है।

जलते जंगल, अमंगल के संकेत

दुनिया भर में जंगलों में लगने वाली आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़े कारक के रूप में उभर रहा है। इस वर्ष ब्राजील में अमेजन के वर्षा वनों में 75000 आग की घटनाएं हो चुकी हैं। 2013 से यह संख्या दोगुनी है। इससे 30 लाख जीव प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की 25 प्रतिशत आक्सीजन की जरूरत इन वर्षा वनों से पूरी होती है। मैक्सिको, ग्रीस, अमेरिका सहित दुनिया के अनेक देश दावाग्नि की चपेट में आ चुके हैं। वैसे तो मनुष्य शुरू से ही जंगलों को आग से साफ करके खेती के लिए जमीनें तैयार करता रहा है, किन्तु अब दुनिया की हवा, पानी, और पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने के लिए जितने न्यूनतम क्षेत्र में वन होने चाहिए उतने भी नहीं बचे हैं। इसलिए इस घातक प्रक्रिया पर विराम लगाना अति आवश्यक हो गया है। जंगलों की आग के और भी अनेक नुकसान हैं। आग से फैलने वाला धुआं कार्बनडाई आक्साइड का मुख्य स्रोत होने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करके वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। तापमान वृद्धि से आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस तरह एक घातक दुश्चक्र चल निकला है। वनाग्नि से असंख्य जीव-जंतु नष्ट हो जाते हैं और जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। मिट्टी की ऊपरी परत जल कर खुरखुरी हो जाती है और बारिश में बह कर समुद्र में पहुंच जाती है। वनस्पति का आच्छादन समाप्त हो जाने से भू-जल भरण की प्रक्रिया भी बाधित हो जाती है। वायु प्रदूषित हो जाने के कारण श्वास संबंधी रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। हमारे देश में भी वनाग्नि भयंकर समस्या बनती जा रही है। अकेले हिमाचल प्रदेश में ही इस वर्ष 1900 वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। इससे 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसमें से 2729 हेक्टे।प वृक्षारोपण क्षेत्र है। 374 वन बीट संवेदनशील हैं। इससे 6।61 करोड़ रु। का नुकसान अनुमानित है।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

Opportunity beckons as oil prices soften

AS the new government prepares for its first Budget, it will have an unexpected bonus of global oil markets remaining bearish. It was earlier expected that geopolitical tensions and supply cuts imposed by OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries) Plus would lead to prices firming up, but this has fortunately not happened. Instead, the markets are subdued and the prospect of a Gaza peace agreement as well as slowing world demand has brightened chances of a moderate price scenario continuing for the rest of 2024.The impact of international crude oil prices on the Budget is considerable given the sizeable outgo of foreign exchange on crude oil purchases from abroad. Any reduction in the import bill will bring welcome relief as it helps in bridging the fiscal deficit, which is set to drop to 5.1 per cent in 2024-25. The cost of imports in 2023-24 was estimated at $132.4 billion, slightly lower than the $157.5 billion spent in 2022-23. The shrinkage was largely due to the fall in average oil prices over the past two years, along with some savings on account of buying Russian crude at discounted rates.

The outlook on the oil front had in April been rather dismal. At the time, crude prices had shot up to $90 per barrel for the benchmark Brent crude after having been below $80 since January. The spike occurred due to an escalation of the West Asia crisis, with Iran launching strikes against Israel. Prospects looked dim then for any improvement in view of deepening geopolitical tensions as well as the determination of OPEC Plus to expand production cuts. In the case of the former, the West Asia conflict initially had little impact on oil markets, but the attacks of Yemen-based Houthi rebels on merchant shipping had created ripples. There were also concerns that oil supplies from the region could be affected in case there was a disruption of shipping through the key choke point of the Strait of Hormuz. Any blockage at this point, which accounts for the bulk of crude movement from the region, could have affected India's oil shipments.The situation has eased somewhat in recent months, though merchant shipping going through the Suez Canal is still affected by the depredations of the Houthi rebels supporting the Palestinian cause. For the time being, crude oil movement is continuing without any serious disruption. There is even a glimmer of hope that efforts to reach a pause in the Israel-Hamas conflict could conceivably succeed.

As for OPEC Plus — the cartel which now includes Russia and its allies — it announced voluntary output cuts by members amounting to 2.2 million barrels per day (bpd) last year in a bid to prop up the market. These are being phased out from October this year. This is much earlier than anticipated, thus ensuring that the bearish market trends will continue at least for this year. OPEC Plus, however, retains the mandatory production cuts on members, amounting to 3.66 million bpd up to 2025.The early phaseout decision, along with reports of lower demand in the world's biggest oil importer, China, has strengthened the softening trend in oil prices. Besides, output from non-OPEC producers is rising rapidly and oil inventories are growing further. This includes the US, Canada, Brazil and Guyana.

The result is that oil prices are now in the range of $80-83 per barrel, much lower than earlier anticipated for this year. This is a far cry from last year's prediction by Goldman Sachs that crude would touch $100 by the end of 2024. Current price trends are at variance with earlier forecasts.

For a country like India, this is a huge relief as it imports over 85 per cent of its fuel requirements. The moderation in world prices will ensure that retail prices of products like petrol, diesel and liquefied petroleum gas are contained at existing levels. This is critical to keep inflationary pressures in check as any hike in rates, especially of diesel, has a cascading effect on the economy.

It also must be recognised that petroleum products, being out of the ambit of the Goods and Services Tax (GST), are viewed as the perennial cash cows to shore up state government revenue. The Karnataka government, for instance, has just hiked retail rates of petroleum products, evidently in a bid to boost revenue. A look at the levies on these products by various states is illuminating as it shows high tax levels. Most states impose a value-added tax, while others like Karnataka and Kerala levy sales tax on petrol and diesel.

Beware of China's attempt to assume leadership of Asia-Pacific

For India, the border issue is not just a small part of bilateral military relations. It is the issue that must be resolved for a mutually stable neighbourhood.

AMID concerns over the emergence of a 'rules-broken' international order, replacing the "taken for granted, insufficiently protected and barely modernised rules-based order", the 21st Shangri-La Dialogue, Asia's premier defence summit, was held in Singapore from May 31 to June 2. This annual dialogue brings together defence ministers, senior officials and non-governmental stakeholders to discuss the most pressing challenges in the Asia-Pacific region.

The most-watched participants this year included Philippines President Ferdinand Marcos Jr, who delivered the keynote address, Ukraine President Volodymyr Zelenskyy, US Secretary of Defence Lloyd Austin and the new Defence Minister of China, Admiral Dong Jun, who was appointed in December last year, two months after his predecessor, Gen Li Shangfu, was formally removed.The challenge set forth for the participants by Sir John Chipman, Executive Chairman, International Institute of Strategic Studies — a co-organiser of the event (along with the Singapore Government) — was to find a unique way to build a rules-based order in the Asia-Pacific, amid the complex realities presented by the "interplay of economic statecraft and military strategy". Within the region, there is an ongoing major power contestation and a progressive drift towards a unipolar Asia, oblivious to the reality that power alone cannot decide the rules by which this region is governed or integrated.

Despite the backdrop of a sombre and bleak global and regional security environment, the messaging by the Chinese Defence Minister and his accompanying delegation of Generals was far from 'reassuring'. The glaring contrast between the words and deeds of China was evidenced best by the stark difference between the 'prepared' text of the speech of Admiral Dong and his answers to the questions raised (though most were left unanswered). In addition, members of the Chinese delegation posed provocative questions to prominent speakers. Such coordinated aggressive behaviour, which is not usual in global security dialogues, gave the impression of a 'pack of wolves' being present at Shangri-La, an ironic contrast to this mythical paradise.

The most significant observation was that China seemed to have unilaterally usurped the mantle of leadership of Asia-Pacific, articulating its own concerns, guised as the voice of the region. Admiral Dong said that while different countries had different security interests and goals, China has a 'leadership' role. He also said: "We will not allow anyone to bring geopolitical conflicts or any war, whether hot or cold, to our region." The efforts to displace the US in the Indo-Pacific and create an uncontested, unipolar, Sino-centric Asia and disregard for the centrality of ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) were more than evident.

The harshest words, though, were reserved for Taiwan, termed the "core of China's core interests". Taiwanese President Lai Ching-te, who took over in May, is viewed by China as a 'separatist'. Referring to his statements as a 'betrayal of China and their ancestors', Admiral Dong warned: "They will be nailed to the pillar of shame in history." Reiterating confidence in the People's Liberation Army's capabilities to deter Taiwan independence, he added, "Anyone who dares to separate Taiwan from China will only end up in self-destruction."

The threat of use of force for the capture of Taiwan was not even attempted to be disguised.

The Dragon's belligerent actions in the South China Sea, particularly against the Philippines, were sought to be justified by dubbing all facts, other than the Chinese 'facts', as 'a fabricated and false narrative'. In a severe criticism of the July 2016 award of the Permanent Court of Arbitration in favour of the Philippines, Admiral Dong accused the country of enforcing the 'illegal arbitration award'. He described it as "blackmailing others (China) under the guise of international law". Claiming Beijing's great restraint in the face of infringements and provocations, he warned that it would backfire.

The questions fielded by Admiral Dong's delegation members seemed an extension of the predetermined script. A Major General confronted President Marcos, stating that the Philippines' behaviour in recent times risks ruining the long-earned, long-lasting regional peace and that the Philippines seems to be disregarding the other party's (China's) comfort level. Likewise, a Senior Colonel asked the US Secretary of Defence, "Is the US planning to build a NATO-like alliance system in the Asia-Pacific region?" adding, "The east border expansion of NATO has led to the Ukraine crisis. What implications do you think the strengthening of the US alliance system in Asia-Pacific will have on the region's security and stability?"

Other references to China's disruptive behaviour included Zelenskyy's assertions that Beijing was attempting to sabotage the global peace summit in Switzerland by pressurising countries not to attend. Australian Deputy Prime Minister and Defence Minister Richard Marles raised concerns over China's strategic partnership with Russia, its escalatory behaviour in Asian waters and airspace, incursions against Taiwan, activities against the Philippines in their territorial waters and interference with Australian navy operations in Korea. Through these illustrations, he raised doubts about the role that China intends to play as a global actor.

The unusually belligerent behaviour of the Chinese delegation at the Shangri-La Dialogue does raise concerns over the Dragon's role in the Indo-Pacific, particularly for its neighbours. There are indicators that India must take note of: China's usurping of the leadership role in Asia and attempts to coerce the nations seeking alternatives; an undisguised attempt to create a Sino-centric unipolar Asia and undermining the centrality of ASEAN; the propensity to create fabricated historical narratives and discredit established international institutions like the Permanent Court of Arbitration (established in 1899); and the willingness to use the military for furthering its perceived national interests.The recent Shangri-La Dialogue has highlighted to the world a facet of China's behaviour that India has experienced for a long time. While India maintains the desire to improve its relations with China, the latter must remain mindful of Indian interests and aspirations. For India, the border issue is not just a small part of bilateral military relations, as the Chinese would have us believe. It is the issue that must be resolved for a mutually stable neighbourhood and to ensure that 'Galwans' and 'Yangtses' do not occur again.

Priyanka's poll debut

Congress takes right call to field her from Wayanad

THE Congress' encouraging performance in the recent Lok Sabha elections has prompted former party president Rahul Gandhi to retain the Raebareli Lok Sabha seat in Uttar Pradesh and vacate the one in Wayanad, Kerala. His sister, Priyanka Gandhi Vadra, who was appointed Congress general secretary in 2019, will make her electoral debut in the Wayanad bypoll. The grand old party, which had been reduced to a nonentity in UP, made a comeback in the 2024 parliamentary polls in alliance with the Samajwadi Party (SP). The Congress bagged six seats, including the Gandhi family bastions of Raebareli and Amethi. Priyanka is believed to have played a key role in helping the party win the two prestigious seats, especially Amethi, where Rahul had suffered a shock defeat in 2019.

It is obvious that the Congress wants to build on the gains made in UP and actively assist the Akhilesh Yadav-led SP in dislodging the ruling BJP in the 2027 Assembly elections. Rahul's long-term presence in the state is a must to energise the party rank and file. For the record, the Congress had hit a new low in the 2022 Assembly polls, winning just two seats in the state with the highest political stakes.

Having made major inroads into the South in recent years, the Congress has chosen a presumably easy seat for Priyanka. The Congress-led United Democratic Front swept the Lok Sabha polls in Kerala, winning 18 of the 20 seats, even as the BJP managed to open its account. Both the BJP and the CPI have trained their guns on Rahul, alleging that he did not inform voters of Wayanad beforehand about his plan to contest from two constituencies. Nevertheless, the Congress is confident that the electorate of this constituency will send another Gandhi to Parliament, that too a first-timer, thus strengthening the resurgent Opposition.

Five constraints on revival of Punjab's economy

Public policy should address these constraints for the sake of vibrant, sustainable and inclusive development.

PUNJAB's regression in economic development has continued unabated over the past four decades. The slow-growing economy has serious consequences, such as the fall in the state's ranking in terms of per capita income, high unemployment rate, mass migration, degradation of environmental indicators, agrarian distress and rural suicide. The revival of Punjab's economy has been constrained by several interrelated factors. If the remedial measures are implemented, Punjab can again provide exemplary economic leadership.The first constraint is the production structure. Compared with other performing states of India and the newly industrialising East Asian countries, Punjab's economy is predominantly agricultural both in terms of contribution to the State Domestic Product (SDP) and the share of the workforce deriving its livelihood from farming. The lack of required interlinkage between the sectors prevents the realisation of increasing returns to scale, which is essential for high rates of economic growth.It has been long realised that Punjab's economy is overemphasising agriculture and requires both transformation of the economy and of the farm sector itself. The suggested strategy has received resistance due to overdependence of the Centre on Punjab for the food security of the country. The state government and farmers have attempted diversification of agriculture, but the attempt failed due to reliance on markets which could not absorb the bulk of the new commodities produced in the absence of suitable processing, manufacturing and marketing facilities. The consequence is Punjab's fixation with wheat-paddy rotation, and this has resulted in depletion of groundwater and biomass burning that has generated a further constraint on the sustainability of the Punjab model of economic development. The diversification of Punjab's economy in general and the agriculture sector in particular requires joint efforts of both the state and Union governments. They need to incur one-time 'switching cost' for building new infrastructure and an

enabling environment. The will of the political leadership can overcome this constraint.

The second major constraint is the dysfunctionality of the fiscal policy. It was in the mid-1980s that the revenue-surplus state turned revenue-deficit for the first time. It was the peak period of turmoil in Punjab when most of the organisations and institutions turned non-functional, including the revenue collection machinery, along with the cost of deployment of Central security forces. This was a double burden on the public exchequer and the state government resorted to borrowings. Despite three decades of elected governments without a break, Punjab has gone deeper into debt. The state has accumulated more than Rs 3.51 lakh crore debt (47 per cent of the debt-to-GSDP ratio). Out of the total borrowings, nearly 92 per cent go to service the debt. The committed expenditure exceeds the revenue collected by the state government. Even during the Covid-19 pandemic, it was realised that the Centre could incur higher fiscal deficit but it restricted state government from borrowing. With both restrictive fiscal rules for the state government and dynamic taxes in the hand of the Centre, the former has a limited capacity to raise resources for meeting the needs of development finance. However, the increasing burden of irrational subsidies such as power subsidies has made the fiscal policy dysfunctional.

The third significant constraint is the result of non-economic factors, such as the use of religion for political purposes and the identity issues that disturb the peace that is desirable for long-term private investment in economic activities. This trend of crowding out private investment started in the mid-1980s and has continued till date. The industrial towns of Mandi Gobindgarh and Batala provide evidence of de-industrialisation and pulling out of investment from other industrial centres of Punjab as well. A complementary reason for the deficiency of investment in Punjab is that it has a long border with Pakistan; more often than not, India-Pakistan relations have not been normal, thus disincentivising both domestic and foreign investment in the state. The low gross fixed capital investment of 14 per cent of the GSDP in 2023 sums up the state of affairs.

The fourth major constraining factor is the deficiency of human capital. It is counter-intuitive to the historical fact that Punjabis possess great entrepreneurial and leadership skills. Over the past four decades, both educational and health organisations suffered because of a lack of public investment. The proliferation of profit-oriented but low-quality private educational and health institutions has created a mismatch between the skills in demand in the business sector and low-skilled human capital produced in the state. The migration of relatively better skilled and financial resource-based human capital to Western countries has further perpetuated the deficiency of human resources required for new economic avenues such as information and communication technology.

Last but not least is the dysfunctionality of development and the lack of decentralisation of developmental institutions. The developmental institutional framework is controlled by vested interests — a gridlock of police-bureaucracy-political elites. Policy-making, implementation and evaluation have been concentrated in the hands of groups that have maximised their interests and indulged in mass-scale rent-seeking behaviour, besides promoting a wide variety of mafia, involved in the illicit drug trade and illegal sand mining. This has reduced opportunities for private investment to flourish in Punjab, thus hastening the exodus of precious human and capital resources from the state. Taken together, the five constraints have created a formidable challenge for the revival of Punjab's economy. Public policy should address these constraints for the sake of vibrant, sustainable and inclusive development. A 'business as usual' approach of the state government has made the situation go from bad to worse. Sincere efforts with a holistic public policy approach involving all stakeholders, including the diaspora, can turn the tide.

Inflation targeting to remain work in progress till food prices fall: RBI

For the eighth time in a row, the monetary policy committee of the RBI had on June 7 left the key policy rates unchanged at 6.5% and reiterated its resolve to bring down inflation to the target on a durable period.

MUMBAI. The Reserve Bank on Wednesday in its monthly bulletin said the goal of aligning inflation with the target of 4% will remain a work in progress as long as food prices pressure persists.After the monetary policy committee was set up, the central bank had set an inflation target of 4%, with a leeway of 2 percentage points on either side. This will be up for review in September 2025.The article further said though many central banks have pivoted towards a less restrictive monetary policy stance in response to the fall in inflation in their economies, back home inflation still remains above the targeted level mostly because of the food prices.

Yet, the article notes that "headline inflation is gradually easing, driven by sustained softening of its core component, although the path of disinflation is interrupted by volatile and elevated food prices."For the eighth time in a row, the monetary policy committee of the Reserve Bank had on June 7 left the key policy rates unchanged at 6.5% and reiterated its resolve to bring down inflation to the target on a durable period. The RBI also reiterated its stance of remaining focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target, while supporting growth.This was because the committee found the domestic economic activity remaining resilient and this had even the RBI increasing its GDP forecast by 20 bps to 7.2% for this fiscal."High frequency indicators of activity reflect a sustained momentum in manufacturing and services. The prospects for agriculture are brightening with the expectations of an above-normal SWM and the actual landfall ahead of its schedule. This should augur well for spurring rural demand and, in turn, support private consumption.The MPC also expected investment activity to be bolstered by strong balance sheets of banks and corporates, the policy emphasis on infrastructure spending, and rising business optimism" the article said.

The RBI expects headline inflation to ease from 5.4% in 2023-24 to 4.5% in 2024-25, as it fears that prices will again spiral from the third quarter.

Suzlon Energy shares hit upper circuit, near 52-week high. Will it gain further

New Delhi. Shares of Suzlon Energy Ltd hit an upper circuit on Thursday, continuing their impressive run this year.

The stock surged past the Rs 50 mark in early trading, reaching an upper circuit limit of 5% at Rs 51.34, before partially giving up its gains.

This pushed Suzlon's market capitalisation close to Rs 70,000 crore. Previously, the stock had settled at Rs 48.90 on Wednesday.Suzlon Energy's shares are now approaching their 52-week high of Rs 52.19, achieved on June 4, 2024.The stock has skyrocketed more than 285% from its 52-week low of Rs 13.28, recorded a year ago. So far in 2024, the stock is up nearly 32%, with an over 15% increase in the past month alone.

The surge in Suzlon's shares is supported by favourable government policies promoting renewable energy.

The central government's goal to achieve 500 GW of renewable energy generation by 2030 has boosted market optimism. Reports suggest that India's renewable energy sector is expected to attract over Rs 20.8 lakh crore in investments, positioning Suzlon Energy as a significant player.Recently, Suzlon Energy appointed Khaitan & Co, a prominent Indian law firm, to evaluate its corporate governance practices following the resignation of independent director Marc Desaedeleer.Additionally, Vice Chairman Girish Tanti was elected as Chair of the Global Wind Energy Council India earlier this week. In April, he was elected Vice-Chair of GWEC, highlighting Suzlon's growing influence in the global wind energy sector.

Domestic brokerage firms remain bullish on Suzlon's prospects.ICICI Securities has issued a buy rating with a target price of Rs 60. JM Financial and Nuvama Institutional Equities also recommend buying the stock, with target prices of Rs 54 and Rs 53, respectively.

Sensex, Nifty decline after opening marginally higher; pharma stocks drop

New Delhi. Benchmark stock market indices declined after opening marginally higher on Thursday, triggered by a drop in pharma company stocks.

The S&P BSE Sensex was down 95.17 points at 77,242.42 at 10:10 am, while the NSE Nifty50 fell 22.40 points to 23,493.60.

The other broader market indices were also trading mixed as volatility witnessed a slight uptick.High-weightage Nifty Bank, Nifty Financial Services and Nifty IT fell in early trade, but Nifty Pharma was the top loser.The top five gainers on the Nifty50 were Ultratech Cement, Kotak Mahindra Bank, Hindalco, JSW Steel and Coal India.On the other hand, the top losers were Sun Pharma, HDFC Life, Bajaj Finance, Power Grid and HCLTech.Dr. VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Financial Services, said, "The current distinct trend in the market is the sectoral churn happening somewhat strongly. Huge money is flowing into fairly valued largecaps in banking and profit booking is happening in sectors like capital goods, telecom, metals and FMCG. This churn is likely to continue in the near-term since it is a healthy trend. The overvalued broader market space also is taking a breather."

Group will invest 100 billion dollar in energy transition over next decade: Gautam Adani

MUMBAI. The Adani Group is planning more than $100 billion investments in energy transition projects and towards building manufacturing capabilities to produce all the key components needed for green energy generation, group chairman Gautam Adani said on Wednesday."The the next decade will see us invest more than $100 billion in the energy transition space and further expand our integrated renewable energy value-chain that today already spans manufacturing of every major component required for green energy generation," the billionaire businessman told an infra event organised by Crisil Ratings here.The diversified group that straddles airports, ports, power generation, distribution, city gas distribution, solar panel manufacturing and data centres, among others, will be setting up facilities to manufacture electrolyzers to make green hydrogen, wind power turbines and solar panels apart from already solar parks and wind farms, he said.Adani said these investments will go into establishing solar parks, wind farms, facilities to manufacture electrolyzers, wind power turbines and solar panels.

Underscoring the country's immense potential of energy transition and digital infrastructure, Adani said the country can add a trillion dollars to the GDP every 12 to 18 months, which will put us on track to be a $30-trillion economy by 2050 and this will see the market capitalisation jumping to $40 trillion from around $5.2 trillion now."What this effectively means is that over the next 26 years, we will potentially add $36 trillion to the stock market capitalisation," Adani said.

Ola Electric, Emcure Pharma get Sebi nod for IPOs. Check details

New Delhi. Markets regulator Securities and Exchange Board of India (Sebi) has given the green light to the initial public offerings (IPOs) of Ola Electric and Emcure Pharmaceuticals, setting the stage for their public listings in the near future.Ola Electric, a Bengaluru-based startup focused on electric vehicles (EVs), is poised to become the first EV startup to list on the stock exchanges.The company aims for a valuation of approximately $6 billion through its IPO, which consists of a fresh equity sale of Rs 5,500 crore and an offer-for-sale (OFS) of 95.2 million shares.Founder Bhavish Aggarwal, along with investors SoftBank Vision Fund and Tiger Global, among others, will participate in the OFS. Ola Electric plans to utilize the IPO proceeds for expanding its subsidiary OCT's cell manufacturing capacity, debt repayment, research and product development, inorganic growth initiatives, and general corporate purposes.In the financial year FY23, the company reported a substantial revenue growth to Rs 2,631 crore from Rs 373 crore in FY22, although its losses widened to Rs 1,472 crore.Alongside Ola Electric, Sebi has also approved Emcure Pharmaceuticals' IPO.Based in Pune and backed by Bain Capital, Emcure Pharma will offer fresh equity worth Rs 800 crore and an OFS of 1.36 crore equity shares by promoters and existing shareholders.The proceeds from Emcure Pharma's IPO will primarily be used for debt repayment and general corporate purposes. The company specializes in developing, manufacturing, and marketing pharmaceutical products across various therapeutic areas.The IPOs are being managed by prominent financial institutions including Kotak Mahindra Capital, BofA Securities, Axis Capital, SBI Capital Markets, Citigroup, Goldman Sachs, ICICI Securities, BoB Capital Markets for Ola Electric, and Kotak Mahindra Capital Company, Jefferies India, Axis Capital, and JP Morgan India for Emcure Pharmaceuticals.Ola Electric and Emcure Pharmaceuticals are expected to launch their IPOs in the coming months.

Vodafone sells 18 per cent stake in Indus for Rs 15,300 crore

NEW DELHI. Vodafone Group PLC on Wednesday sold 484.7 million (48.47 crore) shares in Indus Towers Limited, representing 18% of the latter's share capital through an accelerated book-building offer. The placing raised Rs 15,300 crore (€1.7 billion) in gross proceeds which will be used by Vodafone to substantially repay its existing lenders in relation to the outstanding bank borrowings of €1.8 billion secured against Vodafone's Indian assets.

Following the placing, Vodafone now holds 82.5 million (8.25 crore) shares in Indus, equivalent to a 3.1% shareholding. Bharti Airtel on Wednesday said that it has acquired a 1% equity stake in Indus Towers. Besides Airtel, SBI Mutual Fund and Kotak Securities were also among the buyers of Indus Tower shares.JP Morgan in a research note said that as per a security package agreed upon during the merger of erstwhile Bharti Infratel and Indus Towers, Vodafone Plc's 21.05% stake in Indus was the primary pledge by its lenders against the initial $1.4 billion loan Vodafone had

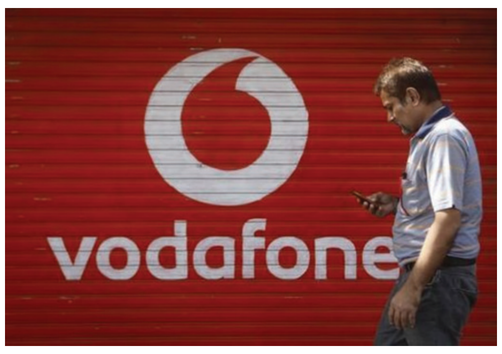

taken in back 2019 to participate in its Indian telecom JV, Vodafone Idea's rights issue.

JP Morgan said that if this share sale goes through, then the proceeds would be first used to repay Vodafone UK's lenders. Indus Towers has a secondary pledge on this Vodafone UK stake with a maximum liability of Rs 4,250 crore.

Vodafone PLC will first clear the dues of the primary pledgers and the residual amount should go towards Indus Towers' dues with a max limit of Rs 42.5 billion (Rs 4,250 crore) directly or indirectly," it said in the note. The stake sale by Vodafone in the Indian tower company is more than what it was expected to offload. The telecom giant on Tuesday was rumoured to sell about 10% stake in Indus for as much as $1.1 billion as a part of its efforts to repay debt.

The stake sale comes months after billionaire Sunil Mittal-led Bharti Airtel denied news reports that it was in talks to buy Vodafone Group's stake in Indus Towers. Bharti Airtel is Indus Towers' biggest shareholder, with a 47.95% stake. With an additional 1%, Airtel's holding has now increased to about 49%.he block deal in Indus Tower triggered a massive spike in volumes and pulled down the shares by .

Sebi asks Religare Enterprises to seek regulatory nod for top investor raising stake

Sebi instructs Religare to seek approvals for Burman stake increase

Directive thwarts Religare's efforts to block Burman family acquisition

Burmans raised Religare stake to 25%, triggering open offer requirement

New Delhi The Securities and Exchange Board of India (Sebi) has instructed Religare Enterprises to apply for necessary approvals to facilitate the Burman family's bid to increase their stake in the financial services company.The directive comes as a setback to Religare's efforts to prevent the acquisition.The Burman family, founders of the consumer goods giant Dabur India, had boosted their stake in Religare to almost 25% in September of last year.This triggered an open offer requirement, allowing them to

purchase additional shares from public shareholders.However, Religare attempted to block this move, alleging that the open offer was fraught with "irregularities and statutory violations," and raising concerns about the acquirers' "fit and proper status."The Burmans aim to acquire an additional 26% of Religare, aiming to strengthen their foothold in the burgeoning financial services sector.

They sought intervention from Sebi due to Religare's lack of cooperation in the process.In an interim order dated June 19, Sebi directed Religare to provide an undertaking by July 12, confirming that it will seek regulatory approvals, including from the central bank, for the open offer.Additionally, Sebi instructed Religare to establish a committee of independent directors, if one is not already in place, although the reason for this directive was not disclosed.Commenting on the development, a Religare spokesperson said, "As per Sebi's advisory the company will apply for the fit and proper status of the acquirers for the open offer to the concerned regulators including the RBI."

Pre-budget meet: Focus on fiscal deficit, job creation

After the meeting, the economists revealed that the government is also focusing on implementing policies aimed at boosting employment growth.

NEW DELHI. During the pre-budget meeting with finance minister Nirmala Sitharaman on Wednesday economists stressed on the importance of further reducing the fiscal deficit in the upcoming budget. After the meeting, the economists revealed that the government is also focusing on implementing policies aimed at boosting employment growth.

"...The government has already stated that the fiscal deficit will be lower in the budget. At the same time, employment remained an important issue of discussion," Ashwani Mahajan, National Co-convener of the Swadeshi Jagaran Manch told reporters after the meeting got over. Nagesh Kumar, Director and CEO of the Institute of Studies in Industrial Development, said upon the need for sustaining the growth of the economy by maintaining Capex (capital expenditure) and by encouraging private sector investment and consumption growth. He said it is important to extend production linked incentive (PLI) scheme to other labour intensive sectors like textiles and labour to give impetus to the manufacturing sector and create jobs.

The meeting was attended by the finance secretary and the secretaries of the Departments of Economic Affairs, revenue, financial services, and corporate affairs, as well as the Chief Economic Adviser of India.Meanwhile, in an another meeting with the revenue secretary, Sanjay Malhotra, industry bodies recommended extension of concessional tax rate of 15% for new domestic manufacturing to give further boost to the government's "Make in India" initiative. They also suggested streamlining of holding period, uniformity in tax rates across various asset classes, a shift in index years for long-term capital gains etc. to mitigate hardships faced by investors.

In addition, the industrial bodies recommended simplification of the overall TDS/TCS compliance and limiting them to two or three rates. They also suggested introduction of new provision allowing companies incurring losses to set it off against previous years' profit and concept of group taxation whereby the financials of companies under the same group could be consolidated for paying taxes in India.

Industrial bodies also recommended that the contributions made and deductions claimed for previous years regarding electoral bonds purchased prior to Supreme Court judgement should remain undisturbed.

34 per cent of biz struggle to find right talent, 1 in 3 grapples with retaining employees

BENGALURU. Nearly 34% of organisations struggle to find the right talent, and almost one in three grapples with retaining existing employees. For employers, one of the top 10 hiring challenges is matching salary expectations, said Michael Page, which provides recruitment services for professionals at middle management to leadership levels.In its Talent Trends 2024 report, it said matching salary expectations proves difficult, while the scarcity of required skills in the talent pool adds complexity. Finding applicants who align with the company culture further intensifies the struggle for businesses.Its data revealed that 94% of respondents are open to exploring different roles in 2024, a decrease of 4% y-o-y. In India, about 94% are open to new job opportunities in 2024. "On the one hand, workers have a growing list of expectations stretching beyond competitive salaries and flexibilityn the other hand, employers face significant pressures in a rapidly evolving business environment, making it harder for both sides to meet in the middle," Nicolas Dumoulin, Senior MD India, Thailand, Philippines & Vietnam, Michael Page, said.Flexibility has become a major point of contention in most parts of India, as employers grapple with implementing hybrid working models and policies that meet both business needs and employee preferences, he added.

India Reports Over 40,000 Suspected Heatstroke Cases This Summer

India heatwave death toll: Temperatures in north India have soared to almost 50 degrees Celsius in one of the longest heatwave spells recorded.

New Delhi/Guwahati: India recorded more than 40,000 suspected heatstroke cases this summer as a prolonged heatwave killed more than 100 people across the country, while parts of its northeast grappled with floods from heavy rain, authorities said.

Billions across Asia are grappling with extreme heat this summer in a trend scientists say has been worsened by human-driven climate change, with temperatures in north India soaring to almost 50 degrees Celsius (122 degrees Fahrenheit) in one of the longest heatwave spells recorded.Birds fell from the skies due to extreme heat and hospitals reported an inflow of heat-affected patients as both day and night time temperatures peaked in recent weeks since the start of summer in March.

The health ministry ordered federal and state institutions to ensure "immediate attention" to patients, while hospitals in the capital Delhi, which is also facing a water shortage, were directed make more beds available.A health ministry official said there were more

than 40,000 suspected heatstroke cases and at least 110 confirmed deaths between March 1 and June 18, when northwest and eastern India recorded twice the usual number of heatwave days.The weather office has forecast above normal temperatures for this month too, as authorities say Indian cities have become "heat traps" due to unbalanced growth.

"During the ongoing heatwave, most bird rescue calls that we receive are due to birds falling from the skies," said Kartick Satyanarayan, co-founder and CEO of non-profit Wildlife SOS."In the past two weeks, Wildlife SOS has been receiving more than 35-40 rescue calls daily, in and around Delhi-National Capital Region. Most of the calls include bird rescue requests."Separately, floods and landslides triggered by incessant rain in the northeastern state of Assam killed at least six people on Tuesday night, officials said."A landslide buried a woman and her three daughters alive," a state disaster management official, Siju Das, said by telephone.

"Their house was on a slope, and they died on the spot around midnight," he said, adding that the bodies were retrieved after a three-hour search operation by rescuers.

"A three-year-old was killed too."In Assam, more than 160,000 people were affected, with waters surpassing the danger level in the Kopili, one of the largest tributaries of the Brahmaputra, which ranks among India's biggest rivers.More than 30 people in the state have died since the end of May in floods and landslides brought by heavy rain, officials said.

I Am Not Secure with Current Kolkata Police Contingent in Raj Bhavan: Bengal Guv Bose

New Delhi: West Bengal Governor CV Ananda Bose on Thursday said that he was apprehending a threat to his security because of the presence of the current contingent of Kolkata Police posted at Raj Bhavan here.

His statement came days after he ordered the police personnel to vacate the Raj Bhavan premises. They, however, are still on duty in the Governor House.“I have reasons to believe that the presence of the current officer-in-charge and his team is a threat to my personal security,” Bose told PTI.“I have informed Bengal CM Mamata Banerjee that I am insecure with Kolkata Police in Raj Bhavan, but there was no action,” he said.

Sources in the Governor House said Bose has complained to the state government that there has been constant snooping by the police personnel posted in Raj Bhavan and he could sense that they were doing it on the insistence of “influencers” from outside.

“The policemen posted here have been snooping on my movements as well as many of my officers. Their acts are with the tacit support of their political masters in government. This is violative of the Constitution,” Bose said.The governor has brought the matter to the notice of Banerjee from time to time but no action has been taken by her. The chief minister also holds the Home portflio.

“None of these can happen without the knowledge of the highest authorities in the police department which is under the Home department,” he asserted.

Bose claimed he had information about the ”misdeeds” of the police contingent posted in Raj Bhavan, under the current officer-in-charge.

Centre Can't Be Mere Spectator, Should Take Lead To Resolve Quota Issue: Sharad Pawar

Pune: NCP (SP) chief Sharad Pawar on Thursday said the Centre cannot be a mere spectator and it should take lead to resolve matters pertaining to the quota demand by the Maratha community and Other Backward Classes (OBCs).Asked about the increasing Maratha-OBC conflict over the reservation issue in Maharashtra, Mr Pawar said there is only one solution that the Centre should take the lead to resolve it and there is a need for amendments in law and the state and Centre's policies.The former Union minister was speaking to reporters at Baramati in Maharashtra's Pune district.

In February this year, the Maharashtra legislature unanimously passed a bill granting a separate 10 per cent reservation in education and jobs to the Maratha community under a separate category.However, the community has been demanding quota under the OBC grouping.

Activist Manoj Jarange has been demanding implementation of the draft notification that recognises Kunbis as “sage soyare” (blood relatives) of Maratha community members and also seeking a law to identify Kunbis as Marathas.

Kunbi, an agrarian group, falls under the OBC category, and Jarange has been demanding that Kunbi certificates be issued to all Marathas, thus making them eligible for quota in government jobs and education.Amid the Maratha reservation demand, two OBC activists have been sitting on a fast in Jalna district, seeking an assurance from the government that the existing Other Backward Classes quota will not be disturbed.

Mr Pawar said, "A change in the policy of the state and centre governments will have to be made." "The governments, specially the Centre, should take the lead in addressing demands of both the communities and ensure the agitation does not cross a limit and that social tension should not take place. The governments cannot be a mere spectator on the issue," he said.

Airlines, Airports Told To Increase Women Staff To 25% Of Workforce

New Delhi: Civil aviation regulator, Directorate General of Civil Aviation (DGCA), has issued an advisory to airports and airlines to increase the number of women employees in their organisations to ensure more gender equality in the aviation sector."With this move, the DGCA aims to increase the number of women in various positions to a desirable representation of 25 per cent by 2025 within the aviation industry in India," the circular states.The circular, titled 'Gender Equality in Civil Aviation Sector", has been issued keeping in mind the principle of gender equality that is enshrined in the Constitution of India and the International Civil Aviation Organisation's (ICAO) vision for promoting equal opportunities in the aviation sector.

The regulator suggested that the airports and airlines should publish the vacant positions on various forums, explicitly encouraging applications from female candidates and drafting positions with precise information on flexible working conditions in their organisations."The stakeholders are advised to promote enhanced representation of women in the aviation workforce, introduce leadership and mentorship programs for women in the organisation, address the issue of stereotypes and gender bias and promote a better work-life balance for women employees," the circular states.It has also directed the stakeholders to improve their policies and practices to ensure gender equality in the workplace.Airlines and Airports have been asked to adopt a zero-tolerance policy towards sexual harassment and formulate HR policies to achieve this goal. They have also been asked to diversify the work profiles of women employees, highlighting women role models and other facilitative steps that promote a gender-inclusive work culture.The organisations should also develop suitable programmes to hire women back if they have taken a break due to parenting needs "or other attendant life cycle issues".

Aviation Watchdog Revises Regulations To Boost Seaplane Operations

New Delhi: In a major leap towards sustainable and safe seaplane operations, the civil aviation regulator, DGCA, has revamped its regulatory provisions.Directorate General of Civil Aviation (DGCA) informed that the pivotal amendments will streamline infrastructure procedures, pilot training requirements, and regulatory compliances, paving the way for seaplane services to reach remote, inaccessible areas."Initially established in 2008, the regulatory framework for seaplane operations was long due for a review. According to a DGCA Working Group recommending rationalization and revision of the said regulatory framework, revised regulations (CAR Section 3 Series C Part IX and CAR Section 7 Series B Part XVI) have been promulgated," an official statement said.

The revised regulations incorporate easier training requirements and simplified approval processes for

undertaking seaplane operations.Pilots with a Commercial Pilot License (CPL) can now qualify as seaplane-rated pilots by undertaking training at any ICAO-recognized training organisation globally. Additionally, new training opportunities for support roles are set to enhance employment potential at seaplane hubs nationwide.

The Ministry of Civil Aviation (MoCA) spearheaded the initiative to promote the seaplane ecosystem, providing guidance and engaging with stakeholders, including DGCA, State Governments, the Airports Authority of India (AAI), Airlines, and Aircraft Manufacturers.These collaborative efforts have ensured that the new regulations address key stakeholder concerns and pave the way for growth in this niche area.With the revised regulatory provisions, seaplane operators can utilize the streamlined procedures and optimized infrastructure requirements, to further extend seaplane services across the country and reach the most remote parts of the country, fostering inclusive and sustainable development. The simplified water aerodrome requirements would also aid in economical and efficient operations while maintaining essential safety standards.

No Relief For Arvind Kejriwal, Delhi Court Reserves Order On Bail Plea In Liquor Policy Scam Case

New Delhi: A Delhi court on Thursday reserved its order on the bail plea of Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party’s (AAP) national convenor Arvind Kejriwal in connection with the money laundering case related to the now-scrapped excise policy.Appearing on behalf of the ED, ASG Raju said that the central agency has documentary evidence showing that part of the alleged proceeds of crime was used to cover the cost of Kejriwal’s stay at the Grand Hyatt Hotel in Goa during the 2022 state elections. This comes a day after a Delhi court extended Kejriwal’s custody till July 3.The ED today said its evidence shows that Rs 1.5 lakh was paid in installments of Rs 50,000 each by Charanpreet Singh to settle the hotel

and banquet charges for Kejriwal’s stay. The ED alleged that Charanpreet, who reportedly managed AAP’s Goa poll funds, received around Rs 45 crore in cash from various “angadiyas” (hawala operators) and was involved in handling cash for the AAP’s Goa election campaign.

The ED also said it has witness statements, including from an individual named Sagar Patel, corroborating the cash payments made to Charanpreet, Prince Kumar and Rajiv Mondkar for the AAP’s Goa election expenses. The agency argued that Kejriwal’s refusal to provide the password to his phone should lead to an adverse inference against him, which is a ground for denying bail even under ordinary bail law.ASG Raju on Wednesday informed the court that the cost of the Delhi chief minister’s stay was covered partly in cash and partly by the admin Department of GNCTD. “It was earlier hushed up but we then discovered that the payment was in cash and the same came through hawala. Charanpreet arranged,” he said.

Delhi Burger King Murder May Be Revenge Killing, Mystery Woman Lured Victim

Delhi Burger King murder: As many as 38 bullets of 3 different makes were fired at Aman Joon inside Burger King outlet at Rajouri Garden Tuesday night

New Delhi: The chilling murder of a 26-year-old man in a shooting spree at a Burger King outlet in west Delhi may have been revenge for a 2020 murder in Haryana, according to reports. Police suspect gang rivalry led to the shocking murder that has raised questions on the law and order situation in the capital. Latest and Breaking News on As many as 38 bullets of three different makes were fired at Aman Joon inside the fast food outlet at Rajouri Garden in west Delhi Tuesday night, the FIR says. The different bullets suggest that more than two weapons were used by the two shooters. Aman's body was found behind the billing counter, indicating that he tried to flee when the killers opened fire. The killers, the Burger King staff have said, were in the 25-30 years age group.

The Mystery Woman

The staff have said Aman came to the eatery to meet a woman. She left the spot soon after the attack, possibly with the dead man's phone. The woman, police have found, faces multiple cases in Haryana and had first come to Delhi to prepare for competitive exams and stayed at Mukherjee Nagar. Police suspect that

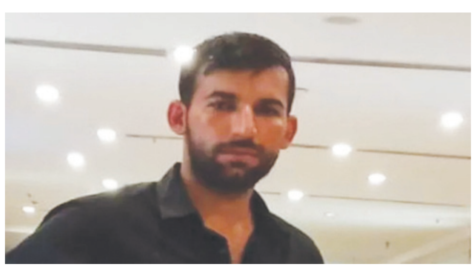

she was part of the trap set up to lure Aman to the Burger King store. CCTV footage has shown that the woman took a train from GTB Nagar Metro Station to reach Rajouri Garden and after the murder, she took the metro from Rajouri Garden to Shakurpur Metro Station, PTI has reported.

The Gangster in Portugal

Fugitive gangster Himanshu Bhau, suspected to be in Portugal now, has claimed responsibility for the murder in a social media post and a police officer told PTI that police suspect the same. Himanshu Bhau has said in the post that Aman was involved in the murder of "our brother" Shakti Dada and "this was revenge". Warning the others involved, he said their "turn will come soon". Himanshu Bhau, whose gang operates across Delhi and Haryana, is notorious for extortion, the police officer said. Bhau, an associate of jailed gangster Neeraj Bawana, fled the country in 2022.

A Jhajjar Murder

Neeraj Bawana's cousin Shakti Singh was shot dead in Haryana's Jhajjar in October 2020. A police officer told PTI that Joon is believed to have tipped off rival gangster Ashok Pradhan about Shakti Singh. Himanshu Bhau, the officer said, wanted to get Joon outside his village so that he can be bumped off and the Burger King plan was made. The social media post by Bhau also mentioned, "14 ke badle 40 goli di hain ginti kar lo" (40 bullets in return of 14, count them)". The authenticity of the social media post is being verified, police said.

NEWS BOX

Louisiana mandates displaying Ten Commandments in public school classrooms

Louisian . Louisiana has become the first state to require that the Ten Commandments be displayed in every public school classroom, the latest move from a GOP-dominated Legislature pushing a conservative agenda under a new governor.The legislation that Republican Gov. Jeff Landry signed into law on Wednesday requires a poster-sized display of the Ten Commandments in "large, easily readable font" in all public classrooms, from kindergarten to state-funded universities.Opponents questioned the law's constitutionality and vowed to challenge it in court. Proponents said the measure is not solely religious, but that it has historical significance. In the language of the law, the Ten Commandments are "foundational documents of our state and national government."The posters, which will be paired with a four-paragraph "context statement" describing how the Ten Commandments "were a prominent part of American public education for almost three centuries," must be in place in classrooms by the start of 2025.

Under the law, state funds will not be used to implement the mandate. The posters would be paid for through donations.The law also "authorises" but does not require the display of other items in K-12 public schools, including: The Mayflower Compact, which was signed by religious pilgrims aboard the Mayflower in 1620 and is often referred to as America's "First Constitution"; the Declaration of Independence; and the Northwest Ordinance, which established a government in the Northwest Territory — in the present day Midwest — and created a pathway for admitting new states to the Union.Not long after the governor signed the bill into law at Our Lady of Fatima Catholic School in Lafayette on Wednesday, civil rights groups and organisations that want to keep religion out of government promised to file a lawsuit challenging it.The law prevents students from getting an equal education and will keep children who have different beliefs from feeling safe at school, the American Civil Liberties Union, Americans United for Separation of Church and State, and the Freedom from Religion Foundation said in a joint statement Wednesday afternoon

"Even among those who may believe in some version of the Ten Commandments, the particular text that they adhere to can differ by religious denomination or tradition. The government should not be taking sides in this theological debate," the groups said.

68 Indians Among 645 Hajj Pilgrims Who Died In Mecca, Says Saudi Diplomat

Riyadh, Saudi Arabia. A diplomat in Saudi Arabia said on Wednesday that 68 Indian nationals died during the hajj pilgrimage this year marked by searing heat, bringing the overall tally to more than 600.

"We have confirmed around 68 dead... Some are because of natural causes and we had many old-age pilgrims. And some are due to the weather conditions, that's what we assume," the diplomat, who spoke on condition of anonymity, told AFP.

The new toll comes after two Arab diplomats told AFP on Tuesday that 550 deaths had been recorded during the hajj, one of the five pillars of Islam that all Muslims with the means must perform at least once.

North Korea is under heavy U.N. Security Council economic sanctions over its nuclear weapons and missile programs, while Russia is also grappling with sanctions by the United States and its Western partners over its aggression in Ukraine.

The total reported dead so far is 645, according to an AFP tally.Riyadh, Saudi Arabia: A diplomat in Saudi Arabia said on Wednesday that 68 Indian nationals died during the hajj pilgrimage this year marked by searing heat, bringing the overall tally to more than 600.

"We have confirmed around 68 dead... Some are because of natural causes and we had many old-age pilgrims. And some are due to the weather conditions, that's what we assume," the diplomat, who spoke on condition of anonymity, told AFP.The new toll coes after two Arab diplomats told AFP on Tuesday that 550 deaths had been recorded during the hajj, one of the five pillars of Islam that all Muslims with the means must perform at least once.

Russia, North Korea Pact Shows Mutual Support By Authoritarian Powers: NATO

Washington. Russia's new defensive pact with North Korea shows increasing alignment among authoritarian powers and underscores the importance of democracies presenting a united front, the head of NATO said on Wednesday.Russian President Vladimir Putin signed a deal with North Korea's Kim Jong Un that included a mutual defense pledge, a move that overhauls Moscow's policy towards Pyongyang.NATO Secretary General Jens Stoltenberg said North Korea had provided "an enormous amount of ammunition" to Russia while both China and Iran were supporting Moscow militarily in its war against Ukraine."We need to be aware that authoritarian powers are aligning more and more. They are supporting each other in a way we haven't seen before," he told a panel discussion during an official visit to Ottawa."When they are more and more aligned - authoritarian regimes like North Korea and China, Iran, Russia - then it's even more important that we are aligned as countries believing in freedom and democracy," he said.The growing closeness between Russia and other Asian nations means it is all the more important that NATO works with allies in the Asia-Pacific, he said, adding this was why leaders from Australia, Japan, New Zealand and South Korea had been invited to a NATO summit in Washington next month.Stoltenberg also said he expected Canada to meet the NATO target of spending 2% of gross domestic product on defense.

Canada's Liberal government, which has poured billions into social programs, only spends 1.37% of GDP on its military. In April it issued a plan to reach 1.76% by 2030.

Rishi Sunak's Conservative Party set for heavy election defeat, polls forecast

Polling by YouGov showed Keir Starmer's Labour was on track to win 425 parliamentary seats in Britain's 650-strong House of Commons, the most in its history. Savanta predicted 516 seats for Labour and More in Common gave it 406.

London. Three opinion polls on Wednesday predicted a record defeat for British Prime Minister Rishi Sunak's Conservatives at a July 4 election, forecasting the Labour Party would comfortably win a large majority after 14 years in opposition.

Polling by YouGov shoed Keir Starmer's Labour was on track to win 425 parliamentary seats in Britain's 650-strong House of Commons, the most in its history. Savanta predicted 516 seats for Labour and More in Common gave it 406.YouGov had the Conservatives on 108 and the Liberal Democrats on 67, while Savanta predicted the Conservatives would take 53 parliamentary seats and the Liberal Democrats 50. More in Common forecast 155 and 49 seats respectivelyChris Hopkins, Political Research Director at Savanta, said its projection put Labour on course "for a historic majority".

The three polls were so-called multilevel regression and post-stratification (MRP) surveys, an approach that uses voters' age, gender, education and other variables to predict results in every British voting district. Pollsters used the method to successfully predict the 2017 British election result.They are largely in line with previous surveys predicting a Labour victory, but show the scale of the Conservatives' defeat could be even worse than previously thought.YouGov's forecast of 108 seats for the Conservatives was around 32 lower than its previous poll two weeks earlier.

Both Savanta and YouGov predicted that the party of Winston Churchill and Margaret Thatcher could be left with the lowest number of seats in its near 200-year history contesting elections.

MISSTEPS

Sunak, who in a final throw of the dice last week pledged to cut 17 billion pounds of taxes for working people if re-elected, has failed to turn the polls around so far in a campaign littered with missteps.

His task has been made harder by the surprise mid-campaign return to frontline politics by prominent Brexit campaigner Nigel Farage, a right-wing populist, whose Reform UK party threatens to split the right-of-centre vote.Britain has a first-past-the-post electoral system, meaning Reform could pick up millions of votes across the country without winning any individual seats.YouGov predicted Reform would win five seats and Savanta none. More in Common did not give a figure for Reform.The Savanta poll, published by the Telegraph newspaper, said Sunak could even lose his own parliamentary seat in northern England, once considered a safe Conservative constituency, with the contest currently too close to call.Sunak has acknowledged that people are frustrated with him and his party after more than a decade in power, dominated at times by political turmoil and scandal.All three surveys projected several senior government ministers, including finance minister Jeremy Hunt, were on course to lose their seats.

Most opinion polls currently place Keir Starmer's Labour about 20 percentage points ahead of the governing Conservatives in the national vote share.

Other polls in recent days have also presented a grim picture for Sunak, with one pollster predicting "electoral extinction" for the Conservatives.

Sri Lankan President on India's industrial development: 'We need to join in'

Sri Lanka must connect with India to benefit from its industrial growth
President hopes to discuss follow-up with Jaishankar on Thursday
In 2022, Sri Lanka declared bankruptcy, its first sovereign default

Colombo. President Ranil Wickremesinghe on Wednesday said Sri Lanka needs to connect with neighbouring India to reap the benefits of its massive industrial development."Our neighbour India is going through a phase of massive industrial development. Tamil Nadu, Telangana and Andhra Pradesh are experiencing it. We must also join in," said Mr. Wickremesinghe in his address at the Industry 2024 event in Colombo.The president said he was hopeful of discussing with External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, who is due to arrive in Colombo on Thursday, about the follow-up on his interaction with Prime Minister Narendra Modi during his visit to India.Usage of solar and wind powers and to obtain liquid hydrogen are areas where we hope to work in collaboration with India," Wickremesinghe, also the finance minister, said, adding that Adani projects in Sri Lanka have pioneered these effortsSri Lanka in the second quarter of 2022 had declared bankruptcy announcing the island's first ever sovereign default.Negotiations with the International Monetary Fund for a bailout began almost immediately and the first tranche of the USD 2.9 billion facility was released in March 2023.he cash-strapped country has introduced a set of hard reforms to address its economic woes.Despite the outstanding issue of debt restructuring, three tranches worth USD 1 billion of the USD 2.9 billion bail-out have been materialised subject to reforms.Wickremesinghe said that by ongoing debt restructuring negotiations, the government was hoping to get time until 2042 to repay.He said it was important for Sri Lanka to convert into becoming an export-oriented economy from the current import-oriented one."Since we are an import-oriented economy, we have to find money to import. To become an export-oriented economy, we have to be competitive with our industries to become a production economy," the president said.The IMF while commending Sri Lanka's recovery efforts said the island nation's economy is far from being safe unless persisted with hard reforms needed.

Indian farm labourer dies in Italy after being left on roadside with severed arm

World An Indian national, working as a labourer at a farm in Italy, died on Wednesday after he was left on the side of a road following an accident that severed his arm.The Indian Embassy in Italy took to X on Monday to condole the "unfortunate demise" of Satnam Singh."The Embassy is aware of the very unfortunate demise of an Indian national in Latina, Italy. We are in contact with local authorities. Efforts are underway to contact the family and provide consular assistance," the post read.Satnam Singh, aged between 30 and 31, was injured on Monday while working at a farm in Latina, a rural area in the south of Rome where thousands of Indian migrant workers live. He was cutting hay when his arm was chopped off by a machine, according to Flai CGIL trade union (an Italian organisation for workers in the agriculture and food industry).Instead of helping Satnam Singh, his employers "dumped" him like a "bag of rubbish near his home", AFP reported, citing the statement by Flai CGIL that likened the situation

to a "horror film".Italian Labour Minister Marina Calderone called the incident "a true act of barbarity" in Parliament."The Indian agricultural worker who suffered a serious accident in the countryside of Latina and was abandoned in very serious conditions...has died," AFP reported, quoting Marina Calderone.She further stated that authorities were investigating the incident and expressed hope that those responsible for the act would be punished.Police said that they were called by Satnam Singh's wife and friends, and an air ambulance was sent. He was flown to a hospital in Rome, but "died around midday" (local time) on Wednesday, a police spokesperson in Latina told AFP.Satnam Singh was working at the farm without legal papers.The centre-left Democratic Party condemned the manner Satnam Singh was treated in a region known for the exploitation of workers, calling it a "defeat for civilisation".

8 dead as Israeli tanks advance deeper into Rafah, heavy shelling hit tents

Cairo Israeli tanks backed by warplanes and drones advanced deeper into the western part of the Gaza Strip city of Rafah on Wednesday, killing eight people, according to residents and Palestinian medics.Residents said the tanks moved into five neighbourhoods after midnight. Heavy shelling and gunfire hit the tents of displaced families in the Al-Mawasi area, further to the west of the coastal enclave, they said.Some eight months into the war, there has been no sign of let up in the fighting as efforts by international mediators, backed by the United States, have failed to persuade Israel and Hamas to agree to a ceasefire.Twelve Palestinians were also killed in an Israeli strike that hit a group of citizens and merchants in the south of the Gaza Strip, medical sources told Reuters on Wednesday.The people were hit as they waited for convoys of aid trucks carrying goods through the Kerem Shalom crossing in Salahuddin Road northeast of Rafah, the sources added.

Israeli forces have laid waste to much of Gaza and seized most of the Palestinian territory but have yet to achieve Israel's stated goal of wiping out Hamas and freeing Israeli hostages.Medics and Hamas media said eight Palestinians were killed in Al-Mawasi and many families fled north in panic. They did not identify the fatalities, and the Israeli military said it was looking into the report.Residents said Israeli army forces blew up several homes in western Rafah, which had sheltered over half of Gaza's 2.3 million people before last month, when Israel began its ground offensive and forced most of the population to head northwards.Some United Nations and Palestinian figures put those who remained at under 100,000 people.

"Another night of horror in Rafah. They opened fire from planes, drones and tanks on the western areas to cover for their invasion," said one Rafah resident, who asked not to be named.Bullets and shells landed in the Mawasi area near where people slept, killing and wounding many," he told Reuters via a chat app.An Israeli commander briefing military correspondents in Rafah on Tuesday named two more locations there - Shaboura and Tel Al-Sultan - where the army planned to take on Hamas fighters."The Hamas battalions there are not yet well worn down and we need to dismantle them completely. We estimate it at more or less a month, at this intensity," Colonel Liron Batito, head of the Givati Brigade, told Army Radio.The Israeli military remained in control of the border between Rafah and Egypt. Footage circulated.

Vladimir Putin arrives in Vietnam for final stop on two-nation Asia tour

Putin praised the Southeast Asian Communist country for its pragmatic stance on Ukraine
Vietnam's neutral "bamboo diplomacy" avoids condemning Russia's Ukraine attack, worrying the West
Neither Vietnam nor Russia are members of the ICC

Hanoi. Russian President Vladimir Putin arrived in Vietnam early on Thursday for talks with the country's Communist leaders on the final stop of his two-nation tour of Asia after concluding a defence pact with North Korea.Putin's aircraft touched down at Hanoi's airport, where he was met on a red carpet by Vietnamese Deputy Prime Minister Tran Hong Ha and top party diplomat Le Hoai Trung.In an opinion piece timed for his visit, Putin applauded the Southeast Asian Communist-ruled country for supporting "a pragmatic way to solve the crisis" in Ukraine.Vietnam, which officially pursues a neutral foreign policy it calls "bamboo diplomacy" in its relations with world powers, has abstained from condemning Russia's attack on Ukraine, a stance that Western countries view as too close to the Kremlin

As well as praising Vietnam for its "balanced" stance on the Ukraine war, Putin listed progress on payments, energy and trade between the countries in the article published in Vietnam's Communist Party newspaper Nhan Dan.

Although both North Korea and Russia face international isolation, Vietnam has built careful alliances with the United States and the European Union.

"President Putin's visit to North Korea and Vietnam is to demonstrate that Western attempts to isolate Russia are not working and that Russia has partners in Asia," said Carl Thayer, an expert on Vietnam security at the Australian Defence Force Academy in Canberra.Russia was hit with U.S.-led Western sanctions after it invaded

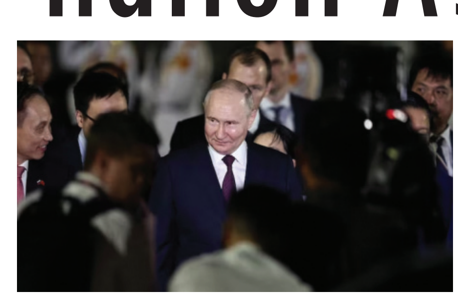

Ukraine in February 2022 in what Moscow calls a "special military operation". In March 2023, the Hague-based International Criminal Court's issued an arrest warrant for Putin over alleged war crimes in Ukraine, charges he denies.Neither Vietnam nor Russia are members of the ICC.

The Southeast Asian country will be the third nation Putin has visited, after China and North Korea, since he was sworn in for a fifth term in May.Vietnam has been gearing up for a full state welcome for Putin, his first visit since 2017 and his fifth in total.Putin is due to meet Communist Party leader Nguyen Phu Trong, state President To Lam and Prime Minster Pham Minh Chinh.The Russian leader will also attend wreath laying ceremonies, including at the Ho Chi Minh Mausoleum, housing the embalmed corpse of Vietnam's founding leader. The countries have historically close ties and shared Communist roots. Tens of thousands of cadres studied in the former Soviet Union during the Cold War, including the current head of Vietnam's Communist Party Trong."President Vladimir Putin is a person who has made many contributions to Vietnam-Russia relations. He always has good feelings and concern for Vietnam and values â€‹â€‹relationships with Vietnam's senior leaders," Ministry of Defence newspaper Quan Doi Nhan Dan said in an article."President Vladimir Putin is a person who has made many contributions to Vietnam-Russia relations. He always has good feelings and concern for Vietnam and values â€‹â€‹relationships with Vietnam's senior leaders," Ministry of Defence newspaper Quan Doi Nhan Dan said in an article.

THE PHOTON NEWS

NEWS BOX

T20 World Cup, Super 8: In the 'Big Boys Club', Afghanistan want to be giant killers

New Delhi. AT the start of the T20 World Cup 2024, did you bet on Afghanistan to make it to the Super 8s? Well, the Rashid Khan-led team has risen through the ranks to make a mark for themselves in international cricket. Their wins over better-ranked teams are no longer an upset. Afghanistan are now in the 'Big Boys Club' as they will take part in the Super 8 stage of the tournament.

The signs of this South-Asian team's rise were evident from the ODI World Cup last year. In their very next ICC event, Afghanistan ensured that they stamped their authority and how! Mind you, they were not placed in an easy group. Group C featured the co-hosts and 2-time T20 World Cup champions West Indies and New Zealand, alongside Papua New Guinea and Uganda.

AFG brilliant run in T20 World Cup 2024

Afghanistan came out all guns firing in their very first match against Uganda to register their second biggest win in the T20Is, hammering the associate team by125 runs.

However, this was just a glimpse of what followed next. This time it was New Zealand, who faced the wrath of Afghanistan's batters as well as the bowlers and lost the match by 84 runs. It was followed by an easy win by 7 wickets against Papua New Guinea. Afghanistan laid down an early marker by knocking New Zealand out of the tournament, the team that has always done well in ICC events.Amongst the Asian teams, India have been doing well as they advanced into the Super 8s without any hiccup. Pakistan and Sri Lanka were the let-downs as they were knocked out early. Nepal impressed with the fight they put up against Bangladesh and South Africa. Meanwhile, Bangladesh had a topsy-turvy ride before sneaking through to the Super 8s.While Afghanistan would be proud of how far they have come, they will face India in their first Super 8 match. They have headed to the next phase on the back of a defeat by hefty margin of 104 runs against the West Indies.

How AFG need to prepare against India?

Former India cricketer Varun Aaron wanted Afghanistan to brush aside the loss and come up with a fresh approach against India."Tell us the truth, definitely. It's going to bother them because you want to take momentum into a big game like against India. You want to have winning memories instead of losing memories because we all know how losses can snowball into a lot of doubts and problems within a team.

No point in thinking about South Africa and our luck in knockouts: Kagiso Rabada

- Rabada said the belief is there in the squad
- South Africa have found the knockout matches to be a stumbling block
- South Africa will next face England in their second Super 8 clash on June 21

New Delhi. South Africa pacer Kagiso Rabada has claimed that there is no point in thinking about their luck in the knockout matches of ICC tournaments after their win against USA on June 19 in the T20 World Cup 2024. The Proteas have found themselves on the losing side in big matches, a trend that sort of started in the 1999 ODI World Cup. Since then, they have infamously earned the 'chokers' tag in the cricketing world after losing in knockout games.

The Proteas now have a 100 percent win record in the T20 World Cup 2024 as they beat USA by 18 runs. During the press conference, Rabada was asked if the team isn't thinking about the curse of the knockouts at the moment. The pacer quickly said they're taking this game by game and keeping their belief that they can head to the final and win.There's no point in thinking about it. You just take it game by game and the belief is there. Belief is there. If you don't have the belief then you might as well go pack your bags and go home. And whatever happens after that happens but the belief is there," said Rabada.

Never write off anyone

The chase from the USA did come close in the end as Andries Gous scored 80 off 47 balls. Rabada first praised the South African batters for posting a good total of 194 in the end. Rabada also said that you never write anyone off and praised the USA side for their playing style in the tournament.

"The USA have been chasing well and that's the reason why they chose to bowl first. I must commend our batting lineup, especially Quinton. And at the end of the day, we got a respectable total on the board, or more than a respectable total on the board, which gave us an opportunity to put them under pressure with the ball."

"We got a couple of early wickets and then Andres batted extremely well and gave them a good chance and they came close in the end. You can never write any opposition off no matter who they're playing for. The USA have been playing well, they beat Pakistan. So, hats off to the way they're playing," said Rabada.

Rahmanullah Gurbaz reveals AFG's 'champions' mindset, says 'Bumrah not only target'

New Delhi. Afghanistan opener Rahmanullah Gurbaz revealed that he will not just look to take on star pacer Jasprit Bumrah during their match against India at the Kensington Oval, Barbados on June 20, Thursday. Gurbaz was eager to take on every Indian bowler during the Super 8s clash. He also revealed that the Afghanistan team is participating in the tournament not just for the sake of it but to emerge as eventual winners. Afghanistan created history by qualifying for the Super 8s as they will face India, Australia and West Indies in the Super 8 stage.The Afghanistan team reached the Super 8s on the back of a brilliant performance in the group stage. They beat Uganda, New Zealand and Papua New Guinea to advance into the next stage of the tournament. However, they suffered a hefty defeat by 104 runs in the lead-up to the Super 8s. Gurbaz has been among the leading run-scorers in the tournament. In 4 matches, he has scored 167 runs at an average of 41.75.The Afghan opener exuded confidence as he suggested that he will not hold back while going all guns blazing against the Indian openers.

"Honestly, my target is not just Bumrah. I will look to target all the bowlers, not only Bumrah, because there are 5 bowlers bowling. I have to face them all, not just Bumrah and maybe another bowler could get me out, but yes, if I get a chance to hit him, let's go for it. Could be Bumrah, Arshdeep or Siraj. Anyone, if they bowl in my area, I will hit. I will either get out or I will hit them," Gurbaz told ICC in a video.

Afghanistan's 'champion' mindset

Gurbaz also affirmed that Afghanistan are playing the tournament with the mindset of winning it, something that has been evident from their performances as well.

"We have played World Cups before, and we are here again now. But there is a huge difference and the difference is that our mindset was to just participate in the World Cup, but this time it is let's go, and we should be champions at the World Cup. There is no pressure on us to be champions. We don't have those expectations, but we are taking it just one game at a time. That is our focus and I hope we achieve our goals, and we qualify to the semi-final first and then to the final," Gurbaz added.Afghanistan have not won a single T20I against India so far but the Rashid Khan-led side will look to pose a stiff challenge to the opposition.

Roger Federer vs Roger Federer lights up London's Tower Bridge

New Delhi. London's Tower Bridge displayed a jaw-dropping advertisement for Roger Federer's latest documentary 'Twelve Final Days'. The fans were reminded to watch the documentary by displaying it on the iconic Tower Bridge. The two towers displayed a video of Federer rallying. One side showcased the young Federer hitting the ball and the other tower had the present Federer hitting it right back. As the ball was moving back and forth between the two towers, the advertisement saw a large screen roll down. The promo of Federer's documentary was displayed, making for brilliant marketing.Federer's documentary is set to be released on June 20th, Thursday on OTT platform Amazon Prime. The creativity was notched up to a high level as this video created a buzz on social media. Federer has possessed the ability to turn heads with his brilliance at the court and this time it was Amazon Prime who nailed it with their creativity this time.

'Twelve Final Days' documentary

Federer had been a dominant force in tennis for

nearly two decades before he decided to hang up his racket in the Laver Cup 2022. It was an emotional day for the tennis fans as the Swiss great played for the last time. The documentary will give insight into his final days as a professional tennis player in the lead up to the Laver Cup. The tennis community is set to face a roller-coaster of emotions as the days in the lead up to Federer's retirement are set to be unravelled.The 20-time Grand Slam champion Federer announced his decision to retire from professional tennis after a celebrated 25-year career spanning 1,500 matches. It was one of the most closely-guarded retirements in sports history.

ederer revealed that him and his wife Mirika Federer cried several times while watching the documentary during its premiere. He also suggested that watching the documentary finally got him on terms with retirement.

T20 World Cup 2024: Time to unleash magician Kuldeep Yadav in Super 8s?

New Delhi. Having passed the group stages of the T20 World Cup 2024 unscathed, India will be eager to continue their winning momentum in the Super 8s as they take on Afghanistan on Thursday, June 20 at Kensington Oval, Bridgetown, Barbados. The Men in Blue will be playing their first game in the West Indies after their last fixture against Canada got washed out in Florida.Coming after playing on the sluggish surface at the Nassau County International Cricket Stadium in New York, the Rohit Sharma-led side will probably look to alter

their team combination as per the conditions in the West Indies. The New York surface allowed India to go in with four seamers as batters found it difficult to attack them.

However, the same might not be the case on the surfaces in the Caribbean, with spinners likely to get a lot more purchase out of the pitches. Hence, the Men in Blue will look to bring in their mystery spinner Kuldeep Yadav into the playing XI.

Kuldeep Yadav ruling the roost

The 29-year-old has 59 wickets from 34 innings in his T20I career at an average of 14.10 and an economy of 6.74. Kuldeep has emerged as India's go-to man in the middle overs to stop the flow of runs by picking crucial wickets.

Despite his incredible numbers, team India will have a lot to think about before bringing him into the squad as they usually don't change their winning combination during mega events. Another headache would be about dropping one of the players from the winning combination to make way for Kuldeep.Mohammed Siraj is likely to be the one making way for the left-arm wrist spinner, having been the least effective amongst the four seamers. The right-arm seamer has picked just one wicket from three innings but has the second-best economy rate amongst all bowlers of 5.18.On the other hand, Jasprit Bumrah (5 wickets), Hardik Pandya (7) and Arshdeep Singh (7 wickets) have all been amongst the wickets for the Men in Blue. Hence, Siraj most likely seems to be the one to make way for Kuldeep.

Michael Vaughan on fighting 'awful' stress-related illness: I was embarrassed

New Delhi. Former English cricketer Michael Vaughan opened up on the mental health struggles he has been battling for the last nine months. One of England's most charismatic captains, Vaughan, talked about the times when he had to resort to medication after going into a slump due to a stress-related illness. The 49-year-old revealed the troubles he faced in his day-to-day life and was 'embarrassed' to go out of his home.Vaughan, who played 82 Tests, 86 ODIs and 2 T20Is, said that he would be grateful if his revelation could help people find their way out of mental trauma. The veteran dropped a post on his social media handle. He also thanked his doctor for prescribing him the right medicines and helping him survive through the tumultuous times.

'Hope I can help one or two people'

"Today I have spoken about the stress-related illness I have been fighting for 9 months. I don't want sympathy as I was lucky enough to see a specialist early to give me the best medication. If this helps one person, it has been worth it," Vaughan wrote on X.

"I'll be honest with you; I was never going to speak about it. But then I thought, 'Wait a

minute, there are probably quite a few people who go through similar and stay silent'. I don't want this to appear as if I'm after any sympathy, because I'm not. I just hope I can help one or two people," Vaughan told The Telegraph."There were loads of times when I wouldn't go out, because I was embarrassed. Even climbing in and out of a car was awful. I would try to walk over the road to Starbucks, and I'd be hobbling. Somebody would ask if I was OK. 'Fine,' I'd reply. 'Just a dodgy knee."

- Kane Williamson may have announced that he has decided to snub a central contract from New Zealand cricket, but expect the star batter to remain one of the main players for the nation in probably all formats of the game. Here's how Williamson can continue to play for New Zealand despite the contract snub.

'Do not ever think you can't get treated'

Vaughan, who last played international cricket back in 2008, said that mental illness isn't a 'visible injury' but can pile up over time, making life tougher for a person. He reckoned that instead of concealing mental health struggles, one should ask for help and consult psychologists and psychiatrists.

"People always talk about mental illness being the hardest to detect because it's not a visible injury; it is just something that happens inside your mind. It's similar to this illness. Over time, it just builds up,3

Key for India will be to get Rohit Sharma-Virat Kohli partnership firing: Brian Lara

- South Africa skipper Aiden Markram is wary of the threat posed by the USA side and claimed they weren't 'a small team anymore.' USA shocked the world when they defeated Pakistan in the group stages of the T20 World Cup 2024.a

New Delhi. Brian Lara feels that the Virat Kohli-Rohit Sharma partnership firing at the top would be key for India ahead of their Super 8 clash against Afghanistan on June 20, Thursday. Kohli and Rohit have opened the batting in India's all 3 matches but it has failed to click. Kohli has scored just 5 runs during this time and Rohit has failed to make an impact after his fifty in the first game against Ireland. Fans do feel it would be best to put Kohli at No.3 and get in Yashasvi Jaiswal to open along with Rohit.Speaking to Star Sports before the game, Lara felt that for putting a good partnership in the Caribbean, getting 60-70 runs in the powerplay would be a great start. The West Indies legend feels one of Rohit or Kohli can afford to drop the anchor, but it would depend on the match-ups.

"I think there is all sorts of possibilities. They are two very aggressive players. They're two world class players. But sometimes, in terms of putting together a partnership in the Caribbean, you think well, you know 60-70 runs in the powerplay would be a great start. I think one could afford to drop anchor, but it all depends, you know, on match-ups. If you feel that, as a batter, that you are better equipped than the other player to do well

against a bowler, then you do that. So I think it's a conversation that has to happen in the middle, and it doesn't necessarily mean that they have to go from both ends," said Lara.

Rohit, Kohli form psychologically important for IndiaLara continued by saying that getting Kohli and Rohit into form is psychologically important for India as both players have an impact on the team. He also commented that blasting away wouldn't be a good thing in the Caribbean."I think key for India is to get this partnership firing because they have such an effect on the team. Obviously, India has played good cricket. They have not lost a game in the tournament so far, and they can keep thinking positively."But you know, I think psychologically they would know how important both of these players coming into form quickly is for that. So, there are different ways of going about it. I don't feel blasting away in the Caribbean is one of the things you know. You just need to think about what you're doing and put a good partnership on because you know more often than not when you're playing Afghanistan than you're thinking, When are the spinners coming? Then the contest begins," said Lara.

Shama Sikander

Set The Internet On Fire In Bikini, Hot Video Goes Viral

Shama Sikander has often made headturns with her sexy photos. Today, also she treated fans with another hot video which has gone viral. Shama was seen flaunting her curves in a bikini as she enjoyed swimming in a pool.saking to her Instagram handle, Shama shared a video in which she was seen enjoying the view while swimming. "Kis kis ka pahado pe jane ka man hai ?" her caption reads. Fans also commented. Recently, Shama took to her Instagram handle and shared a series of pictures which are now setting fire online. In these latest clicks, Shama was seen posing in a black bodysuit, looking hotter with every frame. She ditched accessories, opted for smoky makeup and looked gorgeous as ever. In the caption of her post, Shama wrote, "New week, same fabulous me. Bring it on, Monday!"Meanwhile, on the work front, Shama Sikander has worked in several shows including Baal Veer, Ye Meri Life Hai and Maaya: Slave of Her Desires among others. Even though she has been away from television screens for quite some time now, she often stuns fans with her impeccable fashion sense.Previously, in an interview with News18 Showsha, Shama shared that she wants to work in web series and films only now and does not want to return to television. She revealed that she has not watched TV shows for over six years now and added, "I'm looking at only web series and feature films. I believe in doing different kinds of cinema, stories that matter. I want to do characters on screen that can add to people's lives. I feel that content can be used for great purpose for the well-being of everyone in all its art and glory. So I want to do meaty roles, and powerful performances as I am a performer and I deserve the best," she told us.

Varalaxmi Sarathkumar

Goes Wedding Shopping With Father, Fiance And His Daughter

Varalaxmi Sarathkumar, a popular face in the Tamil and Telugu film industries, has been grabbing the headlines ever since the announcement of her wedding with Nicholai Sachdev. The actress often shares a few glimpses of herself and her fiance on social media, which receives a lot of attention. As the adorable couple are gearing up for their wedding, she shared some clips and photos of her story from their day out when they went out shopping.Actress Varalaxmi Sarathkumar, her father R Sarathkumar, Nicholai Sachdev and his daughter Kasha Nia Sachdev spent a day out together. The actress shared a selfie of "family fun day" where she can be seen wearing an olive green halter-neck dress, while others wore white attire.

The next story was a clip where her father can be seen dressed in a simple white kurta and pyjama, Nicholai Sachdev in a white t-shirt and cream trousers and Kasha in a white t-shirt and a black slit skirt. From the stories, it looks like the family was out shopping and spending time with each other. She shared yet another photo with her father R Sarathkumar.Meanwhile, Varalaxmi Sarathkumar is also in the spotlight for her engagement ceremony which took place on March 1 in Mumbai. There was a section of the internet which trolled her fiance and the fact that he has a young daughter from his previous marriage. The news of her wedding has made their fans go into a frenzy. As per the gossip mill, the wedding is set to take place in Thailand for which grand arrangements are being made. Reportedly, the wedding will be held on July 2. If the reports are anything to go by, the wedding will be graced by family members and close friends. The couple has yet to announce the venue and other related details of the marriage.

Reports also claim that the pre-wedding rituals and mehendi ceremony will be held at the Taj Hotel in Chennai. The wedding reception will reportedly take place at Leela Palace in Chennai. Who's-who of the Tamil industry are expected to grace the reception ceremonyVaralaxmi Sarathkumar has starred in films like Hanu Man, Sarkar, Vikram Vedha, Vindhya Victim Verdict V3, Pakka Commercial, Mr Chandramouli, Kota Bommali PS and Naandhi.

Dalljiet Kaur Accuses Estranged Husband Nikhil Patel of Seeking 'Publicity': 'Stop Being So Desperate'

Dalljiet Kaur has accused her estranged husband Nikhil Patel of seeking "publicity" in India by using her name. Recently, the actress took to her Instagram stories and claimed that Nikhil has hired a PR agent in India. She asked him not to use her name publicly and went on to say that he should rather message her directly."Stop seeking publicity on my name for god sake! And a message on my number directly," she wrote and then added, "Stop being so desperate for fame. You have already managed to do your cultural event/PR party on March 18th and gained enough publicity.""The fact that you hired a PR is the biggest joke. You couldn't have hired someone before March 18th in India, to get published about your personal life," Dalljiet continued and further wrote, "I hope the leaders of your company who were a part of the cultural event called wedding, start worrying about your desperation to be popular by ruining life of a whole family already. And also remember what truly they were invited for, a cultural event or wedding?"Dalljiet Kaur also accused Nikhil of mocking Indian traditions by ruining their married life. She concluded by urging Kenya authorities to take a stand for her and have some "mercy" on her son, Jaydon.i.e. after 10 months of their wedding. Nikhil confirmed their separation in May when he told E-Times, "In January this year, Dalljiet decided to leave Kenya with her son Jaydon and return to India, which ultimately led to our separation. We both realized that the foundation of our blended family wasn't as strong as we had hoped, making it hard for Dalljiet to settle in Kenya. In March 2023, we held an Indian wedding ceremony in Mumbai. Though it held cultural significance, it was not legally binding. This ceremony was intended to reassure Dalljiet's family about her move to Kenya."Recently, Dalljiet moved to Nairobi City court against Nikhil and received a stay order to prevent Patel from evicting her or her son from their home in Kenya.

Actress Rinku Rajguru's Father Has These Conditions For His Prospective Son-In-Law

Actress Rinku Rajguru is best known for her debut in the Marathi film Sairat and has been impressing the audience with her acting skills since then. Besides her films, Rinku's fans are also interested to know about her personal life, including her wedding. Now, Rinku's father Mahadev Rajguru has spilled the beans on this aspect in an interview. As per Mahadev, who is a teacher by profession, he will get his daughter married to a man who fulfils certain conditions. Mahadev said that he would not immediately accept his daughter's choice and would first contemplate it. According to him, Rinku's prospective life partner should not put any restrictions on his daughter's freedom to do whatever she wants. Lastly, the boy should not have any issues, with his daughter going to many places which is her profession's demands.

Rinku Rajguru remains one of the most sought-after actresses in the film industry with hits like Jhimma 2 and Aathva Rang Premacha. Despite being a part of these amazing projects, the 23-year-old doesn't want success to get into her head. She talked about this in an interview with a media portal. She said, "I've just started.

I was 13-14 when I did Sairat and have no formal training in acting. I don't understand stardom." According to Rinku, people often tell her that she should behave in a certain way. The Marathi actress said that she is enjoying being the way she is. "On the set, I'm an actor, at home, I'm studying, spending time with family and friends", she concluded.

Rinku will next act in the Marathi project Khillar, written and directed by Makarand Mane. Lalit Prabhakar will enact the male lead in this project bankrolled by Nuclear Arrow Pictures. Khillar remains in the pre-production stage for now. Khillar deals with the contentious issue of bullock cart racing which is a tradition in Maharashtra that the Supreme Court of India recognised as legal.